चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

300वां अंक चौथी दुनिया

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

08 दिसंबर–14 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

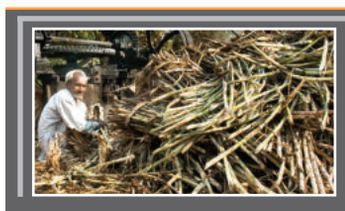

बिड़ला समूह की चीनी मिल व यूको बैंक की मिलीभगत पेज-04

आप की राह में कई रोड़े हैं पेज-05

क्या हाशिमपुरा के पीड़ितों को न्याय मिलेगा? पेज-06

साईं की महिमा पेज-12

मोदी का रथ रोकेंगे नीतीश

फोटो– *संजय कुमार*

कहते हैं, सियासत और सांप-सीढ़ी का खेल एक ही तरह का होता है. दोनों खेलों के नियम भले ही अलग- अलग हों, पर दोनों में जोखिम की आशंका और लाभ की संभावनाएं अपार होती हैं. इसे खेलने वाला खिलाड़ी अपनी एक सही चाल से फर्श से अर्श तक जा सकता है और एक ग़लत चाल उसे अर्श से लाकर फर्श पर पटक सकती है. सही चाल सीढ़ी तक ले जाती है और ग़लत चाल सांप के मुंह में. वर्ष 2005 में बिहार की सियासत में महानायक के तौर पर उभरे नीतीश कुमार का 2014 तक का सियासी सफर कई सांपों-सीढ़ियों के बीच से गुज़रते हुए आज संपर्क यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है. इससे पहले कि हम संपर्क यात्रा की कहानी शुरू करें, यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आख़िर ऐसी कौन-सी राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में पैदा हो गईं कि दो तिहाई बहुमत से सत्ता में बैठने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफ़ा देकर संपर्क यात्रा के कंटीले रास्ते पर निकलना पड़ा.

सरोज सिंह

जिस बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार महानायक के तौर पर उभरे और 2005 के बाद 2010 में भी रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर सूबे की कमान संभाली, उन्हीं नीतीश कुमार को जनता ने लोकसभा चुनाव में आख़िर क्यों ठुकरा दिया? जिस बिहार के लिए यह मान लिया गया था कि इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता है, वहां नीतीश कुमार जैसे नेता ने उम्मीद की एक नई किरण जगाकर देश-दुनिया में साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हों और काम करने का जज्बा हो, तो कुछ भी किया जा सकता है. नीतीश कुमार ने काम शुरू किया और बिहार धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसे नीतीश कुमार के विरोधी भी स्वीकार करने लगे. अब आज आख़िर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को अपना पद त्याग कर संपर्क यात्रा पर निकलना पड़ा. हम जिन राजनीतिक सवालों की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद नीतीश कुमार भी इन दिनों इन्हीं सवालों से रूबरू हैं. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद नीतीश कुमार अपने निवास पर लगभग दो महीने तक इन सवालों का जवाब ढूंढने में मशगूल रहे. इस दौरान वह उन सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिले, जिनका इन सवालों से सरोकार रहा है. पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक, नीतीश कुमार आमने-सामने हुए. ज़िलावार पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिले. पत्रकारों, डॉक्टरों एवं समाज सेवियों के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बात की और ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की.

विचार मंथन की इस लंबी प्रक्रिया में नीतीश कुमार ने सामने वालों को खुलकर अपनी बात रखने की इजाजत दी और ध्यान से उनकी बातों पर ग़ौर किया. इस दौरान नीतीश कुमार को धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि जिस नीतीश कुमार को 2010 में जनता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने दो तिहाई बहुमत के साथ गद्दी पर बैठाया था, वह नीतीश कुमार तो जनता और समर्पित कार्यकर्ताओं से बहुत दूर जाकर कुछ चुनिंदा सत्ता के सौदागरों की बाजीगरी में उलझ कर रह गया. सत्ता के सौदागरों की इसी बाजीगरी ने नीतीश कुमार को जनता और कार्यकर्ताओं की बात सुनने ही नहीं दी. नतीजा यह हुआ कि सत्ता तो चलती रही, पर सत्ता का रास्ता आम जनता और कार्यकर्ताओं के घरों तक न जाकर सत्ता के सौदागरों के महलों तक जाने लगा. जनता और कार्यकर्ताओं ने अपने महानायक को अपने से काफी दूर देखा. उनकी आवाज़ नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया. अब केवल एक ही आवाज़ नीतीश कुमार के कानों तक पहुंच रही थी और वह आवाज़ थी, सत्ता के सौदागरों की. देर से ही सही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को यह आभास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वरना जिस जनता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें महानायक बनाया, आज वहीं लोग उन्हें खलनायक क्यों मान रहे हैं.

इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने नए आवास में गहन मंथन का दौर शुरू किया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं. नीतीश कुमार ने मोटे तौर पर अपनी हार की जो समीक्षा की, उसका फलाफल उन्होंने यह निकाला कि कारण बहुत सारे थे, लेकिन तीन-चार ऐसी वजहें थीं, जिन्होंने सारा खेल ही बदल दिया. बताया जाता है कि नीतीश कुमार की समझ यह बनी कि आम जनता और समर्पित कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी ने बहुत फ़र्क़ पैदा कर दिया. वह भाषणों में भले ही कहते रहे कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं, पर कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जिसका सीधा नुक़सान यह हुआ कि ज़मीनी राजनीतिक सच्चाई के बारे में नीतीश कुमार की जानकारी कम होने लगी. चापलूस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को सीधे दिल्ली भेजकर प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाना शुरू कर दिया. उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि बिहार की जनता उन्हें कितना प्यार करती है और चाहती है कि वह यहीं रहकर सूबे को देश का नंबर एक राज्य बनाएं, क्योंकि उनके बाद उसे कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था. जनता कह रही थी कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में नीतीश, लेकिन सही सियासी फीडबैक नीतीश कुमार तक पहुंच ही नहीं रहा था. नतीजा यह हुआ कि ग़लत जानकारी के बलबूते बने रास्ते पर चलते-चलते वह नीतीश कुमार के मुंह तक चले गए और सियासी तौर पर वह काफी ऊपर से काफी नीचे उतर गए.

नीतीश कुमार को धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि जिस नीतीश कुमार को 2010 में जनता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने दो तिहाई बहुमत के साथ गद्दी पर बैठाया था, वह नीतीश कुमार तो जनता और समर्पित कार्यकर्ताओं से बहुत दूर जाकर कुछ चुनिंदा सत्ता के सौदागरों की बाजीगरी में उलझ कर रह गया. सत्ता के सौदागरों की इसी बाजीगरी ने नीतीश कुमार को जनता और कार्यकर्ताओं की बात सुनने ही नहीं दी.

नीतीश कुमार ने गहन मंथन के बाद इस सच्चाई को समझा और बिना समय बर्बाद किए उन्होंने पूरे बिहार में संपर्क यात्रा करने का फ़ैसला किया. इसमें एक समझदारी यह भी दिखाई गई कि इस यात्रा को केवल समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए ही रखा गया है. सत्ता के तथाकथित सौदागर इस यात्रा से दूर रखे गए. हर बूथ से पांच समर्पित कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, ताकि बूथ स्तर पर अपनी ताकत का आकलन किया जा सके. इन कार्यकर्ताओं से एक फार्म भी भरवाया जा रहा है, जिससे मोबाइल नंबर से लेकर उनकी सभी ज़रूरी जानकारियां पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में हमेशा उपलब्ध रहें और कार्यकर्ताओं से दो तरफ़ा संवाद किया जा सके. हार की समीक्षा के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मोदी का रथ रोकेंगे नीतीश

पृष्ठ एक का शेष

दौरान नीतीश कुमार ने यह भी जाना कि उनकी पार्टी भाजपा के आक्रामक प्रचार का जवाब नहीं दे पाई. इसके अलावा मजबूत संगठन की कमी भी महसूस की गई. विचार मंथन की लंबी प्रक्रिया के बाद नीतीश कुमार समझ गए थे कि सांप के मुंह में जाकर वह सियासी तौर पर काफी नीचे उतर गए हैं और अब उन्हें हर हाल में सीढ़ी तक पहुंचना है और इसीलिए उन्होंने चंपारण से अपनी संपर्क यात्रा का आगाज़ कर दिया.

संपर्क यात्रा के पहले ही चरण में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंचों से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच यह स्वीकार किया कि वह उनसे काफी दूर चले गए थे, उनका उनसे सीधा संवाद नहीं हो पा रहा था, जिससे ज़िलों की ज़मीनी राजनीतिक सच्चाइयां वह समझ नहीं सके. नीतीश कुमार कहते हैं, मैं हार रहा था, उसका मुझे गम नहीं. लोकतंत्र में हार–जीत चलती रहती है, लेकिन अफ़सोस सिर्फ़ इस बात का है कि मेरे कुछ साथी भी मुझे इस बारे में नहीं बता रहे थे. नीतीश कुमार संपर्क यात्रा में कार्यकर्ताओं से वादा करते हैं कि अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा और उनसे उनका संपर्क चौबीसों घंटे बना रहेगा. नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हैं, अगर आपने साथ दिया, तो मैं दोबारा बिहार की सेवा करने के लिए तैयार हूं. सभा में बैठे कार्यकर्ता हाथ उठाकर नीतीश कुमार की बातों का समर्थन करते हैं. कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने के बाद नीतीश कुमार भाजपा के दुष्प्रचार का मुद्दा उठाते हैं. नीतीश कुमार संपर्क यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों की बजाय व्यापारियों के हितों में काम कर रही है.

नीतीश कुमार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को किसानों के वोट लेने थे, तो उसने उनके हितों की बातें कहीं, लेकिन जब काम करने की बारी आई, तो वह किसानों की बजाय व्यापारियों के हितों में काम कर रही है. इन्हीं व्यापारियों ने हज़ारों करोड़ रुपये के प्रचार तंत्र में भाजपा की मदद की थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने बीते 24 अप्रैल को मधेपुरा में ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद देश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा. भाजपा का घोषणा–पत्र ऐलान करता है कि हम किसानों को ऐसा तोहफा देंगे, जो साठ सालों में किसी ने नहीं दिया. बिजली, पानी, बीज, खाद सहित खेती में होने वाला हर तरह का खर्च, सब कुछ जोड़ा जाएगा. साथ ही उस पर 50 फ़ीसद का इजाफ़ा करके जो रकम बनेगी, वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस–एमएसपी) के रूप में दी जाएगी. नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र में साफ़ है कि मोदी सरकार 50 फ़ीसद अतिरिक्त एमएसपी तय करना तो दूर, पहले से तय एमएसपी में 3.5 फ़ीसद का इजाफ़ा भी नहीं कर रही है. इसके अलावा राज्य सरकारों को धमकी भी दी गई कि अगर एमएसपी पर किसानों को बोनस दिया गया,

फोटो–*संजय कुमार*

संपर्क यात्रा से कार्यकर्ता जोश से लबालब हो चुके हैं और नीतीश कुमार के अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं. नीतीश कुमार भाजपा के हाईटेक प्रचार का जवाब भी हाईटेक तरीके से दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों के टेप सुनाकर नीतीश कुमार अपने लोगों को यह समझा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं हैं.

तो राज्य से खाद्यान्नों की अधि–प्राप्ति कम कर दी जाएगी और किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा.

नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है. भाजपाई केवल वोटों के सौदागर हैं और उन्हें हर क़ीमत पर सत्ता चाहिए. इसके बाद नीतीश कुछ अलग अंदाज़ में अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं. वह काला धन मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का भाषण कार्यकर्ताओं को सुनाते हैं. जब टेप ख़त्म होता है, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जब वोट मांगना था, तो वर्तमान प्रधानमंत्री कहते थे कि पूंजीपतियों का काला धन विदेशों में जमा है. भाजपा सरकार पाई–पाई वापस लाएगी और उसे जनता के बीच बांट देगी. अब जबकि वोट मिल गया और सरकार बन गई, तो भाषा ही बदल गई. वह मन की बात लोगों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेशों में कितना काला धन है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है. इससे साफ़ है कि या तो वह पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं. इसके बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के वादे का टेप सुनाते हैं. टेप ख़त्म होता है, तो नीतीश कुमार लोगों से पूछते हैं, सुन लिया न आपने! कह रहे थे कि बिहार के लोगों ने जितना प्यार दिया, उसे सूद समेत लौटाएंगे. विशेष पैकेज देंगे और दर्जा भी देंगे. लेकिन, उनके साथी यहां कह रहे हैं कि विशेष राज्य से कुछ नहीं होगा. अरे, कुछ नहीं होगा, तो क्यों बिहार विधान मंडल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराकर भेजा था? उस समय क्यों विरोध नहीं किया? सत्ता में थे, तो साथ दे रहे थे, अब सत्ता से बाहर हो गए, तो भाषा ही बदल गई.

अपने भाषण के अंतिम चरण में नीतीश कुमार एक बार फिर जनता से सीधा संवाद करते हैं. वह कहते हैं, भाजपाई कहते हैं कि जदयू के पास वैसा संगठन ही नहीं है, जिससे भाजपा का मुकाबला किया जा सके. हमने महसूस किया कि पार्टी का संगठन कुछ कमज़ोर है. लेकिन, जो नीतीश कुमार बिहार को मजबूत कर सकता है, वह अपनी पार्टी के संगठन को भी आपकी मदद से मजबूत कर सकता है, केवल आप लोगों का दिल से साथ चाहिए. इतना कहते ही पूरा सभा स्थल नीतीश कुमार ज़िंदाबाद के नारों से गूंज उठता है. इसके बाद नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा फिर किसी दूसरे ज़िले के लिए निकल पड़ती है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हार का सबक नीतीश कुमार ने कायदे से सीखा है और अब उसी हार को जीत में बदलने के लिए वह कायदे से अपनी सियासी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं. पहले चरण में वह कार्यकर्ताओं के साथ अपनी संवादहीनता तोड़ रहे हैं, उनसे सीधे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और पूरी जानकारी दर्ज कर रहे हैं. इसका लाभ यह हो रहा है कि जो कार्यकर्ता एक तरह से जदयू के लिए निष्क्रिय हो गए थे और भाजपा की ओर मुखातिब हो रहे थे, वे अब एक बार फिर एक नए नारे के साथ भाजपाइयों को जवाब दे रहे हैं. उनका नारा है, बिहार की जनता ने भरी हुंकार, एक बार फिर नीतीश सरकार.

संपर्क यात्रा से कार्यकर्ता जोश से लबालब हो चुके हैं और नीतीश कुमार के अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं. नीतीश कुमार भाजपा के हाईटेक प्रचार का जवाब भी हाईटेक तरीके से दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों के टेप सुनाकर नीतीश कुमार अपने लोगों को यह समझा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं हैं. देखो, उन्होंने जनता को धोखा दिया. चुनाव में जो वादा किया, अब उससे मुकर रहे हैं. नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सम्मोहन में फंसे लोगों को उनकी दो तरह की बातें सुनाकर बाहर निकाला जाए और बिहार की जो सच्चाई है, उसके आधार पर फ़ैसला करने के लिए प्रेरित किया जाए. संपर्क यात्रा की सफलता से उत्साहित नीतीश कुमार की अगली तैयारी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जनता से सीधा संवाद करने की है. यह यात्रा संभवत: आगामी 15 जनवरी से शुरू हो सकती है. नीतीश कुमार हर हाल में नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बिहार में रोकना चाहते हैं और इस समय उनका पूरा ध्यान इसी ओर है. लालू प्रसाद का साथ मिलने से उनका हौसला बढ़ा है. लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक दिया जाए. लालू प्रसाद ने हाल में ही कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं. मतलब साफ़ है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक ही तरफ़ देख रहे हैं, इसलिए एक ही रास्ते पर चलना दोनों की मजबूरी है.

नीतीश जानते हैं कि लड़ाई कठिन है, इसलिए वह सबसे पहले अपनी पार्टी और अपने संगठन को तरोताजा करने में लगे हैं. संपर्क यात्रा इसी अभियान की एक कड़ी थी. यह कारवां अब आगे जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ज़मीनी कार्यकर्ताओं और सत्ता के सौदागरों के बीच का फ़र्क़ समझ लिया है. अब वह जहां जा रहे हैं, कार्यकर्ता उन्हें हाथोंहाथ ले रहे हैं. फिर एक बार–नीतीश कुमार के नारे भी लग रहे हैं. लगता है, नीतीश कुमार एक बार फिर अपने लोगों के बीच लौट आए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 40
दिल्ली, 08 दिसंबर–14 दिसंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सिन्हा का उत्तराधिकारी कौन?

सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है. सिन्हा की जगह लेने के लिए इस दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के लिए यह सस्पेंस का समय है. सरकार ने विपक्ष द्वारा वाक्आउट के बाद भी चयन के लिए लोकपाल अधिनियम में संशोधन का एक बिल पेश किया है. यह पद हाई–प्रोफाइल है और इसके अलावा हाल के महीनों में एजेंसी की प्रतिष्ठा भी थोड़ी धूमिल हुई है. जाहिर है, सिन्हा के उत्तराधिकारी के मुख्य कार्यों में से एक काम संगठन की छवि सुधारना भी होगा. इस पद के मुख्य दावेदारों में बिहार कैडर के अधिकारी अभयानंद, अनिल सिन्हा और कृष्णा चौधरी आदि हैं (मौजूदा निदेशक रंजीत सिन्हा भी बिहार कैडर से हैं). पर्यवेक्षकों का मानना है कि एनआईई के मौजूदा महानिदेशक शरद कुमार भी इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार हैं, जबकि आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव प्रकाश मिश्रा, राजस्थान के डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अंतिम पसंद तो पीएमओ की होगी. ■

मिशन पर बाबू

ऐसा अक्सर नहीं होता है, जब एक आईएएस अधिकारी अपने सहयोगी और यहां तक कि मुख्य सचिव पर कथित तौर पर जानकारी दबाने की कोशिश करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. बंगलुरू के बाबू हलकों में यह बात चर्चा में है, जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रही है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमएन विजय कुमार ने हाल में अपने सहयोगी एवं विशेष उपायुक्त मीर अनीस अहमद पर भूमि हथियाने का और मुख्य सचिव कौशिक मुखर्जी पर यह जानकारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तक न पहुंचाने का आरोप लगाया है. विजय कुमार उस समय कर्नाटक अपीलीय ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रार थे, जब कथित तौर पर ज़मीन हड़पने की यह घटना हुई. सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण से पहले भी विजय कुमार अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने गृहमंत्री केजे जार्ज के सलाहकार के रूप में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी केमपैय्याह की नियुक्ति पर भी आपत्ति की थी. ■

बाबू का निलंबन

लोक निर्माण विभाग के सचिव टीओ सूरज का निलंबन केरल की जटिल सत्ता की राजनीति में चर्चित हो गया है. सूरज कई विवादों के घेरे में हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों के मुताबिक, सूरज राजनीतिक समर्थन की वजह से उबरते रहे हैं. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सूरज के निलंबन की सिफारिश को मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने मंजूरी दे दी है. अब यह कयास ख़त्म हो गया है कि सूरज का पॉलिटिकल कनेक्शन उन्हें राहत दिला देगा. शायद एक लंबे समय के दौरान यह पहली घटना है, जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया गया. हालांकि, लड़ाई अभी जारी रहेगी. सूरज ने साफ़ तौर पर कुछ प्रतिष्ठित नेताओं की पोल खोलने की धमकी दी है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

राजीव जहाजरानी मंत्रालय के नए सचिव

1981 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भारत सरकार के अंतर्गत जहाजरानी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया, वह वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं. राजीव 1977 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी विश्वपति त्रिवेदी का स्थान लेंगे.

सुनील और अंजुली विशेष सचिव नियुक्त

1981 बैच एवं महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी सुनील सोनी को प्रवासी मामलों के मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, वह वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर कार्यरत हैं. सुनील 1978 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रेम नारायण का स्थान लेंगे. इसी तरह 1981 बैच एवं पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी अंजुली चिब दुग्गल को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. अंजुली वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

अतुल निदेशक बने

अतुल पाटने को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि निगम का निदेशक बनाया गया है. वह इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय में कार्यरत थे.

राकेश सीबीआई जाएंगे

1984 बैच एवं गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे. अभी वह गुजरात में सूरत के पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

अमीर कदल से चुनाव लड़ रहीं हिना भट ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी के विज़न और उनकी प्रशासनिक क्षमता ने प्रभावित किया. हिना को विश्वास है कि कश्मीर को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता केवल मोदी में है. हिना को भरोसा है कि उन्हें चुनाव में जीत हासिल होगी. कुछ दिनों पहले हिना ने अपने एक बयान में इस बात का खंडन किया था कि भाजपा राज्य को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की इच्छुक है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने ऐसा किया, तो सबसे पहले वह बंदूक उठाएंगी. हिना कहती हैं कि भाजपा कभी भी 370 को हटाने की पक्षधर नहीं रही.

जम्मू–कश्मीर

भाजपा की जीत नहीं तो हार भी नहीं

मोहम्मद हारून रेशी

लोकतंत्र, मानवता और कश्मीरियत के बारे में वाजपेयी जी का नज़रिया आगे बढ़ाया जाएगा. चलो चलें मोदी के साथ, बदलें कश्मीर के हालात. यह वह संदेश है, जो इन दिनों कश्मीर में दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं को दिन में कई बार मिल रहा है. कश्मीर में लोग सुबह नींद से जागते ही जब अख़बार अपने हाथों में लेते हैं, तो उन्हें उसके पहले पन्ने पर नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर के साथ भाजपा का वह विज्ञापन पढ़ने को मिलता है, जिसमें जनता से बेहद विनम्र शब्दों में उसके (भाजपा) पक्ष में वोट डालने की अपील होती है. जम्मू–कश्मीर के हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों और लद्दाख की बौद्ध आबादी में तो मोदी के नाम का डंका पहले से ही बज रहा है, लेकिन अब मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर, जहां अतीत में भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, में भी यह राष्ट्रीय पार्टी अपनी जड़ें मज़बूत करने की कोशिश करती नज़र आ रही है. जोड़–तोड़ की राजनीति करने और मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा की कई टीमों ने इस समय घाटी व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना डेरा डाल रखा है. भाजपा की ओर से शुरू हुई सक्रियता से ऐसा लगता है कि घाटी में वह अपनी जड़ें मज़बूत करने में सफल हो चुकी है.

दूसरी ओर चुनावी राजनीति में आम लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी भी आश्चर्यजनक है. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को पहले चरण और दो दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं ने जिस उत्साह का प्रदर्शन किया, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को दंग कर दिया है. लोगों ने सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. यह नि:संदेह एक स्पष्ट परिवर्तन है, जो जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक हालात को लेकर दूरदर्शी परिणाम ला सकता है. हालांकि, अलगाववादी दलों ने जनता से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को किसी ने तवज्जो नहीं दी. भाजपा को इस वर्ष संसदीय चुनाव में राज्य के कुल 87 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से 30 में वोटों की बढ़त मिली थी. वह अब घाटी की उन्हीं सीटों पर नज़र जमाए हुए है, जहां मुहाजिर कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा वोट बैंक है. ऐसे क्षेत्रों में अमीर कदल, जब्बा कदल, सोनावार, खानयार, तराल और सुपोर आदि उल्लेखनीय हैं. भाजपा घाटी की उक्त सीटें हासिल करने की फिराक़ में है.

तराल क्षेत्र दक्षिणी कश्मीर में स्थित है. यहां मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 85 हज़ार है, जिनमें मुसलमान 70 हज़ार, सिख छह हज़ार और मुहाजिर कश्मीरी पंडित 8 हज़ार हैं. इस क्षेत्र में प्रत्येक चुनाव में अलगाववादियों के कहने पर पूर्ण बहिष्कार किया जाता है. इस वर्ष संसदीय चुनाव के अवसर पर यहां एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने अपने वोट डाले थे, लेकिन अबकी बार भाजपा यहां के मुहाजिर कश्मीरी पंडितों और सिख मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है. भाजपा के एक स्थानीय नेता ने बताया कि पार्टी तराल क्षेत्र को कश्मीरी पंडित और सिख मतदाताओं के दम पर जीतने की पूरी उम्मीद रखती है. क्योंकि, यह तय है कि यहां के मुस्लिम मतदाता मतदान का बहिष्कार करेंगे. उन्होंने बताया कि तराल में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पंजाब से प्रकाश सिंह बादल को विशेष रूप से बुलाया जा रहा है, ताकि यहां की सिख आबादी को चुनाव का बहिष्कार न करने और भाजपा को वोट देने के लिए मनाया जा सके.

भाजपा इसी तरह की कोशिशें घाटी के उन चुनाव क्षेत्रों में भी कर रही है, जहां मुहाजिर कश्मीरी पंडितों का अच्छा–खासा वोट बैंक है और मुसलमान वोट या तो बहिष्कार के चलते प्रभावहीन हो जाता है या फिर अधिक उम्मीदवारों के कारण विभाजित. एक आम राय यह है कि भाजपा ने घाटी की कई सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े कराए हैं, ताकि मुस्लिम वोट विभाजित हों और उसे (भाजपा) मुहाजिर कश्मीरी पंडितों के वोटों की मदद से जीत हासिल हो जाए. भाजपा ने घाटी में अपनी भरपूर मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए युवकों और महिलाओं पर भी भरोसा जताया है. डॉ. जनाबट, नीलम गाश एवं डॉ. दरख्शां अंदराबी को क्रमश: अमीर कदल, सोनावार और जड्डीबल जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर उतारा गया है. चौथी दुनिया ने उक्त तीनों उच्च शिक्षित महिलाओं से यह जानने की कोशिश की कि आख़िर उन्हें भाजपा में ऐसी क्या बात नज़र आई कि वे उसमें न केवल शामिल हुईं, बल्कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो गईं.

अमीर कदल से चुनाव लड़ रहीं हिना भट ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी के विज़न और उनकी प्रशासनिक क्षमता ने प्रभावित किया. हिना को विश्वास है कि कश्मीर को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता केवल मोदी में है. हिना को भरोसा है कि उन्हें चुनाव में जीत हासिल होगी. कुछ दिनों पहले हिना ने अपने एक बयान में इस बात का खंडन किया था कि भाजपा राज्य को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की इच्छुक है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने ऐसा किया, तो सबसे पहले वह बंदूक उठाएंगी. हिना कहती हैं कि भाजपा कभी भी 370 को हटाने की पक्षधर नहीं रही. वह तो केवल विकास पर ज़ोर दे रही है, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को चुना. अमीर कदल राजनीतिक महत्व के लिहाज़ से एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है. हिना का मुक़ाबला 30 से अधिक उम्मीदवारों के साथ है, जिनमें नेशनल कांफ्रेंस के वर्तमान विधायक नासिर असलम वानी और पीडीपी के अल्ताफ़ अहमद बुख़ारी भी शामिल हैं. यह वही चुनाव क्षेत्र है, जहां 1987 में मोहम्मद यूसुफ़ नामक शख्स ने मुस्लिम मुत्तेहादा महाज़ के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आम राय के अनुसार चुनाव जीत भी लिया था, लेकिन उस समय नेशनल कांफ्रेंस की धांधलियों की वजह से उसे नाकाम क़रार दिया गया था. मोहम्मद यूसुफ़ अब सैयद सलाहउद्दीन के नाम से जाने जाते हैं और सशस्त्र संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख एवं कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के गठबंधन यानी जिहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं.

डॉ. दरख्शां अंदराबी कहती हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाजपा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ करेगी. मोदी धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले शख़्स हैं. वह केवल हिंदुओं के वोट से नहीं, बल्कि देश भर के मुसलमानों के वोट से भी प्रधानमंत्री बने हैं. वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे जम्मू–कश्मीर के मुसलमानों के हितों को नुक़सान पहुंचे. दरख्शां सोनावार क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका मुक़ाबला अन्य उम्मीदवारों के अलावा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह से है. उमर अब्दुल्लाह दो सीटों यानी सोनावार और बेरूआ से चुनाव लड़ रहे हैं. यह पूछने पर कि उन्हें एक हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञ के साथ मुक़ाबला करते हुए डर तो नहीं लग रहा है, के जवाब में दरख्शां, जो उर्दू की प्रसिद्ध शायरा भी हैं, कहती हैं कि वह केवल अल्लाह से डरती हैं. उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि वह इस समय लोगों से निर्माण और विकास के जो वादे कर रही हैं, उन्हें निभाने में उनसे कोई कोताही न हो. वह कहती हैं कि कश्मीर के लोग बेबस हैं. अब तक उन्होंने कई प्रतिनिधि चुने, जिन्होंने धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया.

नीलम गाश को भी विश्वास है कि केवल गिने–चुने चुनाव क्षेत्रों में नहीं, बल्कि पूरे जम्मू–कश्मीर में विकास का एक नया दौर शुरू होगा. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई, तो विकास का एक ऐसा दौर शुरू होगा, जिससे यहां के लोगों की तक़दीर बदल जाएगी. उन्हें यही बात भाजपा में खींचकर लाई है. नीलम का दावा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में नौजवानों की एक बड़ी संख्या भाजपा में शामिल हो चुकी है. 2002 में गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे के कारण मोदी की बदनामी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विश्वास कीजिए, भाजपा के बारे में जो ग़लत धारणा यहां आम है, वह आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी. लोगों को पता चलेगा कि उनके असली दुश्मन वे राजनीतिज्ञ और राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आज तक उन पर हावी रहे.

समीक्षकों का कहना है कि भाजपा इस चुनाव में भले ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में न उभरे, लेकिन राज्य में उसके सुनहरे भविष्य को खारिज नहीं किया जा सकता. राज्य के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले समीक्षक शाह अब्बास कहते हैं कि 1996 में जम्मू–कश्मीर में कांग्रेस का वजूद न के बराबर था. हालांकि, उस समय कांग्रेस में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जैसे चेहरे थे, लेकिन कुछ सालों के बाद यानी 2002 के चुनाव में कांग्रेस एक अहम पार्टी के रूप में सामने आई और राज्य में गठबंधन सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई. 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस 17 सीटें जीतकर एक बार फिर नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी. शाह अब्बास का कहना है कि अगर इस चुनाव के नतीजे में भाजपा सत्ता में न भी आई, तो भी उसके बड़ी पार्टी बनकर उभरने की प्रबल संभावना है. उन्होंने कहा कि संभव है, भाजपा राज्य में इतनी सीटें पाने में सफल हो जाए कि उसे सरकार बनाने के लिए महज़ कुछ आज़ाद उम्मीदवारों या किसी छोटी–मोटी पार्टी की मदद लेनी पड़े. ऐसे में, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल भी अपना सहयोग देने पर राज़ी हो सकते हैं, क्योंकि अगर भाजपा के पास पर्याप्त सीटें होंगी, तो नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी खुद को बेबस महसूस करने लगेंगी.

शाह कहते हैं कि पीडीपी वैसे भी पिछले छह वर्षों से विपक्ष में है. वह और छह वर्षों तक विपक्ष में नहीं बैठ सकती. इसी तरह अपने शासनकाल में सैकड़ों निर्दोष लोगों के मारे जाने और हालिया बाढ़ के बाद पुनर्वास प्रक्रिया में अपनी नाकामी की वजह से पार्टी पहले ही साख खो चुकी है. इस साल के संसदीय चुनाव में उसे जबरदस्त शिकस्त मिली. पार्टी के सबसे कद्दावर नेता फ़ारूक़ अब्दुल्लाह भी चुनाव हार गए. ऐसे में, नेशनल कांफ्रेंस भी अगले छह वर्षों तक विपक्ष में नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी जड़ें और कमज़ोर हो जाएंगी. अगर भाजपा को 30 से अधिक सीटें मिलीं, तो कोई भी दूसरी पार्टी उसे सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हो जाएगी.

बहरहाल, जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम क्या होंगे, इस बारे में अभी कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन यह तय है कि जम्मू–कश्मीर के पिछले छह दशकों के इतिहास में पहली बार भाजपा यहां अपने जड़ें मज़बूत करने में सफल हो चुकी है. वह एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर चुकी है, जिसे अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा इसी तरह की कोशिशें घाटी के उन चुनाव क्षेत्रों में भी कर रही है, जहां मुहाजिर कश्मीरी पंडितों का अच्छा-खासा वोट बैंक है और मुसलमान वोट या तो बहिष्कार के चलते प्रभावहीन हो जाता है या फिर अधिक उम्मीदवारों के कारण विभाजित. एक आम राय यह है कि भाजपा ने घाटी की कई सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े कराए हैं, ताकि मुस्लिम वोट विभाजित हों और उसे (भाजपा) मुहाजिर कश्मीरी पंडितों के वोटों की मदद से जीत हासिल हो जाए. भाजपा ने घाटी में अपनी भरपूर मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए युवकों और महिलाओं पर भी भरोसा जताया है.

सीतापुर ऋण घोटाला

चीनी मिल प्रबंधन और बैंक की मिलीभगत उजागर

हिमांशु कुमार

उत्तर प्रदेश सीतापुर के हरगांव स्थित बिड़ला समूह की दी अवध शुगर मिल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी करके किसानों की ज़मीनें खातों पर गिरवी रख दीं और यूको बैंक सीतापुर से 125 करोड़ रुपये का फसली ऋण निकाल लिया. संबंधित किसानों को इसका पता तक नहीं चला. मिल प्रबंधन ने इस घोटाले में किसानों के उन दस्तावेजों का आपराधिक फ़ायदा उठाया, जो गन्ना के लेन-देन के लिए किसान मिल के पास जमा करते हैं. किसानों के साथ धोखाधड़ी करके अंजाम दिए गए इस घोटाले की जानकारी अधिकारियों को थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. घोटाला करने वाले चीनी मिल प्रबंधन और यूको बैंक सीतापुर के अधिकारीगण बेखौफ घूम रहे हैं. यूको बैंक के उक्त अधिकारियों की साठगांठ के बारे में आसानी से कल्पना की जा सकती है, जिन्होंने बिना किसी छानबीन और पूछताछ के तक़रीबन डेढ़ सौ किसानों की ज़मीनें गिरवी रखकर चीनी मिल को 125 करोड़ रुपये का फसली ऋण दे दिया. यह बिड़ला समूह की सीतापुर स्थित वही चीनी मिल है, जिस पर किसानों का करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है. इसने विगत कई वर्षों से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया.

देश-प्रदेश में बड़े से बड़े घोटाले आए दिन होते रहते हैं, जिनमें से कुछ समाचार-पत्रों की सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन कुछ घोटाले घुटकर रह जाते हैं. ऐसे घोटालों का खुलासा करने में सरकारी मशीनरी निहित स्वार्थों के चलते कोई रुचि नहीं दिखाती और घोटालेबाज

किसान पूछ रहे हैं कि जब घोटाला उजागर हो गया कि शुगर मिल हरगांव ने किसानों के ज़मीन खातों पर यूको बैंक से फसली ऋण के नाम पर 125 करोड़ रुपये निकाल लिए और खुलासा होने पर उन तमाम खातों पर मिल द्वारा उन्हीं किसानों के नाम पर आपाधापी में पैसा भी जमा कराया जाने लगा, तो फिर घोटालेबाजों के ख़िलाफ़ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुईं.

बच निकलते हैं. सीतापुर में वर्षों पूर्व हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच सीबीआई आज तक पूरी नहीं कर सकी. इसी तरह समाज कल्याण विभाग में हुए पेंशन घोटाले की जांच भी दबी पड़ी है. केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना के कार्यों में भी आर्थिक घोटाला किया गया, जिसकी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है. जांच में विलंब और विभागीय अधिकारियों के दांव-पेंच के चलते घोटालेबाज क़ानून के शिकंजे में फंसने से बच जाते हैं. करोड़ों रुपये का ऋण घोटाला करने वाली अवध शुगर मिल्स हरगांव और यूको बैंक सीतापुर के आपराधिक कृत्य के बारे में किसानों को भनक तक नहीं लगी कि उनकी ज़मीनें गिरवी रखकर मिल और बैंक के अधिकारियों का गिरोह गुलछर्रे उड़ा रहा है. 125 करोड़ रुपये के ऋण के दस्तावेजों पर यूको बैंक ने किन लोगों के हस्ताक्षर लिए, किन लोगों की जमानतें लीं और मिल प्रबंधन के किस शीर्ष अधिकारी से औपचारिक सहमति ली, यह सब अभी तक स्पष्ट नहीं है. किसान इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रदेश सरकार के किसी भी तंत्र पर कोई भरोसा नहीं है.

शासन-प्रशासन के अधिकारियों ने घोटाले की जानकारी होते हुए भी उस पर पर्दा डाल दिया. घोटाले का भेद एक किसान को उसकी जानकारी मिलने के बाद खुला. राम गुलाम नामक किसान ने इलाहाबाद बैंक की सिविल लाइन शाखा में फसली ऋण लेने के लिए आवेदन किया था. बैंक ने अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उक्त किसान को सूचना भेजी कि उसके नाम से यूको बैंक से पहले ही ऋण लिया जा चुका है. यह सूचना पाकर राम गुलाम के होश उड़ गए. किसी की सलाह पर उक्त किसान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसकी पूरी जानकारी मांगी और इस तरह इतने बड़े घोटाले की परतें उधड़नी शुरू हुईं. इस घोटाले को स्थानीय मीडिया ने भी तवज्जो नहीं दी. ज़िले में सार्वजनिक चर्चा है कि बैंक और चीनी मिल प्रबंधन ने पत्रकारों और प्रशासन, दोनों को मैनेज कर रखा है. चर्चा यह भी है कि प्रकरण के जानकार एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी को चीनी मिल में नौकरी दिलाने का भी लालच दिया गया था.

इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि इस प्रकरण की पूरी जानकारी ज़िला गन्ना अधिकारी, ज़िला प्रशासन और लखनऊ स्थित गन्ना आयुक्त कार्यालय तक को थी. सीतापुर के ग्राम-गडौसा, पोस्ट-मतुआ निवासी किसान राम गुलाम पुत्र रघुनंदन प्रसाद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ज़िला गन्ना अधिकारी, गन्ना आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश, यूको बैंक सीतापुर, चीनी मिल हरगांव और सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड हरगांव से जब जानकारी मांगी, तब यह खुलासा हुआ कि अवध शुगर मिल हरगांव ने यूको बैंक सीतापुर से किसानों के भूमि खातों पर फसली ऋण के नाम पर 125 करोड़ रुपये का ऋण लिया है. ज़िला गन्ना अधिकारी ऊषा पाल और यूको बैंक के प्रबंधक के पत्रों से उक्त खुलासे की पुष्टि होती है कि फसली ऋण के रूप में किसानों के 125 करोड़ रुपये यूको बैंक सीतापुर से निकाले गए हैं. इतने बड़े पैमाने पर किए गए घोटाले के ज़िम्मेदार चीनी मिल मालिक, मिल प्रबंधन एवं यूको बैंक के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब मामले की लीपापोती करने की कवायद चल रही है. इससे गन्ना किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

किसान पूछ रहे हैं कि जब घोटाला उजागर हो गया कि शुगर मिल हरगांव ने किसानों के ज़मीन खातों पर यूको बैंक से फसली ऋण के नाम पर 125 करोड़ रुपये निकाल लिए और खुलासा होने पर उन तमाम खातों पर मिल द्वारा उन्हीं किसानों के नाम पर आपाधापी में पैसा भी जमा कराया जाने लगा, तो फिर घोटालेबाजों के ख़िलाफ़ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुईं. ऋण देने के खेल में यूको बैंक के अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए सारे नियम-क़ानून ताक पर रख दिए. लिहाजा, चीनी मिल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ-साथ यूको बैंक के अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं. बैंक से जुड़े लोगों का कहना है कि ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंक संबंधित आवेदक से ऋण अदायगी हेतु गारंटी मांगता है, फिर बैंक अधिकारी उसकी विधिवत जांच करते हैं. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ऋण स्वीकृत होता है, जिसे संबंधित आवेदक के खाते में भेजा जाता है. तो फिर संबंधित किसान इस पूरे प्रकरण से अलग क्यों रहे? उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया? ऐसे कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन जवाब नदारद है. चीनी मिल से जुड़े किसानों के लिए चीनी मिल प्रबंधन संबंधित बैंक को गारंटी दे सकता है, लेकिन किसानों को ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंक प्रबंधन उसकी पूरी तरह पुष्टि करता है. उसके बाद ही ऋण की धनराशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है. इस मामले में बैंक प्रबंधन ने इस सामान्य नियम का पालन क्यों नहीं किया? उधर, ज़िला गन्ना अधिकारी ऊषा पाल ने किसान राम गुलाम के शिकायती पत्र का उल्लेख करते हुए एक पत्र (संख्या-1973/79/क्रय/शिकायत/सीतापुर, 09 सितंबर, 2013) सचिव-गन्ना समिति हरगांव को प्रेषित किया. ज़िला गन्ना अधिकारी ने अपने पत्र में चीनी मिल हरगांव द्वारा यूको बैंक स्टेशन रोड सीतापुर से गन्ना किसानों के नाम पर 125 करोड़ रुपये का फसली ऋण लेने का हवाला देते हुए उक्त प्रकरण की जांच करके तीन दिनों के अंदर संबंधित किसानों के बयान लेने और नियमानुसार चीनी मिल के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही थी. ऊषा पाल ने यूको बैंक के शाखा प्रबंधक को भी पत्र भेजकर कहा था कि अवशेष गन्ना मूल्य के आधार पर सीधे किसानों को ऋण दिए जाने की विभागीय व्यवस्था नहीं है. यदि बैंक के स्तर से संबंधित किसानों की जानकारी और सहमति के बगैर ऐसा किया जा रहा है, तो यह नियम विरुद्ध है. इस ऋण की अदायगी के लिए संबंधित किसान ज़िम्मेदार नहीं होंगे.

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड हरगांव द्वारा की गई जांच पर अपनी सफाई पेश करते हुए यूको बैंक सीतापुर के शाखा प्रबंधक ने अपने पत्र (संख्या-यूको बैंक/सीतापुर/2013-14/30 दिनांक, 24-09-2013) में पहले तो कहा कि राम गुलाम पुत्र रघुनंदन प्रसाद, ग्राम-गडौसा, पोस्ट-मतुआ, ज़िला सीतापुर के नाम पर बैंक में किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है. फिर यह भी कहा कि बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा 125 करोड़ रुपये दी अवध शुगर मिल्स लिमिटेड हरगांव के साथ समझौता अरेजमेंट के तहत स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी अदायगी की समस्त ज़िम्मेदारी कंपनी की है. चीनी मिल और यूको बैंक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ज़िला गन्ना अधिकारी ने किसान राम गुलाम को भी आधिकारिक तौर पर बताया कि चीनी मिल हरगांव द्वारा यूको बैंक सीतापुर से 125 करोड़ रुपये का ऋण तो लिया गया, लेकिन ऋण की अदायगी की समस्त ज़िम्मेदारी चीनी मिल हरगांव की है. किसानों पर उसके भुगतान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है. दी अवध शुगर मिल्स लिमिटेड के अधिशाषी उपाध्यक्ष (वित्त) ने भी अपने पत्र के ज़रिये यह माना है कि यूको बैंक से लिए गए 125 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी की समस्त ज़िम्मेदारी चीनी मिल की है. उसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी किसी भी किसान की नहीं होगी. लेकिन, विडंबना यह है कि शासन, प्रशासन, चीनी मिल प्रबंधन या यूको बैंक प्रबंधन के किसी भी अधिकारी ने इस घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में एक शब्द नहीं कहा. ■

चीनी मिलों के अभिलेखों की नियमित जांच हो

जिस प्रकार अवध चीनी मिल्स लिमिटेड हरगांव ने साजिशन 125 करोड़ रुपये किसानों के नाम पर निकाल लिए, कहीं ऐसा ही घोटाला प्रदेश की अन्य चीनी मिलें तो नहीं कर रही हैं? अब यह सवाल सामने खड़ा हो गया है. किसानों का कहना है कि शासन को आर्थिक अनुसंधान शाखा के ज़रिये चीनी मिलों के रिकॉर्ड की नियमित जांच करानी चाहिए. ऐसे घोटाले पाए जाने पर चीनी मिल समेत सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. ■

...और किसानों की खुदकुशी का रास्ता खोल दिया गया

किसान राम गुलाम द्वारा सूचना का अधिकार क़ानून का सहारा लेने से उजागर हुए घोटाले से मिल और बैंक में हड़कंप मच गया. किसान खाताधारकों की जांच कराए बगैर यूको बैंक ने इतना बड़ा फसली ऋण चीनी मिल को सीधे तौर पर कैसे थमा दिया, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे. चीनी मिल द्वारा उक्त बैंक को किसानों के नाम, पते, ऋण के एकाउंट नंबर और धनराशि की बाकायदा सूची सौंपी गई थी. उस सूची के अनुसार, किसान कन्हैया लाल मिश्रा पुत्र रेउती राम मिश्रा निवासी पिपरझला सीतापुर के एकाउंट नंबर-10170515100200 और कन्हैया लाल पुत्र सूर्यबली निवासी बैरागढ़ लखीमपुर खीरी के एकाउंट नंबर-10170515100226 पर तीन-तीन लाख रुपये का फसली ऋण दिखाया गया है. जबकि प्रभात कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी उदरहा जनपद सीतापुर के एकाउंट नंबर- 10170515107023 पर 62 हज़ार रुपये का फसली ऋण दिखाया गया है. इसी तरह सैकड़ों किसानों के भूमि खातों पर चीनी मिल ने यूको बैंक सीतापुर से मिलीभगत करके 125 करोड़ रुपये निकाल लिए. जानकार लोगों का मानना है कि अगर इस पूरे प्रकरण का खुलासा न होता, तो यूको बैंक किसानों को अपना कर्जदार मानकर उनसे ही ऋण की अदायगी कराता. ऋण अदा न करने की स्थिति में किसानों की ज़मीनें वह नीलामी पर चढ़ा देता. नतीजा यह होता कि बहुत से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते. ■

चीनी मिल और बैंक अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी

गन्ना किसानों की सहमति के बगैर चीनी मिल हरगांव द्वारा कूट रचना करके उनके भूमि खातों पर 125 करोड़ रुपये यूको बैंक से निकाल लेना आपराधिक कृत्य है. क़ानून के जानकारों का कहना है कि चीनी मिल प्रबंधन एवं यूको बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध धारा 467, 468, 471, 420 व 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए. जो चीनी मिल प्रबंधन बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की सहमति के बगैर उनके ज़मीन खातों पर फसली ऋण लेने की हिम्मत कर सकता है, तो वह साजिशन किसानों की ज़मीनों का दूसरे से सौदा भी कर सकता था. जब इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो गया कि चीनी मिल प्रबंधन ने यूको बैंक से साठगांठ करके किसानों के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान बनाए और करोड़ों रुपये का घोटाला किया, तो फिर भी ज़िला प्रशासन ने संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लोगों का कहना है कि अगर यह मामला चीनी मिल से संबंधित न होकर किसी अन्य का होता, तो अब तक उसकी संपत्ति कुर्क हो गई होती और वह जेल में बंद होता. सीतापुर के जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न पार्टियों के नेता भी इस मसले पर जानकारी के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं. ज़िले के किसान संगठनों की भी आवाज़ इस प्रकरण को लेकर काफी कमजोर है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एमएस धीर का कहना है कि वह पार्टी से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं से परेशान थे. धीर के साथ आप के राजेश राजपाल और विरोध में आवाज़ उठाने के कारण आम आदमी पार्टी से बाहर किए जा चुके अश्विनी उपाध्याय भी भाजपा में शामिल हुए. उधर पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि धीर का टिकट भी कटने वाला था, इसलिए पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.

आप की राह में कई रोड़े हैं

शशि शेखर

दिल्ली का सियासी दंगल शुरू हो चुका है. जीत के इरादे और झोली भर वादे लेकर सियासी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं. चुनावी तैयारियों के लिहाज से आम आदमी पार्टी (आप) सबसे आगे नज़र आ रही है. ऐसा लाजिमी भी है, क्योंकि इस चुनाव से अगर किसी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल तय होना है, तो वह आम आदमी पार्टी ही है. इससे पहले भी कई आलेखों के ज़रिये यह बताया जा चुका है कि आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती वह मध्य वर्ग है, जिसने पिछले साल तो इस पार्टी का भरपूर साथ दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय इससे छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ. पार्टी की मुख्य चिंता भी यही है कि कैसे इस मध्य वर्ग को अपने साथ लाया जाए. लेकिन, इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के सामने कई और चुनौतियां भी पेश आ रही हैं.

मसलन, पुराने साथियों का पार्टी छोड़ना, टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराज़गी (भले ही वह नाराज़गी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त वह भारी पड़ सकती है) और कम मात्रा में चंदा आना. अभी चंदा मिल तो रहा है, लेकिन उतना नहीं, जितने की ज़रूरत है. बहरहाल, सबसे बड़ी समस्या टिकट बंटवारे को लेकर खड़ी होने वाली है. आम आदमी पार्टी ने अपने कई वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए हैं और कई के कटने वाले हैं. टिकट कटने की आशंका से भी कई विधायकों में खलबली मची हुई है. वहीं स्थानीय स्तर पर कुछ नए चेहरों को टिकट देने की बात से भी पार्टी को कार्यकर्ताओं की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है. ताजा उदाहरण है, आम आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर द्वारा भाजपा का दामन थामना.

आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एमएस धीर का कहना है कि वह पार्टी से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं से परेशान थे. धीर के साथ आप के राजेश राजपाल और विरोध में आवाज़ उठाने के कारण आम आदमी पार्टी से बाहर किए जा चुके अश्विनी उपाध्याय भी भाजपा में शामिल हुए. उधर पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि धीर का टिकट भी कटने वाला था, इसलिए पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन इस सफाई से पार्टी को कोई फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं लगता. बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी पहले से ही बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं. बिन्नी घोषणा कर चुके हैं कि वह उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल उतरेंगे.

बात अगर टिकट बंटवारे की करें, तो पहली सूची में 12 पूर्व विधायकों के नाम हैं. दस हारे हुए उम्मीदवारों को भी पार्टी ने टिकट दिया है. दो पूर्व विधायकों, बिन्नी और धीर के भाजपा में जाने के बाद अब रोहिणी से पूर्व विधायक राजेश गर्ग, तिमारपुर से पूर्व विधायक डॉ. हरीश खन्ना एवं सीमापुरी से धर्मेंद्र कुमार समेत कुछ और विधायकों के टिकट कटने क़रीब-क़रीब तय हैं.

दूसरी तरफ़, धन की कमी से जूझ रही पार्टी ने अब डिनर पार्टी के ज़रिये फंड जुटाने की पहल शुरू कर दी है. इसके तहत अरविंद केजरीवाल के साथ किसी को डिनर करने के लिए 20 हज़ार रुपये देने होंगे. पिछला विधानसभा चुनाव महज 20 करोड़ रुपये में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार अपना बजट बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया है. अभी पार्टी को रोजाना सिर्फ़ दो से ढाई लाख रुपये अधिकतम चंदा मिल पा रहा है. जाहिर है, अगर इस रफ्तार से चंदा मिला, तो पार्टी के लिए तीस करोड़ रुपये जुटाना आसान नहीं होगा. वैसे, पार्टी पैसा इकट्ठा करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है और उसे उम्मीद है कि जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होगी, चंदा मिलने की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी. लेकिन, इस सबसे एक बात तो साफ़ होती ही है कि दिल्ली की सत्ता छोड़ने का खामियाजा पार्टी को आर्थिक रूप से भी भुगतना पड़ा है.

बात अगर टिकट बंटवारे की करें, तो पहली सूची में 12 पूर्व विधायकों के नाम हैं. दस हारे हुए उम्मीदवारों को भी पार्टी ने टिकट दिया है. दो पूर्व विधायकों, बिन्नी और धीर के भाजपा में जाने के बाद अब रोहिणी से पूर्व विधायक राजेश गर्ग, तिमारपुर से पूर्व विधायक डॉ. हरीश खन्ना एवं सीमापुरी से धर्मेंद्र कुमार समेत कुछ और विधायकों के टिकट कटने क़रीब-क़रीब तय हैं. राजेश गर्ग पहले से ही चुनाव न लड़ने की बात कर रहे थे और सरकार से इस्तीफ़ा देने के मसले पर पार्टी के साथ उनके मतभेद भी थे. इसके अलावा, पार्टी कुछ और विधायकों के टिकट काट सकती है और नए जुड़े लोगों को टिकट दे सकती है. इस मसले को लेकर भी स्थानीय स्तर पर अभी से ही नाराज़गी के स्वर उभरने लगे हैं. जाहिर है, अगर पार्टी इस मुद्दे को समय रहते नहीं सुलझा पाती है, तो चुनाव के समय उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है.

बहरहाल, अगर बात फिर से मध्य वर्ग के मतदाताओं की करें, जो यह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का एक विषय है. इस वर्ग विशेष को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है. पार्टी ने 8 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है. दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए एक अलग मेनिफेस्टो लाया गया, जिसमें रोज़गार, शिक्षा और वाई-फाई की घोषणा की गई. दिल्ली सरकार में 55 हज़ार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने और बंद पड़ीं 20 औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की बात कही गई. अरविंद केजरीवाल यह भी कहते हैं कि हम दिल्ली को देश का दूसरा पंजाब नहीं बनने देंगे, हम ड्रग्स को दिल्ली से ख़त्म करेंगे. आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, रोज़गार एवं खेलकूद से जुड़ीं योजनाएं शुरू करने, दिल्ली को वाई-फाई जोन और गांवों द्वारा ज़मीन दिए जाने पर स्टेडियम बनाने की भी बात कही है.

जाहिर है, इन वादों के सहारे पार्टी मध्य वर्ग और खासकर, युवा वर्ग को आकर्षित करना चाहती है. ग़ौरतलब है कि मध्य वर्ग के साथ-साथ दिल्ली का युवा वर्ग भी लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर चला गया था. नतीजतन, दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

मांझी का चुनावी कार्ड

सुकांत

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने भविष्य को लेकर अटकलों के बीच बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करके अपनी पीठ खुद ही खूब थपथपाई है. सरकारी घोषणाओं को उपलब्धि के तौर पर पेश करने की यह परंपरा बिहार में नौ साल पहले शुरू हुई थी. नवंबर 2005 के इन्हीं मुलायम दिनों के गुनगुने माहौल में नीतीश कुमार तत्कालीन एनडीए के मुख्यमंत्री बने थे और उपलब्धि, उम्मीद एवं घोषणाओं से भरे एक साल का पहला रिपोर्ट कार्ड उन्होंने अगले नवंबर में पेश किया था. तबसे यह रस्म चली आ रही है. हां, रिपोर्ट कार्ड की प्रस्तुति को लेकर दो बड़े राजनीतिक बदलाव आए हैं, जिनसे सूबे के भाग्य निर्धारण और विकास की राजनीति का विमर्श काफी हद तक प्रभावित हुआ है. नवंबर 2012 तक रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा नेता एवं उस सरकार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे. एनडीए से जद (यू) के अलग हो जाने के बाद नवंबर 2013 में सरकार का आठवां रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय नीतीश कुमार के दाएं-बाएं उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी थे. और, इस बार नीतीश कुमार के स्थान पर जीतन राम मांझी रहे.

दूसरी बात, बिहार में रिपोर्ट कार्ड की प्रस्तुति सत्ता और सत्तारूढ़ दल (दलों) के लिए उत्सव का अवसर होती रही है. सरकार के सभी मंत्री, सत्तारूढ़ दल अथवा दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य के विभागीय प्रधान एवं वरिष्ठ नौकरशाह इस उत्सव में शामिल होते रहे हैं, पर इस साल माहौल थोड़ा बदला हुआ था. मंत्री तो क़रीब-क़रीब सभी हाजिर हो गए (वे भी, जिनकी निष्ठा केवल सुप्रीमो नीतीश कुमार के प्रति है), पर कई विभागीय प्रधान सचिव- वरिष्ठ नौकरशाह इस बार आयोजन में देखे नहीं गए. अगर जद (यू) संगठन की बात की जाए, तो अध्यक्ष सहित दल के अधिकांश महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस उत्सव से गायब रहे. दल के नेताओं एवं नौकरशाहों के ऐसे आचरण को जद (यू) के आंतरिक विवाद और विभाजित नौकरशाही की खुली अभिव्यक्ति के तौर पर लिया जा रहा है. यह और ऐसे कई प्रसंग पूरे आयोजन को उदासीन बनाने के लिए काफी थे. फिर भी ऊपर-ऊपर सब कुछ खुशनुमा था और मुख्यमंत्री मांझी ने इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ़ से कीं और कुछ बातें अपने दिल की कीं.

मांझी ने आने वाले साल में युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं किसानों को एक बार फिर अपनी सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में रखा है. अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं और अन्य सभी सामाजिक समूहों की छात्राओं की एमए तक की शिक्षा नि:शुल्क करने की घोषणा इस सालगिरह पर की गई. मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों की मौजूदा क्षमता 28 हज़ार छात्र-छात्राओं से बढ़ाकर एक लाख करने की घोषणा की. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रोज़गार के नए अवसरों की घोषणा की गई. सरकार ने मुंगेर में एक फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है. धान की सरकारी खरीद में किसानों को घोषित खरीद मूल्य के ऊपर तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस रकम देने की भी घोषणा की गई. सरकार ने तय किया है कि एक अभियान चलाकर कृषि कार्यों के लिए किसानों को छह महीने के अंदर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. राज्य के किसानों के लिए यह दूसरी राहत भरी ख़बर है. मांझी ने पुलिस-होमगार्ड के जवानों को देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह बिहार में साल में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने यह फ़ैसला उनकी कठिन ड्यूटी के मद्देनज़र उन्हें प्रोत्साहन देने के ख्याल से लिया है. सरकार ने राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में यातायात थाना की स्थापना और दो लाख से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक शहर में यातायात डीएसपी के पद-स्थापन की घोषणा की है.

मांझी ने आने वाले साल में युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं किसानों को एक बार फिर अपनी सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में रखा है. अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं और अन्य सभी सामाजिक समूहों की छात्राओं की एमए तक की शिक्षा नि:शुल्क करने की घोषणा इस सालगिरह पर की गई. मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों की मौजूदा क्षमता 28 हज़ार छात्र-छात्राओं से बढ़ाकर एक लाख करने की घोषणा की.

मांझी सरकार की उर्दू पर नज़र गई, तो उर्दू अकादमी के सालाना अनुदान को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया. इसी तरह सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लोक व्यवहार को लेकर सरकार की फज़ीहत कम करने के लिए लोक संवेदना नामक अभियान चलाने का फ़ैसला लिया गया है, जिसके तहत जनता और उसके प्रतिनिधियों को सरकारी कार्यालयों में उचित सम्मान दिलाने की चेतना जगाई जाएगी. ये नौंवे साल की इस सरकार की नौ घोषणाएं हैं. लेकिन, इस रिपोर्ट कार्ड से आपको पता नहीं चलेगा कि बिहार में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के विभिन्न कार्यक्रम किस हाल में हैं, उनमें कहां बाधा आती है और उन्हें दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं. राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ी और घरों में लट्टू जल रहे हैं. लेकिन, यह पता नहीं चलेगा कि सूबे में ट्रांसमिशन की गड़बड़ी के कारण कितनी बिजली बेकार चली जाती है और उसमें सुधार के लिए अब तक कौन से क़दम उठाए गए हैं. आपको यह जानकारी भी नहीं मिलेगी कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में बेकार घोषित हज़ारों ट्रांसफॉर्मर कब बदले जाएंगे. इस रिपोर्ट कार्ड से आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि राज्य में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों की क्या स्थिति है और यहां जो इकाइयां लगी हैं, उनमें कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है.

नीतीश राज की कुछ उपलब्धियों को देश भर में प्रशंसा मिली. इनमें राज्य की विधि व्यवस्था में आशातीत सुधार, बदहाल सड़कों का कायाकल्प, विकास का माहौल आदि प्रमुख रहे. आज के बिहार की हालत क्या हो गई है या क्या होती जा रही है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. विधि व्यवस्था और सड़क के मोर्चे पर बिहार पुराने दिनों की ओर लौटता दिख रहा है. चीनी सहित अन्य सभी उद्योग और औद्योगिककरण सिर्फ़ चर्चा तक सीमित हैं. भूमि सुधार के सवाल को लेकर गठित बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं करता. बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों के ख़िलाफ़ राज्य में महीनों अभियान चलाने वाले राजनेता आज मंत्री हैं और मांझी के तो नहीं, लेकिन नीतीश के खास हैं. वस्तुत: सवा सौ पृष्ठों का यह रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार की सरकार से लेकर मांझी सरकार तक की घोषणाओं का एक पुलिंदा है. इसमें उपलब्धियों की खोज करने पर जितने पृष्ठ हैं, शायद उतने तथ्य भी न मिलें. ऐसे अवसरों का इस्तेमाल राजनेता अपनी राजनीति के लिए करते हैं, मांझी ने भी वही किया. अगले साल विधानसभा चुनाव है. ऐसे में वोटों का जुगाड़ भी ज़रूरी है. इसलिए अगले साल उन्होंने राज्य सरकार में लगभग एक लाख नई नौकरियां देने का वादा किया. लेकिन, सवर्णों को विदेशी बताकर विवाद में फंस गए.

मांझी ने कहा कि वह तो ग़रीब सवर्णों को बसने के लिए ज़मीन और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देना चाहते हैं. फिर उन्होंने हर चालीस परिवारों पर एक प्राथमिक विद्यालय और तीन प्राथमिक विद्यालयों पर एक मध्य विद्यालय खोलने की ज़रूरत बताई. इसके अलावा उन्होंने अब केवल प्लस-2 विद्यालय खोलने की बात कही. शिक्षा, कृषि, पुलिस और शहरों की हालत सुधारने आदि को चुनावी घोषणा बताए जाने पर उन्होंने कहा, हम माला खटखटाने तो नहीं बैठे हैं. इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे राजनीतिक बात उन्होंने यह कही कि बिहार में ग़रीबों के कल्याण के लिए नीतीश राज में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किए गए, उन्हें लागू करने के नियम-कायदे भी बने, लेकिन नौकरशाही की बेरुखी ने सब गुड़-गोबर कर दिया, कोई भी कार्यक्रम लागू नहीं हो सका. लेकिन, बीते छह महीनों में हालात बदले हैं, अब काम हो रहे हैं. चूंकि मांझी छह महीने पहले ही सत्ता पर काबिज हुए हैं, लिहाजा अब हालात बदलने लगे हैं. इसे आप क्या कहेंगे, नीतीश राज की तारीफ़ या उसका सेंसर! फ़ैसला आपको करना है. इसका मतलब आप जो भी निकालें, पर जान लीजिए कि यह कहने के कुछ ही देर बाद मांझी नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा में शामिल होने जहानाबाद पहुंच गए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> क्या हाशिमपुरा के आरोपियों को अदालत की ओर से सख्त सजा मिल पाएगी? हां में इसका जवाब देते हुए डॉ. यूसुफ़ कुरैशी ने बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट काफ़ी मज़बूत है और अदालत के सामने पूरे मामले की केस डायरी एवं गवाहों के पुख्ता बयान भी मौजूद हैं, इसलिए आरोपियों को सख्त सजा मिलने की पूरी उम्मीद है. हालांकि, यह भी सच है कि आरोपियों में से कई की मौत हो चुकी है, लेकिन जो भी बचे हैं, अगर उन्हें उनके किए की सजा मिलती है, तो हाशिमपुरा नरसंहार के पीड़ितों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, भले ही उन्हें इसके लिए 27 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा हो.

क्या हाशिमपुरा के पीड़ितों को न्याय मिलेगा?

डॉ. क़मर तबरेज़

मेरठ (उत्तर प्रदेश) के 27 वर्ष पुराने हाशिमपुरा मामले में अदालत का फ़ैसला किसी भी समय आ सकता है. चौथी दुनिया भारत का पहला अख़बार है, जिसने सबसे पहले इस घटना की ख़बर देश और दुनिया को दी थी. इसमें पीएसी के जवानों ने हाशिपुरा के 42 मुस्लिम युवाओं को गोली मारकर उनकी लाशें गंग नहर में बहा दी थीं. चौथी दुनिया में प्रकाशित उस ख़बर का शीर्षक था–लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें नहर में बहा दीं. इस ख़बर ने उस समय भी धूम मचा दी थी और आज भी लोग इसे याद करते हैं. उनमें से तीन नौजवान किसी तरह ज़िंदा बच गए थे, जिन्होंने बाद में पीएसी द्वारा की गई बर्बरता और अत्याचार की कहानी पूरी दुनिया को बताई. भारत की शायद यह पहली घटना है, जिसमें अदालत को किसी नतीजे तक पहुंचने में अब तक 27 वर्षों का समय लग चुका है. अदालत का फ़ैसला क्या होगा, यह अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिन लोगों की नज़र इस मामले को लेकर अदालत की कार्यवाही पर है, वे आशांवित ज़रूर नज़र आते हैं.

उनमें से एक डॉ. मोहम्मद यूसुफ़ कुरैशी भी हैं, जो मेरठ के मशहूर नेता एवं व्यापारी हाजी याकूब कुरैशी के बड़े भाई और पेशे से वकील हैं. डॉ. कुरैशी का मानना है कि विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने हाशिमपुरा मामले को लेकर नारे तो खूब लगाए, सड़कों पर विरोध में रैलियां भी निकालीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पीड़ितों की मदद करने या उन्हें न्याय दिलाने में कभी गंभीरता नहीं दिखाई. कुरैशी कहते हैं कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को सरकार की ओर से नियमानुसार मुआवज़े दिए गए, यहां तक कि नवनिर्वाचित मोदी सरकार भी उन्हें और मुआवज़ा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरठ दंगा पीड़ितों को सरकारी मुआवज़ा तक नहीं दिया गया. उस दंगे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके रिश्तेदारों की एक या दो नहीं, बल्कि तीसरी पीढ़ी इस समय मौजूद है, जिसे अब भी न्याय का इंतज़ार है और जो आर्थिक तंगी के कारण कठिनाइयों भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है.

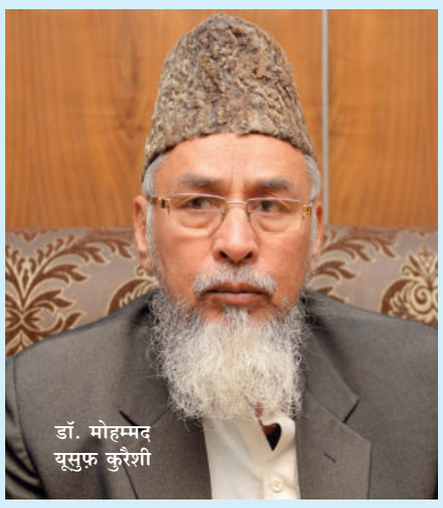
डॉ. मोहम्मद यूसुफ़ कुरैशी

इसे विडंबना ही कहेंगे कि सीबीसीआईडी ने 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के एक साल बाद तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उन 37 आरोपियों में से केवल 19 के ख़िलाफ़ ही मुक़दमा चलाने की स्वीकृति दी.

सवाल यह उठता है कि आख़िर इस मामले की सुनवाई में अदालत को 27 वर्षों का समय क्यों लगा? इस सवाल के जवाब में डॉ. यूसुफ़ कुरैशी कहते हैं कि सरकारों ने हाशिमपुरा के पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अदालत में इस मामले की सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई.

उल्लेखनीय है कि 1987 में जिस समय हाशिमपुरा में पीएसी के जवानों द्वारा बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया था, उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसने तुरंत तो नहीं, बल्कि एक वर्ष बाद यानी 1988 में हाशिमपुरा नरसंहार की सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया. उसके अगले वर्ष यानी 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. कांग्रेस ने अगर हाशिमपुरा नरसंहार की जांच ढंग से कराने की कोशिश नहीं की थी, तो मुलायम सिंह इस काम को ठीक ढंग से करा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

यूसुफ़ कुरैशी तो यहां तक कहते हैं कि 2001 में हाशिमपुरा नरसंहार के पीड़ितों की ओर से जब मौलाना मोहम्मद यामीन अंसारी (इनकी मौत हो चुकी है और अब इनके बेटे जुनैद अंसारी अदालत में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके गाज़ियाबाद से इस मामले को दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट काउंसिल का गठन करके इसकी मंजूरी न देने की वजह से यह मामला गाज़ियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित न होकर बीच में लटका रहा. उल्लेखनीय है कि 2001 से 2003 के बीच उत्तर प्रदेश में बसपा–भाजपा की गठबंधन सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थीं. भाजपा द्वारा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की वजह से सितंबर 2003 में मुलायम सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके बावजूद उन्होंने हाशिमपुरा मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली. उत्तर प्रदेश सरकार का यह रवैया देखते हुए हाजी याकूब कुरैशी ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लगभग एक दर्जन पत्र लिखे. उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हाशिमपुरा मामले की सुनवाई गाज़ियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए अपनी मंजूरी दी. इस तरह दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत में हाशिमपुरा मामले की सुनवाई शुरू हुई, जहां इस समय यह मामला अंतिम चरण में है.

इसे विडंबना ही कहेंगे कि सीबीसीआईडी ने 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के एक साल बाद तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उन 37 आरोपियों में से केवल 19 के ख़िलाफ़ ही मुक़दमा चलाने की स्वीकृति दी. विडंबना तो यह भी है कि 1994 से 2000 के बीच आरोपियों को अदालत के सामने हाजिर होने के लिए 23 बार वारंट जारी किए गए, लेकिन एक भी आरोपी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ. इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस–प्रशासन ने हाशिमपुरा मामले की कितनी अनदेखी की है.

याकूब कुरैशी यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाशिमपुरा मामले के लिए शुरू में जो वकील दिया गया था, वह दीवानी मामलों (सिविल) से संबंधित था, फौजदारी (क्रिमिनल) से नहीं, जिसकी वजह से यह मुकदमा और पेचीदा हो गया. पीड़ितों की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद उक्त वकील को इस मुकदमे से हटना पड़ा. बकौल याकूब कुरैशी, खुशकिस्मती से उसी समय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के रूप में हामिद अंसारी (वर्तमान उप–राष्ट्रपति) ने पीड़ितों को एक वकील दिया, जिसके बाद दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत में हाशिमपुरा मामले की बाक़ायदा सुनवाई शुरू हो सकी.

क्या हाशिमपुरा के आरोपियों को अदालत की ओर से सख्त सजा मिल पाएगी? हां में इसका जवाब देते हुए डॉ. यूसुफ़ कुरैशी ने बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट काफ़ी मज़बूत है और अदालत के सामने पूरे मामले की केस डायरी एवं गवाहों के पुख्ता बयान भी मौजूद हैं, इसलिए आरोपियों को सख्त सजा मिलने की पूरी उम्मीद है. हालांकि, यह भी सच है कि आरोपियों में से कई की मौत हो चुकी है, लेकिन जो भी बचे हैं, अगर उन्हें उनके किए की सजा मिलती है, तो हाशिमपुरा नरसंहार के पीड़ितों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, भले ही उन्हें इसके लिए 27 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा हो. ■

(डॉ. यूसुफ़ कुरैशी से बातचीत पर आधारित)

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

दिखने लगा है मोदी इफेक्ट

मंगलानंद

झारखंड की राजनीति में मोदी इफेक्ट अब सिर चढ़कर बोलने लगा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति रंग ला रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सिर्फ़ दो चुनावी रैलियां की हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे झारखंड की राजनीति में दृष्टिगोचर होने लगा है. डाल्टनगंज एवं चंदवा में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश में केवल विकासवाद की राजनीति चलेगी. जनता ने जातिवाद, प्रांतवाद एवं परिवारवाद का कहर देख लिया, अपने–पराए का खेल देख लिया, इससे किसी का भला नहीं हुआ. झारखंड को भी जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक राज्य का विकास नहीं होगा. मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता. लोकतंत्र में ताकत के जोर पर दुनिया को नहीं चलाया जा सकता. यहां जनता छप्पर फाड़ कर देती है, तो वापस भी ले लेती है.

उन्होंने कहा कि झारखंड की भूमि अमीर है, लेकिन लोग ग़रीब हैं. जनता बेरोज़गारी और ग़रीबी से जूझ रही है, पर झारखंड को लूटने वालों को शर्म नहीं आती. उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर लोगों को इस बात से मतलब तक नहीं रहा कि भवनाथपुर पावर प्लांट शिलान्यास के बाद भी शुरू क्यों नहीं हुआ, जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद क्यों है? मोदी ने कहा कि गांवों में बिजली–पानी हो, माताओं–बहनों को सम्मान मिले, इसलिए झारखंड को गले लगाने आया हूं. मोदी ने डाल्टनगंज में तिलहन और केले की पैदावार पर जोर देते हुए कहा कि भूमि सीमित है, इसमें ही पैदावार बढ़ानी है. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों से किसानों की समृद्धि के बारे में बात की गई है. चंदवा में आयोजित जनसभा में मोदी ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए. इसी से वे खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की.

मोदी ने कहा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, जहां भी आदिवासी हैं, उन्होंने भाजपा को प्राथमिकता दी है. आप भी झारखंड का भाग्य बदलने का मौक़ा दीजिए. आपके कंधे पर जो बंदूक है, उससे सिर्फ़ धरती लाल हो सकती है, सिर्फ़ किसी मां के बेटे की बलि चढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी के पेट की भूख नहीं मिटाई जा सकती. इसलिए आप बंदूक छोड़कर हल उठा लें, उससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का पेट भरेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन राम पर साजिश के तहत हमला किया गया. इस चुनाव में जनता को बुलेट का जवाब बैलेट से देना होगा. यहां जो सरकार बैठी है, उसने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के मंत्रियों को झारखंड में घुसने नहीं देंगे. क्या इससे झारखंड का भला होगा? जब वह (मोदी) गुजरात में सरकार चलाते थे, केंद्र से सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा.

चंदवा में आयोजित जनसभा में मोदी ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए. इसी से वे खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की. मोदी ने कहा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, जहां भी आदिवासी हैं, उन्होंने भाजपा को प्राथमिकता दी है. आप भी झारखंड का भाग्य बदलने का मौक़ा दीजिए.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को डर है कि अगर मोदी का कोई मंत्री या अफसर यहां आएगा, तो उसकी (राज्य सरकार) पोल खुल जाएगी. इसलिए अब जनता को फ़ैसला करना होगा कि वह ऐसे लोगों को झारखंड विधानसभा में घुसने नहीं देगी. पूर्व उप–मुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मात्र एक निर्णय से झारखंड का राजस्व 10 हज़ार करोड़ रुपये बढ़ने जा रहा है. अभी राज्य का योजना बजट 18 हज़ार करोड़ रुपये है. एकमुश्त 10 हज़ार करोड़ रुपये राजस्व बढ़ जाने से विकास के लिए पैसों की कमी नहीं रहेगी. महतो ने कहा कि अब तक केवल 27 प्रतिशत कोयला रखने वाले झारखंड को पूरा हिस्सा मिलेगा. इससे यहां की जनता का विकास होगा. जानकारों का मानना है कि इस बार झारखंड में भाजपा अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> वित्त मंत्री का कहना है कि काला धन लाने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इस मामले पर सरकार ने पिछले छह महीनों में जितना कुछ किया है, उतना अब तक कभी नहीं हुआ. जेटली के मुताबिक, विपक्षी पार्टियां बार-बार यह याद दिलाकर उकसाने की कोशिश करती हैं कि हमने सौ दिनों में काला धन वापस लाने का वादा किया है, मगर सरकार हड़बड़ी में कोई क़दम नहीं उठाएगी, इस काम में समय लगेगा.

समय से ज़्यादा नीति और नीयत महत्वपूर्ण है

अरुण तिवारी

भारतीय राजनीति का नया मुहावरा है, काला धन. यह धन भले ही काला हो, लेकिन इससे जुड़े सपने सतरंगी हैं. सबके लिए. जनता इस उम्मीद में है कि काला धन आने के साथ ही चारों ओर खुशहाली आएगी. सत्ता पक्ष के पास काला धन के रूप में एक लॉलीपाप है, जिसे दिखाकर वोट मिल सकता है और विपक्ष इस बात से उत्साहित है कि मुद्दों के अभाव के इस दौर में उसके पास यही एक हथियार है, जिसके सहारे वह भाजपा के मजबूत किले को भेद सकता है. बहरहाल, काला धन की इस सतरंगी कहानी में कई रंग हैं. एक रंग चुनाव से पहले दिखा, दूसरा रंग चुनाव के दौरान और एक तीसरा रंग अब संसद के भीतर दिख रहा है. इसमें सबसे दिलचस्प रंग संसद में होने वाली बहस से निकल कर सामने आ रहा है. मसलन, इस मुद्दे पर बहस के दौरान जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी बात रख रहे थे, तो शरद यादव का कहना था कि आपके जवाब से तो यही लगता है कि 100 सालों में भी काला धन वापस नहीं आ पाएगा. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता विरोध के लिए सदन में काला छाता लेकर और काली शॉल ओढ़ कर पहुंच गए. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा ने काला धन रखने वालों का नाम उजागर न किए जाने को लेकर वॉकआउट भी किया. लेकिन, वित्त मंत्री का कहना है कि जब तक आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर नहीं होगी, तब तक उनके नाम सामने नहीं लाए जाएंगे. जेटली के मुताबिक, विदेशी बैंकों में क़रीब ढाई सौ लोगों के एकाउंट हैं और अगले कुछ हफ्तों में यह मामला दर्ज किया जाएगा और जब मामला शुरू होगा, तो नाम भी सामने आ जाएंगे.

सरकार को देश में मौजूद काले धन का पता लगाना चाहिए. इसके लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए. हम इस मुद्दे पर आज बहस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान वादों की झड़ी लगाई गई थी. डबल टेक्सेशन से जुड़े समझौते पर फिर से विचार करना चाहिए.
-सीताराम येचुरी (सीपीएम), राज्यसभा.

भाजपा के वादे खोखले हैं. आज़ादी के बाद सभी पार्टियों का शासन रहा है. सभी पार्टियां विदेशों में काला धन जमा होने के लिए ज़िम्मेदार हैं. यूपीए सरकार ने काला धन पर कोई ठोस क़दम नहीं उठाया. कांग्रेस की तरह भाजपा भी इसे लेकर गंभीर नहीं है. सिर्फ़ एसआईटी का गठन कर देना पर्याप्त नहीं है.
-मायावती (बसपा), राज्यसभा.

बेकारी और बेरोज़गारी ख़त्म करो. यह (काला धन) मृग-मरीचिका है. यह न तो आप (कांग्रेस) से आया और न आप (एनडीए) ला पाओगे.
-शरद यादव (जदयू), राज्यसभा.

एनडीए सरकार ने काला धन के मुद्दे पर बहुत तेजी से क़दम उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बांग्लादेशी आतंकवादियों को पैसे दिए. टीएमसी के लोग काले छातों के साथ संसद में आए, लेकिन उनकी जेबें काले धन से भरी हुई हैं. यह कैसे हुआ कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पेंटिंग पहली बार में ही इतने दाम में बिकी और उसे सारदा घोटाले में शामिल शख्स ने खरीदा.
-अनुराग ठाकुर (भाजपा), लोकसभा.

देश को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए. मोदी जी को नाम ऑनलाइन करने दीजिए. उन्हें 15-20 लाख रुपये हर खाते में डालने दीजिए. अब मोदी जी एनआरआई पीएम कहे जाते हैं. उन्हें संसद से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठा वादा किया था. आपको याद रखना चाहिए कि सारदा के मालिक को सीबीआई ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने कश्मीर सीमा से गिरफ्तार कराया था (अनुराग ठाकुर को जवाब).
-सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), लोकसभा.

मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया के कितने मुल्कों से प्रधानमंत्री काला धन वापस लाने की बात कर रहे हैं. इस तरह की धारणा बन गई है कि विदेशों में जमा पैसा काला धन है. इस बारे में फ़र्क़ किया जाना चाहिए कि क्या काला धन है और क्या क़ानूनी रूप से जमा रकम है.
-आनंद शर्मा (कांग्रेस), राज्यसभा.

क्या एनडीए या यूपीए सरकार ने विदेशों में पड़े काले धन का पता लगाया है? 15 लाख नहीं, सरकार हर शख्स के खाते में 15 हज़ार भी डलवा दे, तो लोग खुश हो जाएंगे. प्रधानमंत्री की जन-धन योजना से कर्ज बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी.
-राम गोपाल यादव (सपा), राज्यसभा.

दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, एक बार ये जो चोर-लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा हैं ना, उतने भी हम ले आए ना, हिंदुस्तान के एक-एक ग़रीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपये यूं ही मिल जाएंगे. इतने रुपये हैं. मोदी ने यह भी कहा था, सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी से हो कि कैसे लाएं? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौक़ा मिलेगा, एक-एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के ग़रीबों के लिए काम में लाई जाएगी. लोकसभा में हुई इस बहस पर कांग्रेस के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे तो सीधे-सीधे सरकार से पूछा, मेरे 15 लाख रुपये कहां हैं, जो आपने मेरे खाते में डालने का वादा किया था? वह रकम मेरे खाते में नहीं आई और 150 दिन बीत चुके हैं. आपने अपना वादा नहीं निभाया. मैं आपको वह वादा याद दिलाना चाहता हूं. आपने यह भी कहा था कि देश के वेतनभोगी समाज की देशभक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए. हम उन्हें पैसे देंगे, लेकिन आपने इसी साल 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में यू-टर्न ले लिया. इस मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव भी लाई थी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में काला धन पर बहस का समय तय किया गया.

वित्त मंत्री का कहना है कि काला धन लाने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इस मामले पर सरकार ने पिछले छह महीनों में जितना कुछ किया है, उतना अब तक कभी नहीं हुआ. जेटली के मुताबिक, विपक्षी पार्टियां बार-बार यह याद दिलाकर उकसाने की कोशिश करती हैं कि हमने सौ दिनों में काला धन वापस लाने का वादा किया है, मगर सरकार हड़बड़ी में कोई क़दम नहीं उठाएगी, इस काम में समय लगेगा. चुनाव के दौरान किए गए वादों के बारे में जेटली का कहना था कि

कई बार ईमानदारी के साथ कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी व्यवहारिकता को देखने के बाद कुछ और सच्चाई सामने आती है. पर विपक्ष वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा. एक-एक करके अधिकांश विपक्षी दल इस दौरान सदन से बाहर निकल गए.

दरअसल, दिक्कत यह है कि काला धन की रकम कितनी है, इसके बारे में सरकार को भी ठीकठाक कुछ पता नहीं है. काला धन की परिभाषा को लेकर भी कुछ साफ़ नहीं है. सरकार से अधिक सुप्रीम कोर्ट काला धन को लेकर सक्रिय है और वह एसआईटी के काम पर नज़र रख रहा है. एसआईटी विदेशी बैंकों के उन भारतीय खाताधारकों की सूची की जांच कर रही है, जो भारत को कांग्रेस के शासन में ही मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तीन नाम और सार्वजनिक किए गए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी.■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी का तोड़ छात्र संघ में तलाशते राजनीतिक दल

नवीन चौहान

देश भर की नज़रें इन दिनों छात्र राजनीति की ओर हैं. हर जगह विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों को बहाल करने की मांग अचानक तेज हो गई है. लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों पर रोक लग गई थी. छात्र लगातार छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग करते रहे, लेकिन सरकारों पर उसका कोई असर नहीं हुआ. लेकिन, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का सीधा असर छात्र राजनीति में दिखाई देने लगा. क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक बार फिर से अपनी जड़ें छात्र राजनीति में तलाशने लगे हैं.

आज़ादी के बाद देश में जो भी राजनीतिक बदलाव हुए, उनमें छात्र राजनीति का अहम योगदान था. साठ और सत्तर के दशक में बीजू पटनायक, ज्योति बसु, चौधरी चरण सिंह, महामाया प्रसाद सिन्हा जैसे कई लोगों ने छात्र राजनीति के बल पर ही देश के राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाई. महामाया प्रसाद सिन्हा छात्रों को अपने जिगर का टुकड़ा बताकर बिहार के लौह पुरुष कहलाने केबी सहाय को हराकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए. इसके बाद आपातकाल के दौरान जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव जैसे नेताओं का उदय हुआ. लेकिन, आज परिस्थितियां बदल गई हैं. देश के युवाओं को मोदी के पाले में खड़ा देखकर इन पूर्व छात्रनेताओं को छटपटाहट हो रही है. सभी अपना राजनीतिक भविष्य एक बार फिर से छात्र राजनीति में तलाश रहे हैं.

लोकसभा चुनाव के बाद देश में खासकर, उत्तर प्रदेश में छात्रों की पूछ-परख बढ़ गई है. मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी थी. यह रोक अखिलेश के दौर में भी जारी है, जो युवाओं के समर्थन की बदौलत साल 2012 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे. अखिलेश ने चुनाव के दौरान युवाओं से जो वादे किए थे, उन्हें वह पूरा नहीं कर सके और युवाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतरे. वादों के अनुरूप उत्तर प्रदेश में न तो नए उद्योग लगे, न युवाओं को रोज़गार मिल सका. बेरोज़गारी भत्ता देने में भी कई तरह की नुक्ताचीनी की गई. इसलिए उन्हीं युवाओं को 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी रास आ गए. युवाओं ने धर्म, जाति एवं संप्रदाय को परे रखकर विकास और रोज़गार के नाम पर मोदी के पक्ष में वोट दिया और प्रदेश में भाजपा को 73 सीटों पर विजय दिलाई. समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई और बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई.

ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ चुनावों को लेकर तमाम तरह के आंदोलनों के चलते पिछले काफी समय से अराजकता फैली हुई है. हाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच हुआ संघर्ष भी इसी की एक कड़ी है. बनारस में छात्र छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र परिषद चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे. वे छात्र परिषद की बजाय

छात्रसंघ का चुनाव चाहते थे. बनारस प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ का चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीते 24 नवंबर को सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाकर लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव की तैयारियों का ब्यौरा तलब किया. कुलपतियों से कहा गया है कि वे लिंगदोह समिति के अनुसार वर्गीकरण कर लें और उसके हिसाब से दूसरे राज्यों में अपनाए गए वर्गीकरण और सिद्धांतों का अध्ययन करके उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू करें.

छात्र राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी कहा जाता है. इन नर्सरियों से गुजर कर छात्र राज्य और देश की राजनीति की मुख्य धारा में आ जाते हैं. चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को सक्रिय कार्यकर्ता छात्र राजनीति से ही मिलते हैं. देश के कई बड़े नेता छात्र राजनीति के रास्ते ही राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रचलन में आने के बाद युवाओं की राजनीतिक विषयों में दिलचस्पी बढ़ी है. खासकर, विश्वद्यालयों में पढ़ने वाले युवा अब खुलकर राजनीतिक विषयों पर राय रख रहे हैं. इस वजह से हर जगह छात्रसंघों को बहाल करने के लिए मांगें उठ रही हैं. हाल में संपन्न हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाया. अध्यक्ष पद पर समाजवादी छात्र युवजन सभा के भूपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की. यहां भी व्हाट्स ऐप और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का चुनाव प्रचार में जोर-शोर से इस्तेमाल हुआ.

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र एवं नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष भावेश पांडेय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति पर अचानक ध्यान केंद्रित होने की वजह 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं. इसलिए प्रदेश में जिन जगहों पर छात्रसंघ चुनाव हो रहे हैं, वहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े पदाधिकारी सीधे तौर पर नज़र रख रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं. उन्हें मालूम है कि आज इनका समर्थन करने पर उन्हें 2017 के चुनाव के लिए मेन-पॉवर मिल जाएगी, जो अपना भविष्य राजनीति में देखते हुए जी-जान से पार्टी के प्रचार में लग जाएगी. पार्टियों का रुख विश्वविद्यालयों में रचनात्मकता लाना कतई नहीं है. लोकसभा चुनाव के बाद सपा पदाधिकारियों के क़रीबी लोग एवं कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा की ओर रुख करने लगे थे. इसलिए सपा और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग तेजी से उठने लगी.

समाजवादी छात्र युवजन सभा इलाहाबाद के अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने कहा, साल 2012 में सपा को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने वाला युवा भटक गया था, लेकिन अब उसे अपनी भूल समझ में आ रही है. प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलजों में चुनाव होने जा रहे हैं. इससे छात्रों में एक नई ऊर्जा आ गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक जहां-जहां चुनाव हुए हैं, उनमें से अधिकांश जगहों पर समाजवादी छात्र युवजन सभा के उम्मीदवार जीते हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत हासिल करने वाले छात्रनेताओं ने जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाक़ात की, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव में जीत हासिल की है, वे छात्रों का भविष्य बन गए हैं. उनका भविष्य भी समाजवादी पार्टी के लिए समर्पण से काम करने पर उज्जवल होगा. यदि आप छात्रों के हित में काम करेंगे, तो उनका और युवाओं का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ेगा.

झारखंड विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी समन्वय समिति के लिए काम कर रहे झरिया स्थित आरएसपी कॉलेज के पूर्व छात्रनेता रूदल पासवान ने बताया कि दूसरी पार्टियों की युवाओं के बीच पकड़ कमजोर हुई है. इसका सीधा कारण छात्रसंघों का चुनाव न होना है. कॉलेजों में पढ़ने वाले 85 प्रतिशत युवा 24 घंटे सूचनाओं से जुड़े रहते हैं. अब आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते. स्वाभाविक है कि उनका रुझान उनके हितों की बात करने वाले की ओर होगा. फिलहाल युवा वर्ग मोदी को चाह रहा है, इसलिए दूसरे राजनीतिक दल छात्रसंघों को बहाल करके युवाओं के बीच फिर से पकड़ बनाना चाहते हैं.

फिलहाल, जो राजनीतिक पार्टियां छात्रसंघों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयासरत दिख रही हैं, उनकी साख पहले ही ख़त्म हो चुकी है. वे अब भी सत्तर के दशक की राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन देश का युवा उससे कहीं आगे निकल गया है. उसके तौर-तरीकों में खासा बदलाव आ गया है. अब उसे बरगला कर अपने पाले में लाना संभव नहीं है. इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को युवाओं के स्तर पर आना पड़ेगा. इस मामले में भाजपा दूसरी पार्टियों की तुलना में कहीं आगे निकल चुकी है. फिलहाल उसे पकड़ पाना दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है.■

navinonline2003@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आर्थिक मोर्चे पर साहसिक निर्णय लेने की ज़रूरत

वित्त मंत्री बहुत ही समझदार हैं. वह सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस सबको लागू करने में उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां होंगी. बावजूद इसके, अगले बजट से पहले उनका मन स्पष्ट होना चाहिए और कुछ साहसिक निर्णय लेने चाहिए. मैं 1985 को याद करता हूं, जब राजीव गांधी ने वीपी सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया था. श्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में यह महसूस किया कि मौजूदा टैक्स रेट ज़्यादा है, इसलिए लोग कर चोरी करते हैं. उन्होंने तत्कालीन वित्त सचिव बिमल जालान से इसे कम करने के बारे में पूछा.

26 नवंबर को नरेंद्र मोदी सरकार के छह महीने पूरे हो गए. आइए, देखते हैं कि इन छह महीनों में क्या हुआ. एक तो यह कि राष्ट्रीय भावना काफी उत्साहित हुई है. आम आदमी इस बात से उत्साहित है कि हम बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं. दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें कुछ असामान्य घोषणाएं हैं, लेकिन इससे आप असहमत नहीं हो सकते. सबसे पहले यह कि देश भर में शौचालय बनाए जाने चाहिए, खुले में शौच बंद होना चाहिए. इस बात से कोई भी शिकायत नहीं कर सकता. दूसरा है स्वच्छता अभियान. कचरा निपटान ठीक ढंग से हो. ये सब बहुत पुरानी समस्याएं हैं और अब तक इन सबकी उपेक्षा की गई है. इसलिए अब कोई भी शख्स प्रधानमंत्री से असहमत नहीं हो सकता, जब वह इसके लिए एक राष्ट्रीय परियोजना या एक योजना की घोषणा करते हैं. समस्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आती है. आप कैसे हर गांव के लिए यह योजना चलाएंगे? क्या इसके लिए कोई मानक डिजाइन तैयार किया गया है? अगर शौचालय है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो खुले में शौच तब भी होता रहेगा. क्या कोई मिशन है, कोई बॉडी है, कोई अथॉरिटी है, जो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा देने का काम करेगी? धन की व्यवस्था कैसे होगी? या तो सांसद-विधायक निधि का इस्तेमाल हो या सरकार इसके लिए अलग से पैसे दे या फिर कॉरपोरेट को इसके लिए एक अलग अनुदान देने के लिए कहा जाए. ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है. व्यक्तिगत रूप से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रही. इसी तरह सफाई का काम और भी मुश्किल है. फोटो खिंचवाने के लिए नेताओं द्वारा कचरा साफ़ किया जा रहा है, लेकिन असल में हो क्या रहा है?

हानिकारक बायो-डिग्रेडेबल कचरा, धातु और प्लास्टिक सबको एक साथ मिलाकर पॉलिथीन बैग में डाल दिया जाता है. इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा. हमें इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे. अलग-अलग तरह के कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बे उपलब्ध कराने होंगे. आधुनिक विधि से कचरे का निपटान करना होगा. फिर से वही सवाल कि इसके लिए कौन फंड देने जा रहा है और पैसा कहां से आएगा? मुंबई नगर निगम की तरह समृद्ध नगर निगमों के पास पैसों की कमी नहीं है. फिर भी मुंबई में कचरा भयंकर रूप से फैला हुआ है. लोग जहां मन होता है, वहीं कूड़ा फेंक देते हैं. पर्याप्त संख्या में डस्टबिन नहीं हैं. मुंबई में अनुबंध पर सफाई का काम हो रहा है. जहां भी नगर निगम के आदमी सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने ठेकेदार को यह काम दे दिया है और ठेकेदार काम कर रहे हैं. वे अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा तभी मिलेगा, जब सफाई होगी. अब यह मॉडल पूरे देश के लिए सही मॉडल है या नहीं, मैं नहीं जानता. सरकारी सफाईकर्मी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आप इसे आउटसोर्स कर रहे हैं. लेकिन, तथ्य यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे समृद्ध नगर निगम संगठित तरीके से ही सफाई का काम करा सकते हैं, चाहे वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा हो या ठेकेदार द्वारा. इसी प्रकार छोटे शहरों में जहां नगर पालिका या पंचायत है, वहां भी इस काम के लिए किसी को इसी तरह अधिकृत कर देना चाहिए. अन्यथा यह सब प्रधानमंत्री का एक अच्छा इरादा बनकर रह जाएगा और असल में होगा कुछ नहीं.

इन छह महीनों में इस सबके अलावा, प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों और चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान आदि के साथ संबंधों में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की. यह बहुत अच्छा है. हालांकि, इन देशों के साथ हमारे संबंध खराब भी नहीं थे, लेकिन इसे एक नई दिशा देना स्वागत योग्य बात है. बेशक, दुनिया की राजनीति में यह समझा जाना चाहिए कि हर देश अपना हित पहले देखता है और किसी को यह खराब भी नहीं लगना चाहिए. भारत को अमेरिका एक बड़े बाज़ार के रूप में देखता है. आपको अपने हित खुद देखने होंगे. प्रधानमंत्री द्वारा सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना एक स्वागत योग्य पहल है. यह पिछले छह महीनों का प्लस साइड है. आर्थिक नीति की दिशा में काम किया जाना रह गया है. पिछले बजट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन वित्त मंत्री ने अगले बजट में दूसरी पीढ़ी के सुधारों का वादा किया है. वास्तव में उनका क्या मतलब है, हम नहीं जानते. लीगल सिस्टम की बात करें, तो इसके लिए एक ओवरहॉल की ज़रूरत है. यहां एक मुकदमे में जिस तरह से सालों साल लगते हैं, पैसा खर्च होता है, उससे ग़रीब और मध्यम वर्ग का आदमी अदालत जाना बंद कर देगा. इसके लिए क्या होने जा रहा है, इस दिशा में क़ानून मंत्रालय क्या करेगा? सक्रिय दृष्टिकोण के साथ काम कर रही सरकार को मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे और किन उपायों से आम आदमी को कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन, मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर कोई क़दम नहीं उठाया जा रहा है.

इसी प्रकार वित्तीय मोर्चे को देखें, तो मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही, जो इस पार्टी का मुख्य आधार हैं. चाहे बिक्रीकर या इंस्पेक्टर राज की बात क्यों न हो. मैंने छोटे व्यापारियों से बात की है. उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं आया है. अच्छे इरादों के साथ मोदी सरकार आ गई है, लेकिन ज़मीन पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है. इस सबका समाधान निकलना ज़रूरी है. क्या वित्त मंत्री यह सब करना चाहते हैं, हम नहीं जानते. दुनिया में तेल की क़ीमतों में तेजी से कमी आई है. इससे वित्त मंत्री को राहत मिली है. इम्पोर्ट बिल घटा है, चालू खाता घाटा कम हुआ है. खाद्य भंडार ठीकठाक है, इसलिए फूड स्टॉक जारी करके मुद्रास्फीति नीचे लाई जा सकती है. इसलिए वित्त मंत्री के पास काफीकुछ करने के लिए है जो पिछली सरकार नहीं कर सकी थी. अब वे कितना कुछ करतेहै, इसका इंतजार है. इस सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा यह है कि आख़िर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (पूर्वव्यापी टैक्स) को क्यों नहीं ख़त्म करती? इसे तो सरकार को शपथ लेते ही 24 घंटे के भीतर ख़त्म कर देना चाहिए था. इस पर तो सर्वसम्मति भी है. वित्त मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी, जो बेवजह है. इस बजट से पहले अगर कुछ नहीं होता है, तो कम से कम उन्हें इसे (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) ख़त्म कर देना चाहिए. इससे भारत और भारत से बाहर के निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा कि भारत एक निष्पक्ष देश है और यहां व्यापार किया जा सकता है.

वित्त मंत्री बहुत ही समझदार हैं. वह सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस सबको लागू करने में उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां होंगी. बावजूद इसके, अगले बजट से पहले उनका मन स्पष्ट होना चाहिए और कुछ साहसिक निर्णय लेने चाहिए. मैं 1985 को याद करता हूं, जब राजीव गांधी ने वीपी सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया था. श्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में यह महसूस किया कि मौजूदा टैक्स रेट ज़्यादा है, इसलिए लोग कर चोरी करते हैं. उन्होंने तत्कालीन वित्त सचिव बिमल जालान से इसे कम करने के बारे में पूछा. सभी नौकरशाहों की तरह जालान ने कहा कि इससे हमें राजस्व का नुक़सान होगा. और, सभी राजनीतिक व्यक्तियों की तरह वीपी सिंह ने मुस्कराते हुए कहा कि इस दर पर कोई करों का भुगतान नहीं करता है, तो आप कैसे राजस्व खो रहे हैं? उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए टैक्स रेट घटा दिए. 1985 के बाद से भारत के राजस्व की स्थिति बहुत अच्छी है. तीस फ़ीसद के व्यक्तिगत कराधान की वजह से आज ज़्यादा लोग कर भुगतान करते हैं.

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि हमें टैक्स कम करना चाहिए, ताकि लोग उसका भुगतान कर सकें. मैं अभी कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, जिन पर कर नहीं लगना चाहिए या लगे भी, तो 10 फ़ीसद से ज़्यादा नहीं. जबकि हम अभी उन पर 30 फ़ीसद कर लगा रहे हैं. ऐसे लोगों पर कम कर लगाने से उनके हाथ में पैसा रहेगा, जिसे वे भारत की अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, चाहे वह बैंक में सावधि जमा हो या शेयर बाज़ार या फिर किसी अन्य तरीके से. इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लेकिन इन उपायों को लागू करने का फ़ैसला प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है यानी केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिंदी पत्रकारिता और चौथी दुनिया

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

चौथी दुनिया हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का पहला साप्ताहिक ब्रॉडशीट पेपर था, इसे पहला ब्रॉडशीट रविवारीय अख़बार भी कह सकते हैं. मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इसका पहला संपादक था. मैं यह संक्षिप्त परिचय इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि कई मित्रों का ऐसा गंभीर आग्रह था कि कुछ न कुछ चौथी दुनिया के बारे में अवश्य लिखा जाना चाहिए. चौथी दुनिया ने शायद कुछ ऐसा ज़रूर किया था, जिससे वह पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ. बहुत से आईएएस व आईपीएस मिले, जिन्होंने कहा कि उन्हें आईएएस या आईपीएस बनाने में चौथी दुनिया का बहुत बड़ा हाथ था. हालांकि, चौथी दुनिया इसलिए नहीं निकला था कि वह लोगों को आईएएस और आईपीएस बनने में मदद करे. रविवार पत्रिका से सुरेंद्र प्रताप सिंह हट चुके थे तथा रविवार ने अपनी दिशा बदल दी थी. उदयन शर्मा के संपादकत्व में रविवार निकल रही थी, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, जो रविवार की स्पष्टता व निष्पक्षता के कायल थे. दिनमान भी आपातकाल से जो पटरी से उतरा, तो बहुत से लोगों को निराशा दे गया. रविवार के तीखेपन और दिनमान की गंभीरता लिए एक पत्र की आवश्यकता थी. शायद इतिहास ऐसे ही समय संयोग पैदा करता है.

मैं बंबई गया हुआ था. कमल मोरारका जी से मिलने चला गया. पत्रकारिता पर बात चल रही थी और हम दोनों के विचार एक नई विधा पर मिल गए. कमल जी ने कहा कि आप अख़बार क्यों नहीं निकालते? मैंने कहा, पैसा कहां है? कमल जी ने कहा, मैं लगाता हूं. बात विश्लेषण से शुरू हुई, पर गंभीर हो गई. मैंने पूछा, कब से काम शुरू किया जाए? मुझे लग रहा था कि कमल जी कहेंगे कि अगली बैठक में तय करेंगे. पर उन्होंने कहा कि आज से. वह गंभीर थे. मैंने वहीं से कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया.

मैं पुराने लोगों को लेने के ख़िलाफ़ था, इसलिए नए लोगों को लेने का फ़ैसला लिया. यह मैंने सुरेंद्र जी से सीखा था. पुराना अपने ज्ञान के मद में कुछ ज़्यादा डूबा रहता है, जबकि नए को मौक़ा मिले, तो वह अपने आपको साबित करने के लिए दिन-रात एक कर देता है. राम कृपाल जी के बहुत कहने पर मैं रविवार से केवल अजय चौधरी को लेने के लिए तैयार हुआ, पर उससे पहले हरि हमारे साथ आ चुके थे. अजय चौधरी उदयन के बहुत विश्वासपात्र थे. मुझे लग रहा था कि अजय आएंगे, तो उदयन को लगेगा कि मैं उनकी टीम तोड़ रहा हूं तथा मेरा उन पर विश्वास नहीं जम पाएगा. पर राम कृपाल चाहते थे, इसलिए दबाव डाल रहे थे.

जब उदयन शर्मा रविवार के संपादक बने, तब मैं रविवार का विशेष संवाददाता बनकर दिल्ली आ गया. उन्होंने मुझे कहा कि रविवार की डेस्क उनका सहयोग नहीं कर रही है. क्या दो लोग ऐसे आ सकते हैं, जो विश्वस्त भी हों और पूर्ण पत्रकार भी. उन दिनों लखनऊ नवभारत टाइम्स में राम कृपाल वरिष्ठ उप-संपादक व कमर वहीद नकवी उप-संपादक थे. मैंने उनका नाम सुझाया. उदयन ने उन्हें तैयार करने की ज़िम्मेदारी भी मुझे सौंप दी. मैंने दोनों से बात की और दोनों कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो गए. इन दोनों ने जाकर रविवार को संभाल लिया. जब कमल जी ने कहा कि अख़बार निकालना ही है, तब मुझे इन्हीं का ध्यान आया. मैंने इन्हें नए साप्ताहिक की कल्पना, योजना, सपने व उसके ख़तरे बताए, पर इन्होंने कहा कि आपकी सलाह पर हम रविवार में आए, पर संतुष्टि नहीं मिल रही. इसलिए आप आने को कहेंगे, तो हम दिल्ली आएंगे. मैंने इन्हें आमंत्रित कर दिया.

दिल्ली में साप्ताहिक पत्र का खाका बना. सारी चीजें बुनियादी तौर पर मुझे ही करनी पड़ीं. योगेंद्र राठौर भाग-दौड़ के लिए साथ आए तथा मैनेजमेंट का काम संभाला. एक महीने बाद कमल जी ने बंबई से शैलेंद्र दुबे को भेज दिया, जिन्हें आर्थिक संयोजन करना था. राम कृपाल व नकवी भी कलकत्ता से आ गए, योजनाएं बनने लगीं. किन्हें लेना है, इस पर विचार होने लगा. मैं पुराने लोगों को लेने के ख़िलाफ़ था, इसलिए नए लोगों को लेने का फ़ैसला लिया. यह मैंने सुरेंद्र जी से सीखा था. पुराना अपने ज्ञान के मद में कुछ ज़्यादा डूबा रहता है, जबकि नए को मौक़ा मिले, तो वह अपने आपको साबित करने के लिए दिन-रात एक कर देता है. राम कृपाल जी के बहुत कहने पर मैं रविवार से केवल अजय चौधरी को लेने के लिए तैयार हुआ, पर उससे पहले हरि हमारे साथ आ चुके थे. अजय चौधरी उदयन के बहुत विश्वासपात्र थे. मुझे लग रहा था कि अजय आएंगे, तो उदयन को लगेगा कि मैं उनकी टीम तोड़ रहा हूं तथा मेरा उन पर विश्वास नहीं जम पाएगा. पर राम कृपाल चाहते थे, इसलिए दबाव डाल रहे थे. अंत में अजय चौधरी को लेने का निर्णय लिया गया.

मैं बंबई गया हुआ था. कमल मोरारका जी से मिलने चला गया. पत्रकारिता पर बात चल रही थी और हम दोनों के विचार एक नई विधा पर मिल गए. कमल जी ने कहा कि आप अख़बार क्यों नहीं निकालते? मैंने कहा, पैसा कहां है? कमल जी ने कहा, मैं लगाता हूं. बात विश्लेषण से शुरू हुई, पर गंभीर हो गई. मैंने पूछा, कब से काम शुरू किया जाए? मुझे लग रहा था कि कमल जी कहेंगे कि अगली बैठक में तय करेंगे. पर उन्होंने कहा कि आज से. वह गंभीर थे. मैंने वहीं से कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया.

वीरेंद्र सेंगर के बारे में मुझे बहुतों ने सावधान किया कि इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि यह आंदोलनकारी टीम के मुखियाओं में रहते हैं. इनसे लिखवाना चाहिए, पर स्टॉफ में नहीं रखना चाहिए. मुझे लगा कि सलाह सही नहीं है, यदि पत्रकार अच्छा है, तो उसे लेने का ख़तरा उठाना चाहिए. अरविंद के कुछ लेख मुझे जनसत्ता में पढ़ने को मिले थे, उनका पता मैंने जनसत्ता से तलाशा और उन्हें तलाश कर इलाहाबाद से बुलवाया. आलोक पुराणिक, राजीव कटारा व विनोद चंदोला ऐसे साथी थे, जो नए थे व जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत चौथी दुनिया से की. अर्चना झा के बारे में सुरेंद्र जी कहा. एक और मेहनती लड़की सुमिता भी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

जनता परिवार की एकजुटता बहुत ज़रूरी है

सारा देश विपक्ष विहीन है. विपक्षी दलों में कांग्रेस के पास लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या है. कभी-कभी तो ऐसा लगता है, जैसे अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मानसिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया है कि वे चुनाव हार चुके हैं. और, शायद इसी मानसिकता का एक उदाहरण है कि राहुल गांधी के थिंक टैंक के एक सदस्य ने देश के सौ युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों की बैठक बुलाई और उसमें तीन घंटे तक उन्हें यह समझाया कि 2014 में कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है, बल्कि कांग्रेस चुनाव जीती है. शायद यह दिमागी भ्रम का सबसे सटीक उदाहरण है. आशा थी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के छह महीने बीतने पर उनके क़दमों, उनके विचारों और सरकार द्वारा चिन्हित रास्ते के बारे में विपक्ष की ओर से एक सक्रिय संदेश देश को दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ.

मार्क्सवादी पार्टी या दूसरे शब्दों में कहें, तो वामपंथी दल अपने सिमटे हुए जनाधार के धक्के से अभी तक नहीं उबर पाए हैं. और, दूसरी तरफ़ जयललिता हों, नवीन पटनायक हों या फिर ममता बनर्जी हों, वे इस स्थिति में ही नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी का जवाब दे सकें. ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के एक सांसद की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है. शायद यह ममता बनर्जी का विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका का सही आकलन न कर पाना माना जा सकता है. उनकी पार्टी के कई सारे लोग जिस सारदा चिटफंड घोटाले में फंसे दिखाई दे रहे हैं, उससे उन्हें बचाने की छटपटाहट तो मानी जा सकती है, पर यह विपक्षी नेता का रोल नहीं माना जा सकता. विपक्ष के नेता का रोल बहुत बड़ा होता है, उसे हर क़दम पर सत्ता पक्ष के क़दमों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है और उस नज़र का सैद्धांतिक व वैज्ञानिक विश्लेषण कर जनता को समझाना होता है. और, जब सालों के बाद चुनाव होते हैं, उस समय जनता विपक्ष के नेताओं को तौलती है और उन्हें सत्ता में आना है या नहीं, यह तय करती है.

इस विपक्ष विहीन देश की राजनीति में अगर कोई बड़ी हलचल मची है, तो वह जनता परिवार के एकजुट होने की संभावना को लेकर मची है. नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव की पहल पर जनता परिवार के बिखरे हुए तमाम नेता दो बार एक साथ बैठ चुके हैं. इन नेताओं को एक साथ लाने में मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है. मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में समाजवादी विकल्प देने के लिए बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं और वह नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक सार्थक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं. पर वे सवाल अभी तक वहीं के वहीं हैं, जिनकी वजह से जनता परिवार बिखरा था. लेकिन, इस समय ऐसा लगने लगा है कि उन सवालों का हल जनता परिवार के नेता तलाशने में जुटे हुए हैं.

नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता परिवार के तमाम बिखरे हुए लोग, जिनमें पहला नाम देवगौड़ा जी का है, दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव का है, तीसरा नाम लालू यादव का है, चौथा नाम ओम प्रकाश चौटाला का है और पांचवीं उनकी स्वयं की पार्टी, जिसमें वह, शरद यादव और केसी त्यागी जैसे लोग शामिल हैं, सब मिलकर एक दल बनाएं. नीतीश कुमार का मानना है कि यदि एक दल नहीं बनता है, तो वे लोग नरेंद्र मोदी की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते. नीतीश कुमार का यह भी मानना है कि यह परिवार उस कहानी को चरितार्थ कर रहा है, जिसमें एक किसान ने अपने पुत्र को समझाया था कि सात लकड़ियां अलग-अलग रहने पर आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन अगर वे एक साथ बंध जाएं, एक साथ मिल जाएं, तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है. और, इसलिए वह जोर दे रहे हैं कि सब लोग मिलकर एक दल बनाएं और इस अभियान में उन्हें मुलायम सिंह यादव, देवगौड़ा जी और ओम प्रकाश चौटाला का खुला समर्थन प्राप्त है.

दिसंबर में जनता परिवार की होने वाली तीसरी बैठक में इस बात की संभावना है कि मुलायम सिंह यादव को नए बनने वाले दल का अध्यक्ष मान लिया जाए और उनके ऊपर यह ज़िम्मेदारी छोड़ दी जाए कि वह बाकी सारे लोगों से बातचीत कर नए दल का नाम, उसका झंडा और विलय की प्रक्रिया तय करें. मुलायम सिंह यादव उस पार्टी में सबका रोल देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि देश बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का रोल ज़्यादा देखते हैं. नीतीश कुमार का ज़्यादा रोल देखने का मतलब यह नहीं है कि लालू यादव या शरद यादव या ओम प्रकाश चौटाला की हैसियत कम होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह एक पूर्ण रूप से काम करने वाले संगठन का नक्शा बनाना चाहते हैं. संभावना इस बात की भी है कि अगर मुलायम सिंह की अध्यक्षता में एक पार्टी का निर्माण हो जाता है, जिसके बारे में नीतीश कुमार का मानना है कि उसका कुछ भी नाम रखा जा सकता है, बल्कि नीतीश कुमार ने अपने कुछ दोस्तों से यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी का भी नाम हम सब स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि नाम से जीत हासिल नहीं होती है, काम से जीत हासिल होती है.

तो फिर, देश की राजनीति में विपक्ष का एक सार्थक रोल निभाने वाला दल पैदा हो जाएगा और वह दल सत्ता का माकूल जवाब दे सकता है. देवगौड़ा का यह मानना है कि यदि जनता परिवार एक होकर एक पार्टी बना लेता है, तो फिर नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और जयललिता से बात की जा सकती है. और, संसद में लगभग 100 सांसदों का एक ठोस समूह देश की समस्याओं के ऊपर एक राय रख सकता है.

इस सारी स्थिति में मुलायम सिंह यादव का रोल और नीतीश कुमार का आत्मविश्वास एक सार्थक भूमिका निभा रहा है. नीतीश कुमार ने देश में पिछले तीस सालों में नैतिकता का अद्भुत उदाहरण पेश किया है. उन्होंने हार की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया. इसने नीतीश कुमार को बाकी नेताओं से अलग कर दिया है. नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा देने के बाद एक हज़ार से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से बात की और अपनी हार के कारणों को जानने की कोशिश की. और, जैसा नीतीश कुमार अपने दोस्तों को बताते हैं कि उन्हीं कारणों को जानने के लिए उन्होंने बिहार में संपर्क यात्रा शुरू की है. नीतीश कुमार इस संपर्क यात्रा में अपनी उस कमी को स्वीकार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना पड़ा. उस कमी को स्वीकार करने की वजह से कार्यकर्ता दोबारा नीतीश कुमार की तरफ़ आकर्षित हो रहे हैं. पूरी संपर्क यात्रा के दौरान जैसा प्रत्युत्तर नीतीश कुमार को कार्यकर्ताओं की तरफ़ से मिला, उसने एक नए नीतीश कुमार को जन्म दिया है. इस समय नीतीश कुमार आत्मविश्वासी हैं, जोख़िम लेना चाहते हैं और देश में जनता परिवार को एक करने में अपनी भूमिका की महत्ता को भी समझ रहे हैं. नीतीश कुमार उस पूरे संगठन में अपना नाम न रखने का जुआ भी खेल सकते हैं, पर सारे विपक्ष के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के अग्रणी नाम के बिना आज की तारीख में नया बनने वाला दल वह साख हासिल नहीं कर पाएगा, जो साख उसे मिलनी चाहिए.

इसलिए मानना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार की कोशिशों के फलस्वरूप देश में एक नए विपक्षी दल का प्रादुर्भाव होगा, पर इसमें सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि तीन बड़े दलों के अध्यक्ष एक समुदाय से आते हैं. इन दलों के नेताओं को देश को यह भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि यह नया दल सभी वर्गों और सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, तभी इसे जनता के सभी वर्गों का साथ मिलेगा. अभी तक की उपलब्ध नेतृत्व सूची में किसी दलित नेता का नाम नहीं है. इन सारी चुनौतियों को मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और बाकी जनता परिवार के लोग समझेंगे और इसका कोई न कोई ऐसा समाधान निकालेंगे, जो उन्हें भविष्य में या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ जाकर उनके पिछलग्गू का रोल निभाने के लिए मजबूर न करे. यही चुनौती है और इसी का जवाब अगले एक महीने में अगर नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद उस जवाब के मिलने से भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है. ■

editor@chauthiduniya.com

भाषा पर तर्कहीन विवाद

मेघनाद देसाई

ऐसा क्यों है कि अपने क्षेत्र में पदक जीतने वाले सर्वोत्तम भारतीय गणितज्ञ विदेशों में हैं? लेकिन, अभी उनके पास लोकसभा में बहुमत हासिल है, इसलिए उन्हें देश को अपनी तरह से बर्बाद करने का अधिकार है, जैसा कि पिछली प्रभुत्व वाली पार्टियां करती थीं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उन्होंने वास्तव में विवेकानंद को पढ़ा होता, जिनकी नीतियों पर चलने की वे कसमें खाते हैं, तो उन्हें पता चलता कि प्राचीन संस्कृत के यश पर विवेकानंद का संदेह कितना मज़बूत था.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉन एफ कैनेडी और लिंडन जॉनसन के प्रशासन में विदेश मंत्री रह चुके डीन रस्क ने एक बार कहा था कि वाशिंगटन के आशावादी लोग रूसी भाषा सीख रहे हैं, जबकि निराशावादी लोग चीनी. उस समय रूस अमेरिका का अच्छा दुश्मन था और चीन बुरा. भारत में संस्कृत की बजाय जर्मन भाषा पढ़ाने का फ़ैसला यह जाहिर करता है कि भारत के दूरंदेशी, विकासोन्मुखी लोग जर्मन सीखने को तरजीह देना चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी देश को प्राचीन परंपरा की तरफ़ ले जाना चाहते हैं और संस्कृत सीखना चाहते हैं. यह भी एक रूमानी सोच है, जब सभी भारतीय संस्कृत बोलते थे, उस समय भारत में दूध और शहद की नदियां बहती थीं. यह एक मिथ्या है.

संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, जिसे ब्राह्मण बोला करते थे. यही वजह थी कि बुद्ध एवं महावीर ने अपने उपदेश क्रमशः पाली और अर्द्ध-मगधी भाषाओं में दिए. उस समय जो भी स्थिति रही हो, लेकिन आज संस्कृत एक मृतप्राय: भाषा बन गई है. इस भाषा को बोलने वाले जो थोड़े-बहुत लोग हैं, वे भी अशुद्ध भाषा बोलते हैं. अशुद्ध उच्चारण से वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों की दुर्गति होते हम कितनी बार सुनते हैं. संस्कृत इतिहास में हमेशा अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, जिसे सीखने का सौभाग्य केवल ब्राह्मणों को प्राप्त था. हालांकि, मैकाले नए शासक वर्ग के लिए एक तिरस्कारित नाम है, लेकिन अगर वह नहीं होता, तो शायद श्याम कृष्ण वर्मा को संस्कृत पढ़ने की अनुमति कभी न मिलती और न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई करने का मौक़ा मिलता तथा न वे फक्र से अपना सिर ऊंचा कर पाते. यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी उस मुकाम पर न पहुंच पाते, जहां वह आज हैं.

संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, जिसे ब्राह्मण बोला करते थे. यही वजह थी कि बुद्ध एवं महावीर ने अपने उपदेश क्रमशः पाली और अर्द्ध-मगधी भाषाओं में दिए. उस समय जो भी स्थिति रही हो, लेकिन आज संस्कृत एक मृतप्राय: भाषा बन गई है. इस भाषा को बोलने वाले जो थोड़े-बहुत लोग हैं, वे भी अशुद्ध भाषा बोलते हैं. अशुद्ध उच्चारण से वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों की दुर्गति होते हम कितनी बार सुनते हैं.

इसके बावजूद देश में सांस्कृतिक अतिवाद का एक पक्ष है, जो यह हठ पकड़ कर बैठा है कि स्कूलों में जर्मन भाषा की बजाय संस्कृत पढ़ाई जाए. ऐसे लोगों को कौन समझाए कि संस्कृत की बहुत-सी रचनाओं को विदेशियों, खास तौर पर जर्मन विद्वानों ने गुमनामी के अंधेरों से निकाल कर दुनिया के सामने पेश किया. एक तरफ़ तो प्रधानमंत्री भारत की महत्वाकांक्षाओं, तकनीकी दृष्टि से सक्षम और भविष्य की ओर अग्रसर होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ हम यहां बड़ी तेज़ी से अतीत की ओर जा रहे हैं. यह भाजपा का पागलपन है. अगर इसे फलने-फूलने का मौक़ा दिया गया, तो यह सबके लिए विकास की योजना के तहत पूरे भारत को एकजुट करने का मोदी का सपना तहस-नहस कर देगा. संपूर्ण भारत की बात कौन करे, संस्कृत को तो सभी हिंदू ही पसंद नहीं करते. तमिल तो संस्कृत जितनी ही पुरानी भाषा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. तो फिर तमिल को ही क्यों न सभी स्कूलों में पढ़ाया जाए? बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत का कोई उपयोग नहीं है और यह आधुनिक तकनीक के लिए भी उपयुक्त नहीं है. हालांकि नि:संदेह कई लोग होंगे, जो इसमें नए और जटिल प्रयोग (Neologisms) कर सकते हैं.

जर्मन, फ्रेंच, जापानी या मंडारिन जैसी आधुनिक भाषाएं सीखने की बात तो समझ में आती है, लेकिन संस्कृत को स्कूलों के ऊपर थोपना संसाधन की बर्बादी है. आख़िरकार संस्कृत की हर क्लासिक कृति का बेहतर अनुवाद प्रत्येक भारतीय भाषा में मौजूद है. अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद, अब हिंदू राष्ट्रवादी देश में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम लागू करने के लिए अधीर हैं. उनकी सोच अतीत के महिमा मंडन तक संकुचित है. वे यह विश्वास कर लेना चाहते हैं कि सभी अच्छी एवं महान बातें वेदों और महाकाव्यों में दर्ज हैं. यह हीन भावना से ग्रसित होने के संकेत हैं, जो अहंकार की तरफ़ ले जाते हैं. अगर यह सच भी है, तो इससे भारत की प्राचीन संस्कृति की ही बदनामी होगी कि वेद लिखे जाने के बाद सैकड़ों सालों तक भारतीय सभ्यता में ठहराव आ गया. वे यह तर्क देंगे कि पाइथागोरस के थ्योरम (प्रमेय) वैदिक काल में प्रतिपादित हुए थे. अगर यह मान भी लिया जाए, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? भारत का गणित के क्षेत्र में योगदान इस एक थ्योरम से कहीं अधिक है. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि थ्योरम की खोज कहां हुई, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे गणितज्ञ कहां हैं, जो गणित के क्षेत्र में नया काम कर रहे हैं?

ऐसा क्यों है कि अपने क्षेत्र में पदक जीतने वाले सर्वोत्तम भारतीय गणितज्ञ विदेशों में हैं? लेकिन, अभी उनके पास लोकसभा में बहुमत हासिल है, इसलिए उन्हें देश को अपनी तरह से बर्बाद करने का अधिकार है, जैसा कि पिछली प्रभुत्व वाली पार्टियां करती थीं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उन्होंने वास्तव में विवेकानंद को पढ़ा होता, जिनकी नीतियों पर चलने की वे कसमें खाते हैं, तो उन्हें पता चलता कि प्राचीन संस्कृत के यश पर विवेकानंद का संदेह कितना मज़बूत था. भगवद् गीता पर उनका व्याख्यान पढ़िए और गीता के लेखन के संबंध में श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता और अर्जुन का एक हाड़-मांस का इंसान होने पर उनके संदेह को स्वयं देख लीजिए. विवेकानंद कहते हैं कि शायद आदि शंकराचार्य ने खुद ही गीता की रचना की थी और महाभारत में डाल दिया था! एक मात्र सांत्वना यह है कि अगर किसी विषय को छात्रों से नापसंद कराना हो, तो मेरी नज़र में इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि उस विषय को स्कूल में ख़राब ढंग से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए. जैसे ही छात्र इस शिक्षा प्रणाली से बहार निकलेंगे, वे अपने लिए उस भाषा का चयन करेंगे, जो उनके करियर में उपयोगी साबित हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है. हीमोग्लोबीन दो तरह के प्रोटीन से बनता है अल्फा ग्लोबीन और बीटा ग्लोबीन. थैलासीमिया इन दोनों प्रोटीन में ग्लोबीन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी होने से होता है. जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं. रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार–बार रक्त चढ़ाना पड़ता है. रक्त की कमी से हीमोग्लोबीन नहीं बन पाता है एवं बार–बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राणघातक हो जाता है.

थैलासीमिया

बचाव और सावधानी ज़रूरी

मोनिशा भटनागर

थैलासीमिया बच्चों को माता–पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त–रोग है. इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबीन निर्माण प्रक्रिया में दिक्कतें आने लगती हैं, जिसके कारण खून की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इसकी पहचान तीन माह की आयु के बाद ही होती है. इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार–बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है.

थैलासीमिया दो प्रकार का होता है–यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता–पिता दोनों के जींस में माइनर थैलासीमिया होता है, तो बच्चे में मेजर थैलासीमिया हो सकता है, जो काफी घातक हो सकता है. किन्तु माता–पिता में से एक ही में माइनर थेलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा कम होता. यदि माता–पिता दोनों को माइनर रोग है तब भी बच्चे को यह रोग होने की 25 प्रतिशत आशंका बनी रहती है. अतः यह अत्यावश्यक है कि विवाह से पहले महिला–पुरुष दोनों अपनी जांच करा लें. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में प्रत्येक वर्ष सात से दस हजार थैलासीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है. केवल दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही यह संख्या करीब 1500 है. भारत की कुल जनसंख्या का 3.4 प्रतिशत भाग थैलासीमिया ग्रस्त हैं. इंग्लैंड में केवल 360 बच्चे इस रोग के शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में 1 लाख और भारत में करीब 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं.

इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है. हीमोग्लोबीन दो तरह के प्रोटीन से बनता है अल्फा ग्लोबीन और बीटा ग्लोबीन. थैलासीमिया इन दोनों प्रोटीन में ग्लोबीन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी होने से होता है. जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं. रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार–बार रक्त चढ़ाना पड़ता है. रक्त की कमी से हीमोग्लोबीन नहीं बन पाता है एवं बार–बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राणघातक होता है. मुख्यतः यह रोग दो वर्गों में बांटा गया है:

मेजर थैलासीमिया

यह बीमारी उन बच्चों में होने की आशंका अधिक होती है, जिनके माता–पिता दोनों के जींस में थैलासीमिया होता है. जिसे थैलासीमिया मेजर कहा जाता है.

माइनर थैलासीमिया

थैलीसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है, जिन्हें प्रभावित जीन माता–पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है. जहां तक बीमारी की जांच की बात है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रक्त जांच के समय लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जांच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है.

कंप्लीट ब्लड काउंट

सीबीसी से रक्ताल्पता या एनीमिया का पता लगाया जाता है. एक अन्य परीक्षण, जिसे हीमोग्लोबीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, से असामान्य हीमोग्लोबीन का पता लगता है. इसके अलावा म्यूटेशन एनालिसिस टेस्ट (एमएटी) के द्वारा एल्फा थैलासिमिया की जांच के बारे में जाना जा सकता है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी इस बीमारी के उपचार में मदद मिलती है.

लक्षण

सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में थैलासीमिया रोग होने पर दिखाई देते है.

बचाव एवं सावधानी

थैलासीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है. इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों की मृत्य हो जाती है. सही इलाज करने पर 25 वर्ष व इससे अधिक जीने की आशा होती है. जैसे–जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है.

विवाह पूर्व जांच को प्रेरित करने हेतु एक स्वास्थ्य कुंडली का निर्माण किया गया है, जिसे विवाह पूर्व वर–वधु को अपनी जन्म कुंडली के साथ–साथ मिलवाना चाहिये. स्वास्थ्य कुंडली में कुछ जांच की जाती है, जिससे शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े यह जान सकें कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं. स्वास्थ्य कुंडली के तहत सबसे पहली जांच थैलासीमिया की होगी. एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी की भी जांच होगी. इसके अलावा उनके रक्त की तुलना भी की जाएगी और रक्त में आरएच फैक्टर की भी जांच की जाएगी.

इस प्रकार के रोगियों के लिए बहुत सारी संस्थाएं रक्त प्रबंध कराती हैं. इसके अलावा बहुत से रक्तदाता भी रक्तदान करते हैं. थैलासीमिया पर विश्वभर में शोध अनुसंधान जारी है. इन प्रयासों से ही थैलासीमिया पीड़ितों के लिए एक दवाई अविष्कृत हुई थी. इस दवाई से बच्चों को अब इंजेक्शन के दर्द को नहीं झेलना पड़ेगा. जल्दी ही भारतीय बाजार में ये दवा आने वाली है, जिसे खाने से ही शरीर में लौह मात्रा नियंत्रित हो जाएगी. यह दवा पश्चिमी देशों में एक्स जेड नाम से पहले से ही प्रयोग हो रही है. इससे इलाज का खर्च भी कम हो जाएगा, किंतु इसके दुष्प्रभावों (साइड एफ़ेक्टस) में किडनी प्रभावित होने का एक परसेंट खतरा बना रहता है. चिकित्सकों के अनुसार भारत में अतिरिक्त लौह निकालने के लिए दो तरीके प्रचलन में हैं. पहले तरीके में डेसोरॉल (इंजेक्शन) के जरिए आठ से दस घंटे तक लौह निकाला जाता है. यह प्रक्रिया बहुत महंगी और कष्टदायक होती है. इसमें प्रयोग होने वाले एक इंजेक्शन की कीमत 164 रुपए होती है. इस प्रक्रिया में हर साल पचास हजार से डेढ़ लाख रुपए तक खर्च आता है. दूसरी प्रक्रिया में कैलफर नामक दवा (कैप्सूल) दी जाती है. यह दवा सस्ती तो है लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले 30 प्रतिशत रोगियों को जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है. साथ ही इनमें से एक प्रतिशत बच्चे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते है. ऐसे में नई दवा काफ़ी लाभदायक होगी. यह दवा फलों के रस के साथ मिलाकर पिलाई जाती है और इसकी कीमत 100 रुपये प्रति डोज है.

बोन मैरो ट्रांस्प्लांट

थैलासीमिया के लिए स्टेम सेल से उपचार की भी संभावनाएं हैं. इसके अलावा इस रोग के रोगियों के बोन मैरो ट्रांस्प्लांट हेतु अब भारत में भी बोनमैरो डोनर रजिस्ट्री खुल गई है. मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया (एम.डी.आर.आई) में बोनमैरो दान करने वालों के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां होगी जिससे देश के ही नहीं वरन विदेश से इलाज के लिए भारत आने वाले रोगियों का भी आसानी से उपचार हो सकेगा. यह केंद्र मुंबई में स्थापित किया जाएगा. ऐसे केंद्र वर्तमान में केवल अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशो में ही थे. ल्यूकेमिया और थैलासीमिया के रोगी अब बोनमैरो या स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए इस केंद्र से संपर्क कर बोन मैरो करने वालों के बारे में जानकारी के अलावा उनके रक्त था लार के नमूनों की जांच रिपोर्ट की जानकारी भी ले पाएंगे. जल्दी ही इसकी शाखाएं महानगरों में भी खुलने की योजना है.■

feedback@chauthiduniya.com

नाजियों के खिलाफ चालें चली थीं नैंसी वेक ने

30 नवंबर, 1939 को उन्होंने फ्रांस के सबसे अमीर बिजनेसमैन हेनरी एडमंड के साथ शादी की. इसके बाद नवविवाहित जोड़ा मरसिले में रह रहा था तभी जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया था. वर्ष 1940 में फ्रांस की हार के बाद जब फ्रांसीसी सेना ने जर्मनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया तो नैंसी ने सूचना गुप्तचर के रुप में बहुत ख्याति अर्जित की. लेकिन नाज़ी सेना की नज़रों में वह खटकने लगी थीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

नैंसी ग्रेस अगस्ता वेक मित्र देशों की सबसे ज्यादा सम्मानित जासूसों में से एक हैं. उनका जन्म 30 अगस्त 1912 को न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंग्टन में हुआ था. जब वह केवल दो साल की थीं, तब उनके माता–पिता ऑस्टेलिया चले गए. हालांकि कुछ साल बाद ही उनके पिता न्यूजीलैंड वापस आ गए थे, लेकिन नैंसी मां के साथ सिडनी में रह गईं. इसके बाद नैंसी की शुरुआती शिक्षा–दीक्षा सिडनी में ही हुई.

16 वर्ष की उम्र में नैंसी घर से भाग गईं और कुछ समय तक नर्सिंग का काम किया. नैंसी की चाची की वसीयत से उन्हें 200 पाउंड की रकम मिली. उस रकम को नैंसी ने न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में घूमने में खर्च किया. उस दौरान उन्हें एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए रिपोर्टिंग करने का मौका मिला. माना जाता है कि वह नैंसी के व्यक्तित्व के निखार का वक्त था. उस दौरान एक तरीके से उन्होंने पत्रकारिता की ट्रेनिंग ही नहीं ली बल्कि अपने आपको साबित करने की कोशिश भी की. वह कुछ ऐसे लोगों में शामिल थीं जिन्होंने घूम–घूम कर पूरे द्वितीय विश्व युद्ध को अपनी आंखों से देखा. उस दौरान उस बात को नजदीक से देखा कि आखिर किस तरह से हिटलर और उसकी सेना यहूदियों के खिलाफ अत्याचार कर रही है. सिर्फ इतना ही नहीं पेरिस और विएना आदि जगहों में किस तरह से नाजी सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे. इसके बाद नैंसी ने फैसला किया कि वह हिटलर के यहूदियों के खिलाफ चलाए रहे अत्याचार के खिलाफ काम करना शुरु करेंगी.

30 नवंबर, 1939 को उन्होंने फ्रांस के सबसे अमीर बिजनेसमैन हेनरी एडमंड के साथ शादी की. इसके बाद नवविवाहित जोड़ा मरसिले में रह रहा था तभी जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया था. वर्ष 1940 में फ्रांस की हार के बाद जब फ्रांसीसी सेना ने जर्मनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया तो नैंसी ने सूचना गुप्तचर के रुप में बहुत ख्याति अर्जित की. लेकिन नाज़ी सेना की नज़रों में वह खटकने लगीं थीं. आखिर हिटलर यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी सेना के खिलाफ जासूसी करे और गुप्त सूचनाओं को विरोधियों तक पहुंचाने का काम करे. हिटलर के लिए विरोधी जासूसों की सिर्फ एक ही सजा थी, और वह थी सज़ा–ए –मौत.

नैंसी ने कैप्टन उयान गैरो के नेतृत्व में काम करना शुरु किया था. यहीं से नैंसी के जीवन में परिवर्तन आ गया. उन्होंने फ्रांसीसी सेना को जर्मनी के हथियारों के बारे में जानकारी देना शरू किया, आखिर कैसे जर्मनी की सेना अपने हथियारों को फ्रांस तक पहुंचा रही है. 1944 में उन्होंने ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन टीम को ज्वाइन की और फ्रांस की सेनाओं को हथियार मुहैया कराने की कोशिशों में लग गईं. फ्रांस की सेना नैंसी को लेकर काफी चिंतित रहा करती थीं. क्योंकि जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी उनके फोन टैप करती थी और उनके हर कदम पर नज़र रखा करती थी. जर्मनी की खुफिया एजेंसी नैंसी को व्हाउट माउस के नाम से पुकारती थी.

जब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो नैंसी ने बहुत ही बहादुरी के साथ जर्मनी की सेना के साथ लोहा लिया. युद्ध के वक्त एक बार वेक ने कहा था कि स्वतन्त्रता मेरा एकमात्र लक्ष्य है और युद्ध के दौरान मैं अगर दुश्मन के हाथों मारी जाऊं तो इसका मुझे कोई मलाल नहीं होगा क्योंकि स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है.

दूसरे विश्वयुद्ध के खत्म होने के बाद वेक को फ्रेंच सरकार की ओर से सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड लेगिओन–डी–ऑनर, यूके सरकार की ओर से जॉर्ज मेडल, अमेरिका की ओर से मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया. लेकिन वेक को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सरकार की ओर से कोई अवार्ड नहीं दिया गया.

1957 में वेक ने दूसरी बार शादी की. इस बार उन्होंने एक अंग्रेज फाइटर पायलट जॉन मेल्विन से शादी की. वेक ने कई बार ऑस्ट्रेलियाई संसद में निर्वाचित होकर पहुंचने की कोशिश की लेकिन वह अपने प्रयास में कभी सफल नहीं हुईं. वेक ने अपनी आत्मकथा द व्हाइट माउस के नाम से लिखी. यह किताब अपने वक्त की बेस्ट सेलर थी.■

feedback@chauthiduniya.com

अपना यह लक्ष्य पूरा करने के लिए उसने उत्तरी अमेरिका के डकोटा एवं टेक्सास के आसपास कच्चा तेल प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया और उत्पादन में 70 फ़ीसद की वृद्धि करके प्रथम नंबर पर आ गया. अभी तो अमेरिका सिर्फ़ दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल पैदा करने वाला राष्ट्र बना है, लेकिन अंदाज़ा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला राष्ट्र बन जाएगा.

अमेरिका

अवैध अप्रवासियों को क़ानूनी दर्जा

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका में रह रहे 50 लाख से ज़्यादा अवैध अप्रवासियों को क़ानूनी दर्जा देने की घोषणा की है. इससे उन भारतीयों को भी फ़ायदा होगा, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं. यह आव्रजन नीति को लेकर उठाया जाने वाला सबसे बड़ा क़दम है. इस घोषणा से आईटी क्षेत्र में काम करने वाले एच-1 बी वीजाधारक भारतीयों को मदद मिल सकती है. ओबामा प्रशासन के इस क़दम से अमेरिका में आवश्यक कागजातों के बिना काम कर रहे एक करोड़ 10 लाख लोगों में से पचास लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा. ओबामा ने राष्ट्र के नाम एक संदेश में कहा कि हम आवश्यक कागजातों के बिना रह रहे लाखों अप्रवासियों को लेकर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे. ओबामा ने कहा कि अमेरिका को अप्रवासियों का देश कहा जाता है, लेकिन यह क़ानूनों वाला भी देश है. और, वैसे अप्रवासियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने क़ानून तोड़ा है, खासकर वे, जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं. ■

नाइजीरिया

बोको हराम ने 45 लोगों को मारा

उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम आतंकियों के एक हमले में 45 लोग मारे गए. उक्त आतंकी 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उन्होंने गांव में काम कर रहे लोगों को मारना शुरू कर दिया. यह हमला बोरनो प्रदेश के माफा इलाके के अजायाकुरा गांव में हुआ. ग्राम प्रधान के मुताबिक, हमले के बाद 45 लोग मृत पाए गए. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, अगर लोग भागकर झाड़ियों में न छिपे होते, तो मरने वालों की संख्या और अधिक होती. समीपवर्ती इलाके में ही पिछले महीने बोको हराम के आतंकियों ने 30 से अधिक लड़के-लड़कियों का अपहरण कर लिया था. दरअसल, बोको हराम देश से मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और उसे एक इस्लामिक देश में तब्दील करना चाहता है. कहा जाता है कि बोको हराम के समर्थक कुरान के उस कथन से प्रभावित हैं कि जो भी अल्लाह द्वारा कही गई बातों पर अमल नहीं करता है, वह पापी है. बोको हराम इस्लाम के उस संस्करण को मानता है, जो मुसलमानों को पश्चिमी समाज से संबंध रखने वाली किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेने से मना करता है. ■

आईएसआईएस

ब्रिटिश बंधक का सातवां वीडियो

आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ब्रिटिश बंधक जॉन कैंटली का सातवां वीडियो जारी किया है. उक्त वीडियो में कैंटली ने अमेरिका की नाकाम कोशिशों के बारे में खुलासा किया है. इस बार भी वह नारंगी कपड़ों में संदेश देते नज़र आ रहे हैं. नौ मिनट के इस वीडियो में ब्रिटिश बंधक कैंटली ने दावा किया कि अमेरिका जुलाई में बंधकों को छुड़वाने में नाकाम रहा है. उसकी कार्रवाई से पहले ही आईएसआईएस के आतंकियों ने सभी बंधकों को अन्य जगह पर भेज दिया था. उन्होंने बताया कि अमेरिका के इस क़दम में डेल्टा फोर्स कमांडो, ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर सहित कई लड़ाकू जेट विमान शामिल थे, लेकिन हम वहां थे ही नहीं. कैंटली कहते हैं, मुझे भी अन्य बंधकों की तरह मार दिया जाएगा. मैं तब तक ही बोल पाऊंगा, जब तक आतंकी मुझे जीवित रखेंगे. कैंटली को दो साल पहले सीरिया में बंधक बना लिया गया था. ग़ौरतलब है कि ब्रिटिश बंधक का यह नया वीडियो अमेरिकी बंधक पीटर कासिग की हत्या के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है. ■

संयुक्त अरब अमीरात

लश्कर, आईएम आतंकी संगठन घोषित

संयुक्त अरब अमीरात ने लश्कर-ए-तैयबा एवं इंडियन मुजाहिदीन समेत 74 संगठनों को आतंकवादी संस्थान घोषित किया है. आतंकवाद निरोधक क़ानून के तहत घोषित इस सूची में तालिबान, अलकायदा, दाओश एवं मुस्लिम ब्रदरहुड नामक आतंकी संगठन भी शामिल हैं. संयुक्त अरब अमीरात का आतंकवाद निरोधक क़ानून वहां की सरकार को आतंकी संगठनों की सूची प्रकाशित करने का अधिकार देता है. अब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उक्त सूची में शामिल आतंकी संगठनों से संपर्क करना, उनकी गतिविधियों में शामिल होना और उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देना अपराध माना जाएगा. अगर कोई आतंकी संगठनों से संपर्क रखता है और उनके हितों के लिए काम करता है, तो उसे उम्रक़ैद की सजा दी जाएगी, जबकि आतंकी वारदात करने पर सजा-ए-मौत दी जाएगी. ■

तेल-गैस का उत्पादन

अमेरिका अब सऊदी अरब और रूस से आगे

वसीम अहमद

अमेरिका कच्चे तेल के उत्पादन के लिहाज से सऊदी अरब को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा देश बनने के क़रीब पहुंच चुका है. अमेरिका से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र ग्लोबल एनर्जी के अनुसार, अतीत की तुलना में अमेरिका के कच्चे तेल के उत्पादन में 7 फ़ीसद की वृद्धि हुई है. कच्चे तेल के उत्पादन के लिहाज से अब तक यह श्रेय सऊदी अरब को हासिल था. 2012 के सर्वे के अनुसार, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल एवं लिक्विड निर्यात करने वाला देश था. अमेरिका की सहायता से सऊदी अरब प्रति दिन 11.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता था और उसमें से 8.6 मिलियन बैरल निर्यात होता था, लेकिन आईईए (इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब से ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन किया. अमेरिका ने मध्य अगस्त से मध्य नवंबर तक अपने कुल उत्पादन में 70 फ़ीसद की वृद्धि दर्ज की है. 2012 तक अमेरिका सामूहिक तौर पर 7.03 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता था और अपनी ज़रूरत का 30 फ़ीसद हिस्सा विदेश से आयात करता था. जाहिर है, उसे अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता था. इसलिए अमेरिका की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि वह अपने यहां कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करे, ताकि उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े.

अपना यह लक्ष्य पूरा करने के लिए उसने उत्तरी अमेरिका के डकोटा एवं टेक्सास के आसपास कच्चा तेल प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया और उत्पादन में 70 फ़ीसद की वृद्धि करके प्रथम नंबर पर आ गया. अभी तो अमेरिका सिर्फ़ दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल पैदा करने वाला राष्ट्र बना है, लेकिन अंदाज़ा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला राष्ट्र बन जाएगा. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, अमेरिका ने इस वर्ष के पहले तीन माह में प्रति दिन 11 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन किया. लेकिन, उत्पादन की यह स्थिति हमेशा बरकरार नहीं रखी जा सकती. बावजूद इसके अगर उत्पादन बढ़ने की गति यही रही, तो 2015 तक अमेरिका प्रति दिन 10 मिलियन बैरल और 2020 तक 11.1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करने की स्थिति में आ जाएगा और तब वह दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल पैदा करने वाला राष्ट्र बन जाएगा.

दूसरी ओर सऊदी अरब, जिसे प्रकृति ने कच्चे तेल का भंडार दे रखा है और जो ओपेक देशों को कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है, उसकी यह हैसियत अब ख़त्म हो रही है. उसके उत्पादन में चार फ़ीसद की गिरावट आई है. अगर उसके उत्पादन में इसी तरह कमी आती रही और तेल के कुओं के सूखने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो 2015 तक उसकी उत्पादन क्षमता घटकर 10.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन एवं 2020 तक 10.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकती है. ग़ौरतलब है कि इस कमी का प्रभाव उसके तेल के भंडारों पर पड़ेगा. हालांकि सऊदी पेट्रोलियम मंत्री अली नाइमी का कहना है कि सऊदी अरब के पास अभी इतना भंडार मौजूद है कि 80 वर्षों तक उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी. उनका कहना है कि सऊदी अरब के पास अब भी क्रूड तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं. इन भंडारों में तेल का अंदाज़ा 264 अरब बैरल बताया गया है. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अगले 80 वर्षों तक अपने कच्चे तेल के वर्तमान निर्यात स्तर को भी बरकरार रख सकता है. लेकिन, जिस तरह से सऊदी अरब की अपनी खपत बढ़ती जा रही है और उत्पादन में कमी हो रही है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसके भंडार इतने लंबे समय तक उसका साथ दे पाएंगे. सऊदी अरब की अपनी तेल खपत 3.2 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जो अगले 20 वर्षों के अंदर 8 मिलियन बैरल तक पहुंच सकती है. इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के अंदर तेल की खपत बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है. अगर कम होने का यह सिलसिला बढ़ा, तो उस स्थिति में निश्चय ही आठ मिलियन बैरल प्रति दिन की खपत की ज़रूरत तेल भंडार से पूरी करनी होगी. तब उक्त भंडार 80 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे. यह स्थिति पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है. आज पूरी दुनिया की मशीनरी तेल पर निर्भर है. अगर ओपेक राष्ट्रों का सबसे बड़ा निर्यातक देश ही अपना लक्ष्य हासिल करने में नाकाम हो गया, तो आने वाले समय में कठिनाई पैदा हो सकती है. आज विश्व का 35 प्रतिशत तेल ओपेक राष्ट्र पैदा कर रहे हैं. उनमें सऊदी अरब सबसे आगे है. अभी उक्त राष्ट्र प्रति दिन 1 से 75 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, 2018 तक यह आंकड़ा 36 से 75 मिलियन बैरल प्रति दिन हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दामों में इस समय जो गिरावट आई है, उसका कारण भी कहीं न कहीं अमेरिका द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि है. हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस गिरावट के पीछे अमेरिका एवं सऊदी की सोची-समझी साजिश है. यह सारा खेल ईरान और रूस की आर्थिक स्थिति तबाह करने के लिए खेला जा रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादक राष्ट्रों मसलन लीबिया, इराक, नाइजीरिया एवं सीरिया में अशांति के बावजूद कच्चे तेल के दाम इतने कम हो गए हैं, जितने पिछले कई वर्षों में नहीं हुए थे. इस समय ईरान एवं रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है और उन्हें सीमित मात्रा में कच्चा तेल बेचने की अनुमति है. अगर कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कम होता है, तो जाहिर-सी बात है कि तय की हुई मात्रा में कच्चा तेल आपूर्ति करने के बदले उन्हें विदेशी मुद्रा कम मिलेगी, जिसका सीधा प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. शायद यही कारण है कि ईरान ने ऐसे राष्ट्रों को, जो कच्चे तेल के दाम में कमी करने के पक्ष में हैं, अपना शत्रु बताया है. हालांकि विशेषज्ञ इससे इंकार करते हैं. उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम कम होने का बुनियादी कारण अमेरिका द्वारा बीते कुछ महीनों में किया गया उत्पादन और चीन में औद्योगिक मशीनरी के लिए कच्चे तेल की मांग में कमी होना है. ग़ौरतलब है कि इन दिनों चीन में औद्योगिक मंदी आती जा रही है.

अमेरिका कच्चे तेल का उत्पादन करने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करता है. यही आधुनिक तकनीक उत्पादन में वृद्धि का कारण बनी. इस तकनीक के तहत पानी की तेज धार और अन्य तत्वों को पहाड़ों के बीच से तेजी से छोड़ा जाता है, ताकि पहाड़ से कच्चे तेल के भंडारों के खनन के लिए उन्हें नर्म किया जा सके. उत्तरी अमेरिका में यह तकनीक अपनाने के चलते अमेरिका आगे बढ़ा और वह 2020 तक विश्व में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने की ओर क़दम बढ़ा चुका है. ऐसे में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले ओपेक देश खासे चिंतित हैं. उन्हें लगता है कि अमेरिका द्वारा इस स्तर पर उत्पादन करने से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल का दाम कम हो जाएगा और जो राष्ट्र तेल पर ही आधारित हैं, उनके लिए आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि अमेरिका न सिर्फ़ कच्चे तेल के उत्पादन में सऊदी अरब को पीछे छोड़ रहा है, बल्कि उसने गैस का उत्पादन करने वाले रूस को भी मात दे दी है. आईईए ने कहा है कि उसे आशा है कि गैस के उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका 2015 तक रूस से आगे निकल जाएगा और वह विश्व का सबसे ज़्यादा गैस उत्पादित करने वाला राष्ट्र भी हो जाएगा. वह ऊर्जा से संबंधित अपनी ज़रूरतें पूरी करने के मामले में 2035 तक आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा. अमेरिका ने अपने गैस उत्पादन में 40 फ़ीसद की वृद्धि दर्ज की है. गैस के उत्पादन में रूस एक लंबे समय से अग्रणी रहा है. अगर अमेरिका गैस उत्पादन का यह स्तर बरकरार रखता है, तो वह पूरे विश्व में कच्चे तेल और गैस का बेताज बादशाह बन जाएगा.

अमेरिकी दैनिक वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका में गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जिसका अधिकतर भाग ऐसे स्थान में पाया गया है, जहां उसे निकालने का काम अभी शुरू ही हुआ है. अमेरिका अब तक बाहर से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब वह उस स्थिति में आता जा रहा है कि दूसरे राष्ट्रों को ऊर्जा निर्यात कर सके. बहरहाल, ओपेक देश विशेषकर, सऊदी अरब के लिए यह समाचार चिंता का विषय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी हैसियत कम होती जा रही है. उसे अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए अमेरिका की तरह कोई नई तकनीक इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन ऐसा अमेरिका के सहयोग के बिना संभव नहीं है. ऐसे में यह संभावना बहुत कम है कि सऊदी अरब इस स्थिति से खुद को उबार लेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> स्वामी जी हतप्रभ. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरू मां के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया? शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरू मां से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? मां शारदा ने कहा, तुम्हारा मन देखने के लिए. प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है, तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में समो लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है.

साई चरण सुखदाई है

चौथी दुनिया ब्यूरो

मुंबई में एक श्री हरिश्चन्द्र पितले नामक गृहस्थ थे. उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था. उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्साएं कराईं, लेकिन उनसे कोई लाभ न हुआ. अब केवल एक उपाय बचा था कि किसी सन्त के चरण–कमलों की शरण ली जाए. हरिश्चन्द्र ने साई का गुणगान सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि साई बाबा के केवल हाथ के स्पर्श तथा दृष्टिमात्र से ही असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं. तब उनके मन में भी साई बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है. यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने को फलों की टोकरी लेकर स्त्री और बच्चों सहित वे शिरडी आए. मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण–वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को साई चरणों में डाल दिया. बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया. बच्चे ने आंखे फेर दी और बेसुध हो कर गिर पड़ा. उसके मुंह से झाग निकलने लगा तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं. यह देखकर उसके माता–पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे. बच्चे को कभी–कभी थोड़ी मूर्च्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, लेकिन यह मूर्च्छा दीर्घ काल तक रही. माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुःखग्रसित हो रोने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, जैसे कि एक व्यक्ति, चोरों के डर से भाग कर किसी घर में प्रविष्टि हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े, या एक भक्त मंदिर में पूजन के लिए जाए और वह मंदिर में ही उसके ऊपर गिर पड़े या एक गाय शेर के डर से भागकर किसी कसाई के हाथ लग जाए. तब बाबा ने सान्त्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप न कर, धैर्य धारण करो. बच्चे को अपने निवासस्थान पर ले जाओ. वह आधा घंटे के पश्चात ही होश में आ जाएगा. तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरन्त पालन किया. बाबा के वचन सत्य निकले. जैसे ही उसे बाड़े में लाए कि बच्चा स्वस्थ हो गया और हरिश्चंद परिवार पति, पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया. हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण–वंदना किया. मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे. तब बाबा ने मुस्कराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गईं. जिन्हें विश्वास और धैर्य है, उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे. हरिश्चंद्र एक धनी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए. श्रीमती हरिश्चंद्र पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी. वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी. उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे. उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए.

ईश्वर के समान ही सन्त भी भक्तों के अधीन है. जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा सन्त करते हैं. शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर हरिश्चंद्र परिवार बाबा के समीप मस्जिद में गया और चरण–वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी. बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया. हरिश्चंद्र को पास बुलाकर वे कहने लगे. बापू पहले मैंने तुम्हें दो रुपये दिए थे और अब मैं तुम्हे तीन रुपये देता हूं. उन्हें अपने पूजन में रखकर नित्य इनका पूजन करो. इससे तुम्हारा कल्याण होगा. हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रसाद स्वरुप ग्रहण कर, बाबा को पुनः साष्टांग नमस्कार किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की. उन्हें एक विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूं कि दो रुपये मुझे पहले कब दिये थे.

वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, लेकिन बाबा मौन ही रहे. मुंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन दो रुपयों की समस्या भी उनसे कही. उनकी माता को भी पहले तो कुछ समझ में न आया, लेकिन पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरातन घटना की स्मृति हो आई, जिसने समस्या हल कर दी. उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर साई बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता कई वर्षों पहले अक्कलकोटकर महाराज के दर्शनार्थ गए थे. महाराज पूर्ण सिद्ध, योगी, त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे. तुम्हारे पिता परम भक्त थे. इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई. तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ दो रुपये दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवनपर्यन्त पूजा की. उसके पश्चात्य उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये गुम हो गए. कुछ दिनों के बाद उनकी पूर्ण विसमृति भी हो गई. तुम्हारा सौभाग्य है, जो श्री अक्कलकोटकर महाराज ने साई स्वरप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया. अब भविष्य में जागरुक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर, उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ. साई समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो. माता के मधुर वचनामृत का पान कर हरिश्चंद्र को अत्यन्त हर्ष हुआ. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

समाजवाद का नया चेहरा

माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बहुत धुमधाम से बनाया गया और मनाना भी चाहिए जन्मदिन मनाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन क्या शाही तरीके से जन्मदिन मनाना एक समाजवादी नेता को शोभा देता है? जो अपने को राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदम पर चलने वाला बताता हो. सपा मुखिया के जन्मदिन पर पूरे रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सड़कों पर कालीन बिछाई गई थी. इतना ही नहीं उनके के लिए लंदन से 70 लाख की बग्घी मंगाई गई थी. उस बग्घी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माता प्रसाद और आजम खान के साथ बैठकर पूरे शहर में घूमे और उस दौरान उनके ऊपर फूल बरसाए गए. मुलायम सिंह यादव ने 75 फीट का केक काटा. उनके जन्मदिन के मौके पर शहर में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था. पूरे शहर में उनके स्वागत के लिए गेट भी बनाए गए थे और पैसे भी लुटाए गए. सपा मुखिया को बताना चाहिए कि क्या यही समाजावाद है?

–श्रीनिवास सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

बाबाओं की माया

कबीरपंथी और संतलोक आश्रम के संचालक बाबा रामपाल का जो चेहरा सामने आया है, वो काफी चौकाने वाला है. सतलोक आश्रम की जांच में जो पता चला है, वो उसकी काली करतुतों की पोल खोल रहा है. कोर्ट के आदेश पर उसे पुलिस पकड़ने पहुंची, तो उसने पुलिस के खिलाफ जंग छेड़ दिया. पेट्रोल बम, पत्थर फेकना और बंदुक से पुलिस वालों के ऊपर हमला करना दर्शाता है कि वह एक रैकेट चला रहा था. देश में बाबाओं का नया–नया चेहरा सामने आ रहा है इसमें राजनेताओं का भी हाथ है, जिनके शह पर उनका धंधा फलता–फूलता है. वह चाहे रामपाल हो या कोई अन्य. रामपाल के सतलोक आश्रम में इतनी भारी मात्रा में पेट्रोल बम, बंदूके और कारतूस इतनी मात्रा में कहा सें पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ये ढ़ोगी बाबा देश में सतसंग के नाम पर रैकेट चला रहे हैं और ऐसे ढ़ोगी बाबाओं की और उनके आश्रमों की जांच होनी चाहिए, जिससे उनकी काली करतुतों का काला चिट्ठा सबके सामने आ सके.

–अभिषेक तिवारी, बक्सर, बिहार.

जम्मू–कश्मीर में भी मोदी

कवर स्टोरी–श्रीनगर की बाढ़ मोदी के लिए वरदान(24 नवंबर–30 नवंबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि श्रीनगर की बाढ़ मोदी के लिए वरदान है. जम्मू–कश्मीर में आई भारी बाढ़ के कारण मची तबाही में लोगों की भारी संख्या में जान–माल का नुकसान हुआ. नरेन्द्र मोदी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई बार वहां का दौरा कर उन्हें आश्वासन भी दे चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ के समयभी जम्मू–कश्मीर के लोगों की परेशानियों को जानने के लिए गए थे और पीड़ितों को हर मदद का आश्वासन दिया. बाढ़ के बाद मोदी पीड़ितों की खैरियत जानने के लिए दीपावली के दिन जम्मू–कश्मीर दौरे पर गए और वहां के लोगों को एक बार फिर हर मदद का आश्वासन दिया. इसी बहाने मोदी वहां लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं और जिसका फायदा भाजपा को विधानसभा चुनाव में होगा.

–मुसाफिर सिंह, दरभंगा, बिहार.

आप की चुनौतियां

आलेख–आसान नहीं होगी आप की राह(24 नवंबर–30 नवंबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. यह बिल्कुल सही है कि आप की राह विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है. जब यह पार्टी बनी थी उस समय इस पार्टी में शाजिया इल्मी और विनोद कुमार बिन्नी जैसे कई नेता थे, जो अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं. जब आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता चरम पर थी, तो वो 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर थी. इस समय आपके कई सारे नेता पार्टी झोड़कर जा चके हैं, जिसमें शाजिया इल्मी, बिन्नी, धीर जैसे नेता शामिल है. इसलिए होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की राह आसान नहीं होगी और उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई सारी चुनौतियों से निपटना होगा. नवीन चौहान का आलेख काफी तथ्यपरक है.

–नवनीत कालरा, सीलमपुर, दिल्ली.

प्रधानमंत्री से सवाल

जब तोप मुकाबिल हो–विस्तार–फेरबदल से उपजे सवाल(24 नवंबर–30 नवंबर 2014)पढ़ा काफी अच्छा है. नरेन्द्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, संतोष भारतीय ने सही कहा है कि वह उसी को मंत्री बनाएंगे, जिन पर उनका पूरा विश्वास है. मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से कई सवाल खड़े हुए हैं. जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाना और स्वास्थ्य मंत्रालय से हर्षवर्धन को हटाना. यह सवाल उठता है कि डॉ हर्षवर्धन को क्यों हटाया गया. सुरेश प्रभु, राजीव प्रताप रुडी को जिस विषय की जानकारी है वह मंत्रालय न देकर उन्हें दूसरे मंत्रालय दिए गए. मोदी का मंत्रिमंडल है वह जिसे चाहें उसे मंत्री बनाए, लेकिन लोग इस सवाल का जवाब जानना ही चाहेंगे.

–कमल किशोर वर्मा, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

विश्वसनीय समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र को मैं चार सालों से पढ़ रहा हुं, लेकिन चौथी दुनिया हमेशा सटीक और सही जानकारी देता है. चौथी दुनिया ने कोयला घोटाला जैसे कई घोटाले उजागर किए हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र ने कभी अपने मुल्यों से समझौता नहीं किया यही उसकी पहचान है, लेकिन बड़े–बड़े समाचार पत्र इस समय अपने मुल्यों को खो चुके हैं. इसमें प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद नई–नई जानकारियां हासिल होती हैं. संतोष भारतीय द्वारा लिखा गया जब तोप मुकाबिल हो, कमल मोरारका का आलेख और मनीष कुमार के आलेख समेत चौथी दुनिया की सभी खबरें तथ्यपरक होती हैं. आशा है कि चौथी दुनिया में आगे भी ऐसी ही सामग्री पढ़ने को मिलती रहेंगी.

–उमाशंकर यादव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

स्वामी विवेकानंद

बात उस समय की है, जब विवेकानंद जी को शिकागो की धर्मसभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था. वे भारत के प्रथम संत थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया था. विवेकानंद के गुरू रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो चुका था. इसलिए इस महती यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने गुरू मां शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी से आशीर्वाद लेने वे गुरू मां के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए बोले, मां, मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है. मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं. मां शारदा ने कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना. मैं पहले देख लूंगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं? और बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती हूं. विवेकानंदजी सोच में पड़ गए, मगर गुरु मां के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए. मां शारद रसोईघर में थीं. विवेकानंदजी ने कहा, मां मैं आशीर्वाद लेने आया हूं. ठीक है आशीर्वाद तो तुझे मैं सोच समझकर दूंगी. पहले तू मुझे वो चाकू उठाकर दे दे मुझे सब्जी काटनी है. विवेकानंदजी ने चाकू उठाया और विनम्रता पूर्वक मां शारदा की ओर बढ़ाया. चाकू लेते हुए ही मां शारदा ने अपने आशीर्वचनों से स्वामी विवेकानंद बोलीं, जाओ नरेन्द्र मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं. तुम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे. तुम्हारी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं रहा है. स्वामीजी हतप्रभ. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरू मां के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया? शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरू मां से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? तुम्हारा मन देखने के लिए. मां शारदा ने कहा, प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में समो लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है. मगर तुमने ऐसा नहीं किया. तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी और मूठवाला सिरा मेरी तरफ बढ़ाया. यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेलकर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है. वह भूल से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता. अगर तुम साधुमन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू की मूठ होती, फल नहीं. ■

शिक्षा–हमेशा दूसरों के कष्ट को दूरे करने की कोशिश करनी चाहिए.

> सरकार, प्रकाशक और लेखक की भूमिका सबको ज्ञात है. टेलिकॉम यानी फोन और उसमें लोड सॉफ्टवेयर, सर्चे इंजन, जहां जाकर कोई भी अपनी मनपसंद रचना को ढूंढ सकता है. पाठकीयता के निर्माण का एक पहलू डिवाइस मेकर भी हैं. डिवाइस यथा किंडल और आई– प्लेटफॉर्म, जहां रचनाओं को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है. प्रकाशक पाठकीयता बढ़ाने और नए पाठकों के लिए अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर रचनाओं को उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाता है.

पुस्तक मेला नहीं, सांस्कृतिक आंदोलन

अनंत विजय

अगर किसी पुस्तक मेले में एक दिन में एक लाख लोग पहुंचते हों, तो इससे किताबों के प्रति प्रेम को लेकर एक आश्वस्ति होती है. यही हुआ हाल ही में संपन्न पटना पुस्तक मेला में. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित इस पुस्तक मेला के बीच आए एक रविवार को वहां पहुंचने वालों की संख्या एक लाख के पार चली गई. इसके अलावा पुस्तक मेला से जुड़े लोगों का अनुमान है कि दस दिनों में पुस्तक मेला में किताबों की बिक्री का आंकड़ा भी क़रीब छह करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया. पटना पुस्तक मेला में ज़्यादातर किताबें हिंदी की थीं, लिहाजा इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है. एक तरफ़ हिंदी में साहित्यिक कृतियों की बिक्री कम होने की बात हो रही है और उस पर चिंता जताई जा रही है, वहीं साहित्येतर किताबों में पाठकों की बढ़ती रुचि को रेखांकित किया जा रहा है. पटना पुस्तक मेला इस लिहाज से अन्य पुस्तक मेलों से थोड़ा अलग है कि यहां किताबों की दुकानों के अलावा सिनेमा, पेंटिंग, नाटक आदि पर भी विमर्श होता है. इस साल तो पटना पुस्तक मेला में संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से देशज नामक एक सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ, जिसमें मशहूर पंडवानी लोक नाट्य गायिका तीजन बाई से लेकर मणिपुर और कश्मीर की नाट्य मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी. कश्मीर का गोसाईं पाथेर जो है, वह वहां की भांड पाथेर परंपरा का नाटक है, जिसे कश्मीर घाटी के भांड कलाकार लंबे समय से मंचित करते आ रहे हैं. बिहार के दर्शकों के लिए यह एकदम नया अनुभव था. इन नाटकों की प्रस्तुति इतनी भव्य थी कि भाषा भी आड़े नहीं आ रही थी.

दरअसल, अगर हम देखें, तो पटना पुस्तक मेला ने बिहार में पाठकों को संस्कारित करने का काम भी किया. बिहार में एक सांस्कृतिक माहौल होने के पीछे पटना पुस्तक मेला का बड़ा हाथ है. पिछले दो सालों से पटना पुस्तक मेला को नज़दीक से देखने का अवसर मिला है. वहां जाकर लगा कि एक ओर जहां तमाम लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य के मीना बाज़ार में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां साहित्य एवं साहित्यकारों को उपभोक्ता वस्तु में तब्दील करने का खेल खेला जा रहा है, जहां प्रायोजकों के हिसाब से सत्र एवं वक्ता तय किए जाते हैं, वहीं पटना पुस्तक मेला देश की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे नए पाठकों तक पहुंचाने का उपक्रम कर रहा है. संवाद कार्यक्रमों के ज़रिये पाठकों को साहित्य की विभिन्न विधाओं की चिंताओं और उसकी नई प्रवृत्तियों से अवगत कराने का काम किया जा रहा है. भगवान दास मोरवाल के नए उपन्यास–नरक मसीहा के विमोचन के मौक़े पर एक वरिष्ठ आलोचक ने आलोचना में उठाने–गिराने की प्रवृत्ति को रेखांकित किया, तो इक्कीसवीं सदी की पाठकीयता पर भी जमकर चर्चा हुई. पाठकीयता के संकट के बीच उसे बढ़ाने के उपायों पर रोशनी डालने के साथ ही सोशल मीडिया में हिंदी के साहित्यकारों की कम उपस्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई. प्रकाशन कारोबार में आ रहे बदलावों पर हार्पर कालिंस की मुख्य संपादक कार्तिका वीके ने विस्तार से पाठकों को बताया. इस मौक़े पर पटना पुस्तक मेला के आयोजक सीडीआर के अध्यक्ष रत्नेश्वर एवं रंगकर्मी अनीस अंकुर भी मौजूद थे.

हिंदी साहित्य और पाठकीयता पर हिंदी में लंबे समय से चर्चा होती रही है. लेखकों और प्रकाशकों के बीच पाठकों की संख्या को लेकर लंबे समय से विवाद होता रहा है. साहित्य सृजन कर रहे लेखकों को लगता है कि उनकी कृतियां हज़ारों में बिकती हैं और प्रकाशक घपला करते हैं. वे बिक्री के सही आंकड़े नहीं बताते. इसी तरह प्रकाशकों का मानना है कि साहित्य के पाठक लगातार कम होते जा रहे हैं और साहित्यिक कृतियां बिकती नहीं हैं. दोनों के तर्क कुछ विरोधाभासों के बावजूद अपनी–अपनी जगह सही हो सकते हैं. दरअसल, साहित्य और पाठकीयता, यह विषय बहुत गंभीर है और उतने ही गंभीर मंथन की मांग करता है. अगर हम देखें, तो आज़ादी के पहले हिंदी में दस प्रकाशक भी नहीं थे और इस वक्त एक अनुमान के मुताबिक, तीन सौ से ज़्यादा प्रकाशक साहित्यिक कृतियां छाप रहे हैं. प्रकाशन जगत के जानकारों के मुताबिक, हर साल हिंदी की क़रीब दो से ढाई हज़ार किताबें छपती हैं. अगर पाठक नहीं हैं, तो किताबें छपती क्यों हैं? यह एक बड़ा सवाल है, जिससे टकराने के लिए न तो लेखक तैयार हैं और न प्रकाशक.

क्या लेखकों एवं प्रकाशकों ने अपना पाठक वर्ग तैयार करने के लिए कोई उपाय किया? क्या लेखकों ने एक खास ढर्रे की रचनाएं लिखने के अलावा किसी अन्य विषय को अपने लेखन में उठाया? अगर इस बिंदु पर विचार करते हैं, तो कम से कम हिंदी साहित्य में एक खास किस्म का सन्नाटा नज़र आता है. हिंदी के लेखक बदलते जमाने के साथ अपने लेखन को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं.

इक्कीसवीं सदी में पाठकीयता पर जब हम बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि हमने इस सदी में पाठक बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किए. अगर हम साठ से लेकर अस्सी के दशक को देखें, तो उस वक्त पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने हमारे देश

में एक पाठक वर्ग तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. पीपीएच ने उन दिनों एक खास विचारधारा की किताबें छापकर सस्ते में बेचना शुरू किया. हर छोटे से लेकर बड़े शहर तक रूस के लेखकों की किताबें सहज, सस्ती और हिंदी में उपलब्ध होती थीं. उसके इस प्रयास से हिंदी में एक विशाल पाठक वर्ग तैयार हुआ. सोवियत रूस के विघटन के बाद जब पीपीएच की शाखाएं बंद होने लगीं, तो न हिंदी के लेखकों ने और न हिंदी के प्रकाशकों ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश की. प्रतिबद्ध साहित्य पढ़वाने की जिद और तिकड़म ने पाठकों को दूर किया. फॉर्मूला–बद्ध रचनाओं ने पाठकों को निराश किया. नई सोच और नए विचार सामने नहीं आ पाए. विचारधारा ने ऐसी गिरोहबंदी कर दी कि नए विचार और नई सोच को सामने आने ही नहीं दिया गया. जिसने भी आने की कोशिश की, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सुनियोजित तरीके से हाशिये पर रख दिया गया. किसी को कलावादी कहकर, तो किसी को कुछ अन्य विशेषण से नवाज कर. इस प्रवृत्ति के शिकार हुए सबसे बड़े लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और रामधारी सिंह दिनकर थे. इन दोनों लेखकों का अब तक उचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है.

दूसरा नुक़सान यह हुआ कि विचारधारा और प्रतिबद्धता के आतंक में न तो नई भाषा गढ़ी जा सकी और न उस तरह के विषयों को छुआ गया, जो समय के साथ बदलती पाठकों की रुचि का ध्यान रख सकते. यहां कुछ लेखकों को विचारधारा के आतंक शब्द पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह तथ्य है कि साहित्य एवं विश्वविद्यालयों से लेकर साहित्य अकादमियों तक एक खास विचारधारा के पोषकों का आतंक था. जन और लोक की बात करने वाले इन विचार पोषकों की आस्था न तो उससे बने जनतंत्र में है और न लोकतंत्र में. लेखक संघों का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी किसी ने विचारधारा पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की, उसे संगठन बदर कर दिया गया. ये बातें विषय से इतर लग सकती हैं. मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इससे

हिंदी साहित्य और पाठकीयता पर हिंदी में लंबे समय से चर्चा होती रही है. लेखकों और प्रकाशकों के बीच पाठकों की संख्या को लेकर लंबे समय से विवाद होता रहा है. साहित्य सृजन कर रहे लेखकों को लगता है कि उनकी कृतियां हज़ारों में बिकती हैं और प्रकाशक घपला करते हैं. वे बिक्री के सही आंकड़े नहीं बताते.

पाठकीयता को क्या लेना–देना है. संभव है कि इस प्रसंग का पाठकीयता से प्रत्यक्ष संबंध न हो, लेकिन इसने परोक्ष रूप से पाठकीयता के विस्तार को बाधित किया है. वह इस तरह से कि अगर किसी ने विचारधारा के दायरे से बाहर जाकर विषय उठाए और उन्हें पाठकों के सामने पेश करने की कोशिश की, तो उसे हतोत्साहित किया गया. नतीजा यह हुआ कि साहित्य से नवीन विषय छूटते चले गए और पाठक एक ही विषय को बार–बार पढ़कर उबने लगे. साहित्यकारों ने पाठकों की बदलती रुचि का ख्याल नहीं रखा. वे उसी सोच को दिल से लगाए बैठे रहे कि हम जो लिखेंगे, वही तो पाठक पढ़ेंगे. मैंने अभी हाल में लेखकों की इस सोच को तानाशाही कह दिया, तो बखेड़ा खड़ा हो गया. पाठकों की रुचि और बदलते मिजाज का ध्यान न रखना तो एक तरह की तानाशाही है ही.

दरअसल, नए जमाने के पाठक बेहद मुखर और अपनी रुचि को हासिल करने के लिए बेताब हैं. नए पाठक इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि वे किस प्लेटफॉर्म पर कोई रचना पढ़ेंगे. अगर अब गंभीरता से पाठकों की बदलती आदत पर विचार करें, तो पाते हैं कि उनमें काफी बदलाव आया है. पहले पाठक सुबह उठकर अख़बार का इंतज़ार करता था और आते ही उसे पढ़ता था, लेकिन अब वह अख़बार आने का इंतज़ार नहीं करता, ख़बरें पहले जान लेना चाहता है. ख़बरों के विस्तार की रुचि वाले पाठक अख़बार अवश्य देखते हैं. ख़बरों को जानने की चाहत उनसे इंटरनेट सर्फ कराते हैं. इसी तरह पहले पाठक किताबों का इंतज़ार करता था. किताबों की दुकानें ख़त्म होते चले जाने और इंटरनेट पर कृतियों की उपलब्धता बढ़ने से पाठकों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया. हो सकता है कि अभी किंडल और आई–फोन या आई–पैड पर पाठकों की संख्या कम दिखाई दे, लेकिन जैसे–जैसे देश में इंटरनेट का घनत्व बढ़ेगा, वैसे–वैसे पाठकों की इस प्लेटफॉर्म पर संख्या बढ़ती जाएगी. इसके अलावा न्यूज हंट जैसे ऐप हैं, जहां बेहद कम क़ीमत पर हिंदी साहित्य की कई महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं. यह बात कई तरह के शोध के नतीजों के रूप में सामने आई है. दरअसल, अगर हम देखें, तो पाठकीयता के बढ़ने–घटने के लिए कई कड़ियां ज़िम्मेदार हैं. अगर हम पाठकीयता को एक व्यापक संदर्भ में देखें, तो इसके लिए कोई एक चीज ज़िम्मेदार नहीं है. यह एक पूरा ईको सिस्टम है, जिसमें सरकार, टेलिकॉम, सर्च इंजन, लेखक, डिवाइस मेकर, प्रकाशक, मीडिया एवं मीडिया मालिक शामिल हैं. इन सबको मिलाकर पाठकीयता का निर्माण होता है.

सरकार, प्रकाशक और लेखक की भूमिका सबको ज्ञात है. टेलिकॉम यानी फोन और उसमें लोड सॉफ्टवेयर, सर्चे इंजन, जहां जाकर कोई भी अपनी मनपसंद रचना को ढूंढ सकता है. पाठकीयता के निर्माण का एक पहलू डिवाइस मेकर भी हैं. डिवाइस यथा किंडल और आई– प्लेटफॉर्म, जहां रचनाओं को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है. प्रकाशक पाठकीयता बढ़ाने और नए पाठकों के लिए अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर रचनाओं को उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाता है. पाठकीयता बढ़ाने में मीडिया का भी बहुत योगदान रहता है. साहित्य को लेकर हाल के दिनों में मीडिया में एक खास किस्म की उदासीनता देखने को मिली है. इस उदासीनता तो दूर करके एक उत्साही मीडिया की दरकार है. हिंदी साहित्य जगत को पाठकीयता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि वह इस ईको सिस्टम का संतुलन बरकरार रखे. इसके अलावा लेखकों और प्रकाशकों को नए पाठकों को साहित्य की ओर आकर्षित करने के लिए नित नए उपक्रम करने होंगे. पाठकों के साथ लेखकों का जो संवाद नहीं हो रहा है, वह पाठकीयता की प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है. लेखकों को चाहिए कि वे इंटरनेट के माध्यम से पाठकों के साथ जुड़ें और उनसे अपनी रचनाओं पर फीडबैक लें.

फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की लेखिका ई एल जेम्स ने ट्राइलॉजी लिखने से पहले इंटरनेट पर एक सीरीज लिखी थी और बाद में पाठकों की राय पर उसे उपन्यास का रूप दिया. उसकी सफलता अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है. इन सबसे ऊपर हिंदी के लेखकों को नए–नए विषय भी ढूंढने होंगे. जिस तरह हिंदी साहित्य से प्रेम गायब हो गया है, उसे भी वापस लेकर आना होगा. आज भी पूरी दुनिया में प्रेम कहानियों के पाठक सबसे ज़्यादा हैं. हिंदी में बेहतरीन प्रेम कथा की बात करने पर धर्मवीर भारती का उपन्यास–गुनाहों के देवता और मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास–कसप ही याद आते हैं. हाल में संपन्न हुए पटना पुस्तक मेला से यह संकेत मिला कि पढ़ने की भूख है. वहां एक दिन में एक लाख लोगों के पहुंचने से उम्मीद तो बंधती ही है. ज़रूरत इस बात की है कि यह उम्मीद कायम रखते हुए इसे नई ऊंचाई दी जाए. पटना के अलावा कोलकाता पुस्तक मेला में भी सांस्कृतिक विरासत बचाने का उपक्रम होता है. साहित्य को उपभोग की वस्तु में तब्दील करते विभिन्न लिटरेचर फेस्टिवल्स के बीच पुस्तक मेला अपनी अलग पहचान पर कायम है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित एक कलाकार

सुजीत मलिक

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

आज शहरी समाज में लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हम प्रकृति व हरियाली से दूर आ गए हैं, लेकिन इसी के साथ एक एहसास भी है जो लोगों को भूलने भी नहीं देता है कि हम मिट्टी के उपर खड़े हैं. एक कलाकार भी ऐसा ही महसूस करता है और कुछ नया करने की ठान लेता है. दिल्ली के डी.एल.एफ. गाजियाबाद में रहने वाले सुजीत मलिक भी ऐसे ही एक कलाकार हैं, जिन्होंने छोटी से जगह और छतों पर पेड़ पौधे लगा कर प्रकृति व हरियाली को शहरीकरण के इस दौर में एक नए रूप में पारिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं.

रूफ टॉप्स एण्ड ग्राउंड्स एक प्रयोग है, जहां पर इंसान और हरियाली के संपर्क को टटोलने के लिए कई जीवित कलाओं का उपयोग किया जा रहा है. डी.एल.एफ. गाजियाबाद के किनारे की छोटी–सी जगह डी–1 ब्लॉक में सुजीत मलिक ने कई स्थानीय परिवार समेत एक साथ एक ही समय में अपने घर के छत को अपना आशियाना बना लिया है. हमेशा वीरान रहने वाली छतें अभी जीवित बनने लगी हैं. इस प्रोजेक्ट का पहला कार्य था एक फालतू समझे जाने वाले पेड़ को छत पर लगाना. सभी ने पूछा कि इस पेड़ को क्यों लगाया? इस प्रश्न से यहां पर कलाकार सुजीत मलिक को प्रकृति सेवा के बारे में बताने का एक मौका मिल गया. सुजीत ने लोगों को पेड़–पौधों व प्रकृति सेवा के गुण बताने लगे और धीरे–धीरे छतों पर पेड़ बढ़ने लगे. उसके साथ–साथ लोगों की बातचीत में भी बदलाव आने लगा. सुजीत के घर के बगल की जमीन पिछले 20 वर्षों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई था. इसमें नेवला, सांप, चूहा, गिरगिट का बसेरा हो गया था. सुजीत की पहल पर सारे लोग इसे साफ करने को तैयार हो गए. यहां पर स्थानीय लोगों की मदद से कई सारे गड्ढे खोदे गए और पौधारोपण का काम हुआ.

रूफ टॉप्स एण्ड ग्राउंड्स एक प्रयोग है, जहां पर इंसान और हरियाली के संपर्क को टटोलने के लिए कई जीवित कलाओं का उपयोग किया जा रहा है. डी.एल.एफ. गाजियाबाद के किनारे की छोटी-सी जगह डी-1 ब्लॉक में सुजीत मलिक ने कई स्थानीय परिवार समेत एक साथ एक ही समय में अपने घर के छत को अपना आशियाना बना लिया है.

सुजीत ने इस इलाके में कई अलग–अलग कम्यूनिटि आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया. इसमें एक था कैलेंडर प्रोजेक्ट. कैलेंडर प्रोजेक्ट एक परिवार के परिचय से दूसरे परिवार फिर तीसरे परिवार, ऐसे–ऐसे करके बारह परिवार तक सम्पर्क बढ़ता चला गया. फिर स्थानीय लोगों के बीच साप्ताहिक मुलाकात होनी शुरू हुई. इस तरह, स्थानीय लोगों को जोड़ कर सुजीत मलिक ने छत पर प्लांटेशन के काम को कॉलोनी के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया.

बहरहाल, सुजीत इससे आगे एक नया ग्रीन कमांडो ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसके तहत नए बच्चों को शुरू से ही खेती–किसानी व पर्यावरण के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके. इसमें सात साल के बच्चों से लेकर बारह साल के बच्चों को पांच साल तक लगातार, सप्ताह में एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके तहत दिल्ली के आस–पास के इलाके में इन बच्चों को ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण दे कर, खुद उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा व प्रशिक्षण दिया जाएगा. कहते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और कृषि भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. लेकिन दुख की बात है कि आज लोग कृषि कार्य से दूर होते जा रहे हैं. ऐसे में अगर बच्चों में शुरू से ही खेती के बारे में दिलचस्पी पैदा किया जा सके तो संभव है कि आने वाले समय में ये बच्चें किसानी कार्य को गरिमापूर्ण कार्य बना दें. ■

feedback@chauthiduniya.com

नोकिया का एंड्रॉयड लॉलीपॉप वाला टैबलेट एन-1

नोकिया ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर नया टैबलेट एन–1 लॉन्च किया है और इसके साथ ही उसने एक बार फिर मोबाइल उपकरण क्षेत्र में कदम रखा है. नोकिया का मोइक्रोसॉफ्ट को अपना उपकरण बेचने के बाद उसका यह पहला टैबलेट एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लॉलीपॉप पर आधारित है. एप्पल आइफोन बनाने वाली फॉक्सकान की इंजीनियरिंग, बिक्री और ग्राहक सेवा से लेकर पूरे कारोबार के लिए जिम्मेदार होगी. इसमें देनदारी और वारंटी लागत शामिल है. कंपनी ने कहा कि एन–1 एंड्रॉयड टैबलेट के साथ नोकिया ब्रांड को उपभोक्ता के लिए दोबारा लाकर खुश है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आसान बनाने में सहयोग करेंगे. इस टैबलेट की स्क्रीन 7.90 इंच की है, जो 2048गुणा1536 पिक्सल का रेजोल्यूशन देगी. इसका प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज का है. इसमें रैम 3 जीबी की रैम है और साथ ही आपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप पर आधारित है. इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है. इसकी बैटरी 5300 एमएएच की है. इसमें नोकिया का एन–1 टैबलेट पहले चीन में लगभग 15000 रुपये में मिलेगा और इसमें टैक्स शामिल नहीं होगा. उसके बाद इसे धीरे–धीरे अन्य बाजारों में पेश किया जाएगा. ■

छल्ला ढूंढकर देगा आपका मोबाइल फोन

कभी हम अपना मोबाइल फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं और ऐसे में फोन खोने का भी डर रहता है. अगर आप अपना मोबाइल फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं और आपका कोई करीबी उसे छिपाकर आपको परेशान करता है, तो अब आपको परेशान न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा औजार आ गया है, जो आपके फोन को कहीं भी हो तुरंत ढूंढ लाएगा. मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने एक की–चैन (चाबी का छल्ला) लॉन्च किया है, जो मोबाइल को ढूंढ़ने में आपकी मदद करेगा. यही नहीं, अगर आपकी चाबी खो जाए, लेकिन मोबाइल पास में ही हो तो मोबाइल चाबी और इस छल्ले को ढूंढ़ लेगा. इस कीलिंक को आप अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर सकते हैं. इसके बाद जब भी आप अपना मोबाइल कहीं रखकर भूल जाएं तो इस छल्ले की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं और अगर छल्ला–चाबी ही खो जाए तो उसे स्मार्टफोन की मदद से पा सकते हैं. इस कीलिंक यानी छल्ले की सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत 1500 रुपये रखी गई है. इसे मोटोरोला.कॉम से खरीदा जा सकता है. कंपनी के अनुसार इस छल्ले की बैटरी एक साल तक चलती है और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से साधारण कॉइन सेल बैटरी से बदला जा सकता है. दरअसल यह कीलिंक एक छोटी ब्लूटुथ डिवाइस है, जिसे आप अपने एंड्रॉयड फोन 4.3 या उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस 7.1 या उससे आगे के वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल प्लेस्टोर या एप्पल एप्प स्टोर से मोटोरोला कनेक्ट एप्प डाउनलोड करना होगा. यह कीचेन 100 फीट की दूरी तक आपके मोबाइल को ढूंढ सकती है. ■

जियोमी ने लॉन्च किया रेडमी नोट

जियोमी 4 जी स्मार्टफोन की भी डिस्प्ले 5.5 इंच की है और इसका प्रोससेर 1.6 गीगाहर्ट्ज का है. इसका रैम भी 2 जीबी का है और इसकी भी स्टोरेज क्षमता 8 जीबी की है.

जियोमी ने नए स्मार्टफोन रेडमी नोट को लॉन्च कर दिया है. रेडमी नोट भारत में एमआई की तरफ से लाया गया पहला 4जी फोन है. इसे विशेषरूप तौर पर भारत में 4जी नेटवर्क के लिए लॉन्च किया गया है. इसे भारती एयरटेल के साझेदारी में लाया गया है. एयरटेल के साथ साझेदारी के तहत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई के चुनिंदा एयरटेल स्टोर्स के माध्यम से रेडमी नोट 4 की बिक्री की जाएगी. फोन की खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. जियोमी रेडमी नोट में 5.5 इंच का डिस्प्ले है. इसका प्रोसेसर 1.7 गीगाहर्ट्ज का है और साथ ही इसमें 2जीबी की रैम दी गई है. इस नोट में स्टोरेज की क्षमता 8 जीबी की है. इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. यह नोट एंड्रॉयड 4.3 जैली बीन आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. इसकी बैटरी की क्षमता 3100 एमएएच की है. जियोमी रेडमी नोट की कीमत 8,999 रुपये रखी गई है.

जियोमी 4 जी स्मार्टफोन की भी डिस्प्ले 5.5 इंच की है और इसका प्रोससेर 1.6 गीगाहर्ट्ज का है. इसका रैम भी 2 जीबी का है और इसकी भी स्टोरेज क्षमता 8 जीबी की है. इसका भी रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापकिस्ल है. यह 4 जी नोट एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है, लेकिन इसकी भी बैटरी 3100 एमएएच की है. रेडमी नोट 4जी स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपये है. ■

फरारी की सुपर लग्जरी कारें

फरारी भारत में अमीर लोगों के लिए शानदार कारों की श्रृखला लॉन्च केरगी. ये कारें बेहद मंहगी होंगी. कंपनी केलिफोर्निया टी कनर्वटिबल, वी–12एफएफ, 458 इटालिया, एफ12बर्लिनेट्टा, 458 स्पाइडर और ला फरारी कारों को भारत में बेचेगी. इन कारों की कीमत साढ़े तीन करोड़ से लेकर सात करोड़ तक की रेंज में होंगी. इन कारों का सीधे आयात होगा, जिसके कारण भारत में इनकी कीमत अधिक होगी. भारत में ऐसी लग्जरी कारों पर 170 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी है. फरारी दुबई से ही अपने भारतीय ऑपरेशंस को चलाती है और वह ऐसे एजेंट रखना चाहती है जो देश में लग्जरी कारें मंगाते हों. बेहद महंगी होने की वजह से भारत में सुपर लग्जरी कारों की उतनी बिक्री नहीं है, लेकिन फिर भी यह एशिया प्रशांत के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां दो करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की कारें बिकती हैं. ■

इन कारों की कीमत साढ़े तीन करोड़ से लेकर सात करोड़ तक की रेज में होंगी. इन कारों का सीधे आयात होगा, जिसके कारण भारत में इनकी कीमत अधिक होगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> वॉल्श के पद छोड़ने के बाद नए सिरे से कोच की तलाश शुरू हो गई है. वॉल्श ने ऐसे समय में कोच का पद छोड़ा है जब देश चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 6 से 14 दिसंबर तक खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, ओलंपिक चैंपियन जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और पाकिस्तान की टीमें खेलती दिखाई देंगी. वॉल्स की मौजूदगी और गैर–मौजूदगी का टीम के प्रदर्शन पर कितना और कैसा फर्क पड़ेगा यह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और उसके बाद नज़र आ जाएगा.

कोच टैरी वॉल्श का इस्तीफा

भारतीय टीम जीत की लय कायम रख पाएगी ?

नवीन चौहान

भारतीय हॉकी टीम कुछ दिनों पहले तक एक सुहाना सफर तय कर रही थी. सबसे पहले भारतीय टीम ने इंचियोन में 16 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 2016 में ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक का टिकट पक्का किया. इसके बाद भारतीय टीम विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से उनकी धरती पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज में दो-दो हाथ करने पहुंची. पहले टेस्ट मैच में एशियन गेम्स चैंपियन भारत को 4-0 से करारी हार मिली. लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन वापसी की और मेजबान टीम को बाकी बचे तीनों मैचों में धूल चटा दी और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटते ही टीम को जीत की राह पर लाने वाले कोच टैरी वॉल्श ने वेतन विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया. हालांकि इस्तीफा देने के लिए वॉल्श के ऊपर हॉकी इंडिया ने किसी तरह का दबाव नहीं डाला, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा माहौल बना दिया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. वॉल्श की मांगों पर विचार करने के लिए अजितपाल सिंह, अशोक कुमार और ज़फर इकबाल की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई लेकिन समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वॉल्स कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में नौकरशाही के हस्तक्षेप से परेशान थे. उन्होंने कोच का पद छोड़ने से पहले हॉकी इंडिया के सामने वेतन वृद्धि के अलावा और कुछ अन्य शर्तें रखीं थीं. भारतीय खेल प्रधिकरण (साई) और खेल मंत्रालय वॉल्श की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था. लेकिन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और हॉकी इंडिया से बिगड़ते रिश्तों की वजह से अंततः उन्हें कोच का पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद वॉल्श ने कहा कि वे भारतीय टीम को कोचिंग करते रहने के बारे में उत्सुक हैं. हॉकी इंडिया के प्रमुख नरिंदर बत्रा ने वॉल्श पर अमेरिकी हॉकी टीम के तकनीकि निदेशक के पद पर रहते हुए वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया. इस वजह से दोनों के बीच मतभेद गहरा गए. वॉल्श के इस्तीफा देने के बाद बत्रा ने साई महानिदेशक जिजि थामसन को लिखे पत्र में कहा कि हॉकी इंडिया को अब टेरी वॉल्श की सेवाओं की जरूरत नहीं है और अब वह साई की स्वीकृति से नए मुख्य कोच की तलाश करेगा. इसके बाद उनकी दोबारा नियुक्ति के रास्ते भी बंद हो गए. लेकिन यहां सवाल उठाता है कि नए कोच की नियुक्ति के बाद हॉकी टीम जीत की लय बरकरार रख पाएगी? वॉल्श के पद छोड़ने के बाद नए सिरे से कोच की तलाश शुरू हो गई है. वॉल्श ने ऐसे समय में कोच का पद छोड़ा है जब देश चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 6 से 14 दिसंबर तक खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, ओलंपिक चैंपियन जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और पाकिस्तान की टीमें खेलती दिखाई देंगी. वॉल्स की मौजूदगी और गैर-मौजूदगी का टीम के प्रदर्शन पर कितना और कैसा फर्क पड़ेगा यह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और उसके बाद नज़र आ जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रोलेंट ओल्टमेंस कोच की भूमिका में हैं, हालांकि उनके कोच रहते टीम ने 2013 में मलेशिया में खेले गए एशिया कप में रजत पदक जीता था. फाइनल में भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया से मात मिली थी. इसलिए इस बार भी उनसे आशाएं हैं कि वह मुख्य कोच की गैर-मौजूदगी में कोच की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे पाएंगे. संभावना है कि अगले साल जनवरी तक नए कोच की नियुक्ति हो जाएगी. हॉकी इंडिया ने कुछ लोगों के टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर लिए हैं.

एशियाई खेलों के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत ने भारतीय टीम में नई स्फूर्ति भर दी थी. खिलाड़ियों में एक नया आत्मविश्वास आ गया था कि वे किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं. ऑस्ट्रेलिया में शुरूआत में पिछड़ने के बाद जीत हासिल करना इस बात का सबूत है. टीम के प्रदर्शन में आए सुधार का सबसे ज्यादा श्रेय वॉल्श को ही जाता है. टेरी ने 2012 में ओलंपिक खेलों में 12 वें पायदान पर रही भारतीय टीम के कोच का पद साल 2013 में संभाला था. केवल एक साल में उन्होंने अपने प्रयास से टीम की चाल, चरित्र और चेहरा बदल डाला और एक संघर्ष करती टीम को जीत की पटरी पर वापस ले आए. उनके कोच रहते ही भारतीय टीम 16 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल कर सकी. इसके बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में मात दी.

कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक-फूंक कर पीता है. लेकिन हॉकी इंडिया ऐसा करता दिखाई नहीं दे रहा है. भारतीय टीम साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. यह पहला मौका था कि भारतीय टीम ओलंपिक पदक खेलों में नहीं पहुंच सकी. इसके बाद भारतीय टीम साल 2012 में लंदन ओलंपिक का टिकट आखिरी वक्त में दिल्ली हुए क्वालीफायर टूर्नामेंट जीतकर हासिल किया था. लेकिन लंदन में अंतिम (12 वें) पायदान पर रहने के बाद टीम को एक बार फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी. लेकिन इन बातों पर गौर किए बगैर हॉकी इंडिया ने वॉल्श को जाने दिया. वॉल्स ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मुझे अफसरशाही के निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बैठाने में परेशानी हो रही थी. इसका सीधा सा मतलब है कि हॉकी की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों ने ही हॉकी का बंटाधार किया है. जैसे-तैसे टीम ने फिर से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया तो कोच के काम में टंगड़ी अड़ा दी. वॉल्श ने जो शर्तें रखीं थीं उनको सबके सामने रखना चाहिए था. 62 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई कोच के लिए थकान एक मुद्दा थी और यदि वह 120 दिनों की छुट्टी की बात कह रहे थे, तो इस मसले को बातचीत से हल किया जा सकता था. उन्होंने छुट्टियों के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध रहने की भी बात की थी. वॉल्श मुख्य रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण(साई) के साथ अपने अनुबंध की शर्तों में संशोधन चाहते थे. यदि उन शर्तों को मान लिया जाता तो वह कोच का पद नहीं छोड़ते. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शर्तों के मुताबिक नया अनुबंध नहीं हुआ तो उनके लिए रियो ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए सकारात्मक परिणाम ला पाना मुश्किल हो जाएगा.

भले ही आधिकारिक तौर पर हॉकी राष्ट्रीय खेल न हो, लेकिन हर भारतीय उसे राष्ट्रीय खेल के रूप में ही जानता- समझता है. भले ही वह टीम की हार के लिए ज्यादा संवेदनशील नहीं रह गया है बावजूद इसके हर कोई भारतीय हॉकी के ऐतिहासिक गौरव को लौटता हुआ देखना चाहता है. लेकिन हॉकी इंडिया के प्रशासकों का अहम लोगों की आशाओं और अरमानों से ज्यादा बड़ा हो गया है. हॉकी लीग के शुरू होने के बाद हॉकी इंडिया पैसे के लिए भी मोहताज नहीं रह गया है. यह कड़वा सच है कि खिलाड़ियों और कोचों से ज्यादा पैसा हॉकी इंडिया के प्रशासकों पर खर्च होता है. यदि बात खिलाड़ी और कोच के वेतन वृद्धि की आती है तो फंड की कमी की बात सामने आड़े आ जाती है. यदि वेतन को परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है तो यह बेमानी है. हर कोई अपनी मेहनत के बदले रिवॉर्ड चाहता है. यदि वॉल्श ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है. यदि मांगे जायज हैं और उनसे भारतीय हॉकी का फायदा हो सकता है तो इन बातों को अहम पर नहीं लेना चाहिए. पूर्व कोच माइकल नॉब्स वेतन के रूप में 11000 डॉलर लेते थे. वॉल्स को 12000 डॉलर वेतन के रूप में दिए जाते हैं. अब जिस किसी को भी कोच के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो वह भी कम से कम वॉल्श के वेतन के बराबर ही लेगा. लेकिन यहां इस बात की गारंटी नहीं होगी कि उसके बाद टीम जीत का सिलसिला बरकरार रख सकेगी. नया कोच नए सिरे से टीम की तैयारी करवाएगा उसे खिलाड़ियों को समझने में और उनके साथ तालमेल बैठाने में भी वक्त लगेगा. ऐसे में ओलंपिक से पहल वॉल्श को जाने देना बड़ी भूल है. हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने अपने अहम के लिए टीम का बंटाधार करवाने की ठान ली है. ■

navinonline2003@gmail.com

सायना दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनना चाहती हैं

भारत की बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने कहा कि वह दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनना चाहती हैं और वह इसके लिए वह प्रयासरत भी हैं. चाइना ओपन खिताब जीतकर साइना विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची सायना ने कहा कि मुझे खुशी है कि तीन खिताब जीतकर मैं नौवें से चौथे नंबर तक पहुंची. अब मेरा इरादा अगले महीने होने वाली दुबई सुपर सीरिज में अच्छा प्रदर्शन करना है. उन्होंने कहा कि वह 2016 रियो ओलंपिक को ध्यान में रखकर अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रही हैं. उन्होंने कहा कि फिट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ओलंपिक पास आ रहे हैं. इसके लिए फिट रहकर शीर्ष तीन चीनी खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा खेलना जरूरी है. मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हराने या उन्हें कठिन चुनौती देने की कोशिश करूंगी और नंबर वन की रैंकिंग हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि दूसरे चीनी खिलाड़ी भी काफी दमदार है. मैं मेहनत करती रहूंगी. कौन जानता है कि कब क्या हो जाए. मैं चौथे नंबर तक पहुंची और उम्मीद है कि कुछ और टूर्नामेंट जीतूंगी तो इसका असर रैंकिंग पर भी पड़ेगा.■

मेसी चैंपियंस लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने

महान फुटबॉल खिलाड़ी लायोनेल मेसी ने चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकार्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने एपोएल निकोसिया के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना 72 वां गोल किया. बार्सीलोना की कप्तानी कर रहे मेसी ने 37 वें मिनट में टीम का दूसरा गोल करते ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मेसी ने राउल का रिकार्ड तोड़ा जिन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 142 मैचों में 71 गोल किए थे. लेकिन उनके प्रतिद्वंदी और पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाल्के भी अब तक 70 गोल कर चुके हैं. इसलिए मेसी के लिए इस रिकॉर्ड को अपने नाम बनाए रखने के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा. साथ ही चोटिल होने से भी बचना होगा. मौका मिलते ही रोनाल्डो उनसे आगे निकल सकते हैं वह भी इस सीजन बेहतरीन फॉर्म में हैं. मेसी ने राउल से 51 मैच कम खेलकर यह रिकार्ड बनाया है. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ला-लीगा का सर्वाधिक गोल करने का टेल्मो जारा का 59 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. मेसी अब तक बार्सिलोना के लिए 289 मैचों में 253 गोल कर चुके हैं. पिछले साल उन्होंने बार्सिलोना की ओर से सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. ■

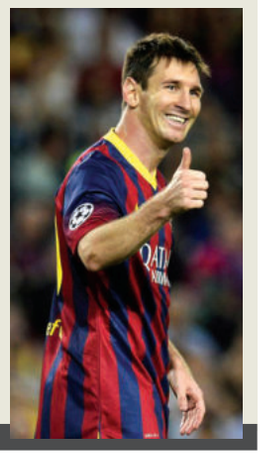

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

aviral
The Foundation of Trust
Presents
RS GROUP
शौर्य
AWARDS FOR
BRAVERY & EXCELLENCE
2014
Powered by
IDI Group
The sign of experience
In Association with
RS GROUP
R S GROUP OF COMPANIES
"SERVICE YOU DESERVE, PEOPLE YOU TRUST"
Live December 16
Venue: Sangeet Natya Academy Gomti Nagar, Lucknow
M4U Entertainment
You Tube
Google
MEDIA PLANNER
Jewel Sponsor
park exports
Co-Organiser
SHAKTI UPPFWA
Co-sponsor
RSG REAL ESTATES INDIA (P) LTD.
"Always At Your Service"
Live on
ETV
Media Associates
न्यूज ग्राउण्ड
सच के पथिक
RED FM 93.5
Bajaate Raho!
net vision
entertainment | information | community
चौथी दुनिया
Pioneer alliance News
गुड हैल्थ
Property Expert
सुमन
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
दब्लैकइंक
मायापुरी
प्रज्ञा प्रभात
tbilive.com
मेट्रो उजाला
visit us : www.m4uworld.com | www.dushyantworld.com

चौथी दुनिया

08 दिसंबर–14 दिसंबर 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

कुशवाहा को चाहिए नंबर एक की कुर्सी

सरोज सिंह

राजनीतिक तौर पर बेहद ही संवेदनशील कुशवाहा समाज इन दिनों सत्ता में अपनी भागीदारी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया है. खासकर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और मनोज सिंह का ग्राफ दिल्ली और बिहार की राजनीति में जिस तेजी से बढ़ा है, उससे यह समाज बहुत ही उत्साहित है. कुशवाहा समाज में अब यह समझ बन गई है कि चाहे कोई भी दल क्यों न हो अब इस समाज की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है. बिहार और दिल्ली के सत्ता समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की ताकत कुशवाहा समाज हासिल कर चुका है इसलिए अब यह वक्त आ गया है कि बिहार की नंबर एक की कुर्सी यानि की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी कुशवाहा को बिठाया जाए. लगभग नौ फीसदी भागीदारी रखने वाला कुशवाहा समाज इसके लिए पार्टी बंधन को तोड़ने के लिए भी तैयार बैठा है. इस बात की बानगी उस समय देखने को मिली जब सूबे के लघु सिंचाई मंत्री मनोज कुमार सिंह ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग भी किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाते हैं तो समाज को हर बंधन तोड़कर उस दल का साथ देना चाहिए.

कुशवाहा समाज के मजबूत स्तंभ मनोज सिंह कहते हैं कि मैं तो दिल की बात कह रहा हूं. अगर कोई दल कुशवाहा को सीएम की दौड़ में आगे नहीं करता है तो फिर नीतीश कुमार ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं और पूरा समाज उनके साथ है. मनोज सिंह कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने आजतक दूसरे लोगों को शिखर तक पहुंचाया है. समाज ने कुर्बानियां दी है और विकास का रास्ता तैयार किया है. अब समय आ गया है कि बिहार की जनता इस समाज को इसका मेहताना दे. मनोज सिंह आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी कुशवाहा समाज का अपमान कर रहे हैं. छह माह में ही उपेंद्र कुशवाहा का विभाग बदल दिया गया जबकि वह अच्छा काम कर रहे थे. मनोज सिंह तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई दल या गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करता है तो फिर पूरे कुशवाहा समाज को उस दल या गठबंधन का ही साथ देना चाहिए. हालांकि वह कहते हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और समाज के हितैषी होने के नाते वह ऐसा बोल रहे हैं. मनोज सिंह कहते हैं कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं. मैं तो बस इतना चाहता हूं कि कुशवाहा समाज का कोई नुमांइदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. उधर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा समाज के अंदर बन रही इस तरह की सोच पर कहते हैं कि शुरू से ही इस समाज को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली है इसलिए समाज चाहता है कि उसका नुमाइंदा आगे जाए ताकि समाज की परेशानियों को सुलझाया जा सके. मुख्यमंत्री के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सवाल किसी पद का नहीं है और न ही सवाल किसी खास समाज का है. असली सवाल है कि लाख कुर्बानियां देने के बावजूद जो समाज सत्ता की हिस्सेदारी में किसी वजह से छूट गए हैं वैसे समाज को आगे करना होगा. हमारा सपना समरस समाज का निर्माण है और यह तभी संभव है जब हर किसी को उचित भागीदारी मिले. सूबे का नेता कौन हो इसका फैसला तो बिहार की साढ़े दस करोड़ जनता को करना है. उल्लेखनीय है कि इस समय हर दल में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चिंतन मनन जारी है. नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे आने के बाद एक बेदाग छवि और कुशल प्रशासक के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजी से उभरने लगे हैं.

यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा चेतना मंच बनाकर अपने चार मंत्रियों और अपने भरोसेमंद सहयोगी निरंजन कुशवाहा उर्फ पप्पू जी को पूरे बिहार के दौरे पर लगा दिया गया है. संसाधन की कोई कमी नहीं है. यहां तक कि हेलिकाप्टर तक का प्रयोग किया जा रहा है. निरंजन पप्पू कहते हैं कि कुशवाहा समाज पूरी तरह जाग चुका है और उचित समय पर उचित निर्णय लेगा. कुशवाहा चेतना मंच के बैनर तले चल रहे कार्यक्रम को पूरे बिहार में भारी समर्थन मिल रहा है. जानकार बताते हैं कि कुशवाहा समाज की यह बैचेनी यूं ही नहीं है. समाज में बड़ी भूमिका निभाने वाले लगभग हर समाज के नुमांइदे नंबर एक की कुर्सी पर बैठ चुके हैं. बड़ी तादाद में होने और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद कुशवाहा समाज अभी तक नंबर एक की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है. बिहार सरकार के मंत्री मनोज सिंह अगर दल के दायरे से बाहर जाकर किसी कुशवाहा को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे उनकी पीड़ा आसानी से समझी जा सकती है. कुशवाहा समाज को लग रहा है कि अब सही वक्त आ गया है और लोहा गरम है इसलिए अभी चोट करना ही होशियारी है. कुशवाहा समाज के अंदर अगर इस समय जरूरत से ज्यादा राजनीतिक बैचेनी है तो इसकी वजह भी इसी पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है.■

feedback@chauthiduniya.com

शाहाबाद के कुशवाहा मतों पर दलों की तिरछी नजर

ममता चौहान

शाहाबाद प्रक्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां हमेशा परवान पर रहती है. परंतु हाल के दिनों में जिस तरह से राज्य के सत्ताधारी दल जदयू, केन्द्र के सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से यहां गतिविधियां बढ़ाई गई, उसे देख लगता है कि इन दलों की तिरछी नजर शाहाबाद के कुशवाहा मतों पर लगी हुई हैं. जहां पहले से हीं रालोसपा सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पैठ बना चुके हैं. यह दिगर बात है कि गत लोकसभा चुनाव में जदयू छोड़कर राजद में गए श्री भगवान कुशवाहा आरा से और फिर बसपा छोड़कर जदयू में गए श्याम लाल कुशवाहा बक्सर से चुनाव हार गए. परंतु इन चुनावों में शाहाबाद के तीन प्रमुख संसदीय सीटों काराकाट, आरा और बक्सर में प्रमुख दलों के चार कुशवाहा प्रत्याशी मैदान में थे जो यह बताने के लिए काफी है कि सभी दल इस क्षेत्र में शुरू से ही कुशवाहा मतों को रिझाने में लगे हैं. चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तेजी से उपेन्द्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा के साथ-साथ सासाराम और आरा लोकसभा क्षेत्र में यात्राएं की उसे देख अन्य दलों की मंशा भी इसी राह पर चलने लगी. परिणाम हुआ कि सासाराम में एक भव्य कुशवाहा चेतना सम्मेलन आयोजित हुआ. जिसमें राज्य सरकार के मंत्री जदयू नेता सम्राट चौधरी सहित कई कुशवाहा दिग्गज मिलकर धारा को जदयू के तरफ मोड़ने का प्रयास किया. यह सम्मेलन अभी संपन्न ही हुआ था कि भाजपा का कुशवाहा चेतना रथ सासाराम आ पहुंचा. जहां विधायक जवाहर प्रसाद तेज तर्रार नेत्री एमएस गंधा सहित कई नेताओं ने जोर अजमाईश की. ये रथ पूरे शाहाबाद में घूमा और चेतना जगाने के बहाने भाजपा ने कुशवाहा मतों को पार्टी की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया. वैसे बताते चलें कि पहले से हीं सासाराम के कुशवाहा बहुल विधान सभा सीट पर भाजपा के जवाहर प्रसाद कब्जा जमाए बैठे हैं. जबकि जगदीशपुर की सीट श्री भगवान कुशवाहा के हाथों से फिसलकर राजद के भाई दिनेश के हाथ में चली गई है. यहां यह जानकारी देना आवश्यक है कि पिछले तीन विधान सभा चुनावों से पूरे शाहाबाद में कुशवाहा विधायको की संख्या लगातार कम हो रही है. 2000 से 2005 तक शाहाबाद में सासाराम के जवाहर प्रसाद, जगदीशपुर में श्री भगवान कुशवाहा, काराकाट में अरूण कुमार सिंह और चैनपुर में महाबली सिंह विधायक हुआ करते थे. 2005 से 2010 तक यह संख्या घटकर तीन पर आ गई. तब महाबली सिंह राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे और काराकाट के सांसद बने. इस उपचुनाव में चैनपुर की सीट भाजपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद ले उड़े थे. 2010 में जब चुनाव हुए तो यह संख्या घटकर मात्र एक रह गई. तब जवाहर प्रसाद सासाराम से पुन: भाजपा विधायक के रूप में चुने गए. उनके अलावा काराकाट से माले विधायक अरुण कुमार और जगदीशपुर से राजद विधायक श्री भगवान कुशवाहा चुनाव हार चुके थे. फिलहाल पूरे शाहाबाद में जवाहर प्रसाद अपनी बिरादरी के इकलौते विधायक बचे हुए हैं. जबकि शाहाबाद की चार सीटों में से सिर्फ एक सीट काराकाट पर उपेन्द्र कुशवाहा का कब्जा है. मतों के प्रतिशत राजनीति में सक्रियता को देखते हुए यह संख्या काफी कम है. जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चाहे जदयू या राजद कांग्रेस भाजपा, लोजपा और रालोसपा सभी अपने अपने अभ्यास तेज किए हुए हैं. जिसके प्रमाण आयोजित की गई रैलियां ,सम्मेलन, रथ यात्राएं पेश कर रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

अशोक सिंह ने दावा ठोंका

जमुई के वरिष्ठ जदयू नेता अशोक सिंह ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना मजबूत दावा ठोंक दिया है. यह चुनाव अगले साल अप्रैल माह में प्रस्तावित है. फिलहाल इस सीट पर संजय सिंह विधान पार्षद हैं. अशोक सिंह कहते हैं कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और मैं दिल से चाहता हूं कि जनता की सेवा में अब मैं अपना सौ फीसदी योगदान दूं. उन्होंने कहा है कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है. वोटरों के भारी दबाव के कारण मुझे इस चुनाव में कूदने का फैसला करना पड़ा. बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है इसमें मैं भी अपना छोटा सा योगदान देना चाहता हूं. गांव-गांव में विकास की गाड़ी दौड़े यही मेरा सपना है. अशोक सिंह ने विकास पसंद करने वाले हर किसी से स्थानीय निकाय चुनाव में सहयोग करने की अपील की है. अशोक सिंह का दावा है कि क्षेत्र के सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है. वोटर बस मतदान के दिन का इंतजार कर रहे हैं.

– राजेश

संगोष्ठि आयोजित

फॉरबिसगंज प्रखंड के रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक में द्विजदेनी पुस्तकालय के तत्वावधान में 'मां की महिमा' विषय पर संगोष्ठि का आयोजन मुखिया प्रवीण कुमार दास की अध्यक्षता में किया गया. इसका संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया. संगोष्ठि में महर्षि वेद व्यास के संदेश 'मां के समान–गति नहीं, ऋण नहीं' और न तो माँ के समान छाया न तो प्रिया है इस संसार में... की जानकारी दी गयी. स्कूली बच्चों ने कवि नीरज जी की कविता 'मां ही गंगा, मां ही यमुना, मां ही तीरथ धाम, मां सिर पर हाथ जो तेरा क्या ईश्वर का काम, सुनाकर भाव विहल कर दिया. बतौर मुख्य अतिथि मोहनलाल दास ने कवि नाटककार, जॉर्ज बर्नाड शॉ के कथन की प्रस्तुति दी. इस अवसर पर सुनील साह, विनोद दास, मोहनलाल दास, नैय्यर शमशाद, हरिप्रसाद दास, हर्ष नारायण दास, हेमंत यादव, राजनारायण प्रसाद आदि ग्रामीण उपस्थित थे.

– अमित कुमार

जयंती मनी

बिहार बाल मंच के तत्वावधान में वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गयी. इसकी अध्यक्षता मुखिया प्रवीण कुमार दास ने की जबकि मंच का संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया. अतिथियों में हेमंत यादव, हर्ष नारायण दास, राजनारायण प्रसाद, हरि प्रसाद दास, विजय साह, आशीष कुमार, नैयर शमशाद, मो. रिजवान, मो. सलाइद्दीन, नागेश्वर दास, मनोज देव, स्कूली बच्चों में नाजरीन, अख्तरी, रूबी, चांदनी, कृति, आकृति, पल्लवी आदि ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. वक्ताओं ने कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान रचित अमर कविता 'बुंदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी का गायन किया तथा रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के प्रसंगों का इल्लेख किया. प्रतिभागी स्कूली बच्चों को द्विजदेनी पुस्तकालय फारबिसगंज के सौजन्य से प्रोत्साहन पुरस्कार उपहार के साथ प्रदान किया गया.

– अमित कुमार

मेहनतकश बनें मधुमेह दूर भागेगा आपसे . . .

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ एस.के. यादव
एम.डी. मेडिसिन, दरभंगा

डायबिटीज या मधुमेह पर चर्चा एक बार पुनः लाजमी हो गया है इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। मधुमेह अक्सर मोटे, व्यक्तियों को होता है और वे व्यक्ति जो सिडेन्ट्री जॉब में रहते हैं अर्थात ज्यादातर बैठने वाला काम करते हैं उन्हें ज्यादा होता है। उपरोक्त बातें दरभंगा के डायबिटिज स्पेशलिस्ट डॉ. एस. के यादव ने बातचीत के दौरान कहीं। आगे उन्होंने बताया कि डायबिटीज दो प्रकार का होता है पहला अनुवांशिक जो कि माता–पिता के द्वारा होता है तथा दूसरा 40 के उपर के लोगों को होता है। इस बिमारी के लक्षणों में ज्यादा भूख, ज्यादा प्यास, लगना एवं एक्सेस यूरिन का आना, वजन घटना शामिल है। इसके लक्षण सामने आने पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट डायबिटिज के लिए जरूर करा लें।

अपने लाइफ स्टाइल को बदलना जरूरी है और दैनिक जीवन में मेहनतकश इन्सान बनें जिससे आप इन बीमारियों से दूर रह सकें। अपने दैनिक जीवन में सुबह 50 मिनट तेज टहलना शामिल अवश्य करें। खाने में आलू चावल, मीठा आदि वर्जित रखें। और शाकाहारी बनें।

तेज टहलने के बाद प्राणायाम को शामिल अवश्य करें। हरी सब्जियां, दाल इत्यादि को शामिल करें। हमेशा भूख से कम खाएं। नाशता अवश्य करें। करेला और मेथी का प्रयोग ज्यादा करें। रोटी खायें और थोड़ा – थोड़ा करके दिन में 3–4 बार खायें। ■ प्रस्तुतिः चित्रा भारती

AROFIT Protin Powder
Protein granules enriched with Vitamn, Minerals & Carbohydrates

Levokon Tab
Levofloxacin 500 mg
The powerfull quinolone with superior efficacy

ARILINE Cap.
Acebrophylline 100 mg

MUSTAL Tab.
Montelukast Sodium 10 mg+ Levocetirizine HCL 5 mg

ONDANOK DROP
Ondanesetron 2 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

गया

नए मुकाम पर मिंटो टॉवर

महाराजा रावणेश्वर प्रसाद सिंह के निधन के बाद इस ऐतिहासिक धरोहर के रख-रखाव का उत्तरदायित्व वर्ष 1953–54 तक गिद्धौर राज परिवार पर ही था परंतु इस रियासत के तत्कालीन महाराजा प्रताप सिंह की लंबी अवधि तक कोलकाता प्रवास के फलस्वरूप इस ऐतिहासिक धरोहर के रख–रखाव में दिक्कत आने लगी. इस कारण वर्ष 1983–84 में बिहार सरकार को मिंटो टॉवर दानस्वरूप दे दिया गया.

इमरान

जमुई–झाझा मुख्य मार्ग के गिद्धौर बाजार चौक पर स्थित खूबसूरत मिंटो टॉवर अब और भी निखर कर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर दमकने वाला है. सूबे के भवन निर्माण मंत्री दमोदर रावत के अथक प्रयासों से मिंटो टॉवर का गौरव अब और भी बढ़ गया है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो तत्कालीन अंग्रेज शासक लॉर्ड मिंटो के आगमन के सम्मान में वर्ष 1906–07 में मिंटो टॉवर का निर्माण गिद्धौर राज्य में चंदेल शासकों के शासन काल में महाराजा रावणेश्वर प्रसाद सिंह ने कराया था. महाराजा रावणेश्वर प्रसाद सिंह का जन्म 1860 ई. में हुआ था. अपने पिता शिव प्रसाद सिंह के निधन के बाद सन 1886 ई. में गिद्धौर राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी. महाराजा रावणेश्वर प्रसाद सिंह के निधन के बाद इस ऐतिहासिक धरोहर के रख–रखाव का उत्तरदायित्व वर्ष 1953–54 तक गिद्धौर राज परिवार पर ही था परंतु इस रियासत के तत्कालीन महाराजा प्रताप सिंह की लंबी अवधि तक कोलकाता प्रवास के फलस्वरूप इस ऐतिहासिक धरोहर के रख–रखाव में दिक्कत आने लगी. इस कारण वर्ष 1983–84 में बिहार सरकार को मिंटो टॉवर दानस्वरूप दे दिया गया. सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात इस धरोहर की मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा वर्षो पूर्व कराया गया था. लेकिन मिंटो टॉवर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मंत्री दामोदर रावत ने इसके रखरखाव की व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया. यह दामोदर रावत के मेहनत का ही नतीजा है कि

108 साल पुराने इस ऐतिहासिक मिंटो टावर को सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना संख्या–30 दिनांक 6.11.2014 द्वारा इसे संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है. इसके बाद मिंटो टॉवर का लोकार्पण 11 नवंबर को मंत्री दामोदर रावत के द्वारा विभागीय प्रधान सचिव चंचल कुमार और विशेष सचिव गंगा कुमार की उपस्थिति में किया गया. अब इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कला–संस्कृति एवं युवा विभाग की होगी. मंत्री दामोदर रावत कहते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल विभाग की नहीं होती है बल्कि यह तो आम जनता का भी कर्तव्य है कि जमुई जिले के इस महान धरोहर को कैसे सुरक्षित रखें. दामोदर रावत कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा किया गया एक छोटा प्रयास अपने मुकाम तक पहुंच पाया. उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस मिंटो टॉवर के बारे में जाने और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझे. रावत कहते हैं कि इतिहास हमारी अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल कर रखें. उन्होंने इस काम को सफल बनाने के लिए प्रधान सचिव चंचल कुमार और विशेष सचिव गंगा कुमार का भी धन्यवाद किया.■

feedback@chauthiduniya.com

अघवारा बांध निर्माण की जांच निगरानी के हवाले

सीतामढ़ी जिले में विकास किसानों के लिए अभिशाप बन कर रह गया है. जिले के बाजपट्टी प्रखंड के बसहा गांव के दर्जनों किसानों ने अघवारा बांध निर्माण में कार्य एजेंसी की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की थी. पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए किसानो के हित में निर्माण एजेंसी की मनमानी के खिलाफ जिला से लेकर जल संसाधन विभाग तक आवाज लगायी थी. इस संबंध में 'चौथी दुनिया' ने पिछले साल 23 से 29 दिसंबर के अंक में पृष्ठ संख्या–19 पर 'जारी है निर्माण कंपनियों की दादागिरी' एवं 17 से 23 फरवरी 2014 के अंक में पृष्ठ संख्या– 20 पर 'निर्माण कंपनी कर रहीं किसानों की हकमारी' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. जब कोई निदान नहीं निकला तब इस मामले को निगरानी विभाग का रास्ता दिखाना मुनासिव समझा गया. अब क्षेत्र के किसानों की नजर निगरानी विभाग की जांच टीम की रिपोर्ट पर अटकी है...

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले से होकर प्रवाहित होने वाली अघवारा समूह की नदियों पर करीब 60 करोड़ की लागत से बांध निर्माण शुरू कराया गया. जल संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे निर्माण में व्यापक स्तर पर प्रावधानों की अनदेखी की शिकायत की जाने लगी. सरकारी व प्रशासनिक अनदेखी का आलम रहा कि किसानों की पीड़ा को कोई भी समझने को तैयार नहीं हुआ. किसानों की फसल को बिना पूर्व सूचना के ही निर्माण एजेंसी द्वारा खेत से मिट्टी समेत जबरन काट कर बांध का निर्माण कराया जाने लगा. इसका खुलासा तो तब हुआ है जब बाजपट्टी प्रखंड के बसहा निवासी किसान भाग्यनारायण यादव ने बागमती प्रमंडल संख्या–1 के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता भीम शंकर राय को एक आवेदन दिया. आवेदन में कहा था कि निर्माण एजेंसी ब्रम्हपुत्रा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर संदेश कुमार यादव पुलिस की सहयोग से जबरन किसानों को धमका कर बांध से सटे दोनों साईड खेत से मिट्टी काट कर बांध का निर्माण करा रहे है. कार्यपालक अभियंता से किसान श्री यादव ने मांग की थी कि अगर किसानों के खेत से मिट्टी काट कर ही बांध का निर्माण करना है तो पहले किसानों को लिखित रूप में इससे अवगत करायें.

पूर्व सांसद नवल किशोर राय

बथनाहा प्रखंड के माधोपुर तिरकौलिया पंचायत से पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत के अंतिम सीमा रामपुर पचासी गांव तक निर्माण कार्य में प्रावधानों की अनदेखी किये जाने की शिकायत भी की गयी थी. बताया गया था कि सोनबरसा, तिरकौलिया, माधोपुर, लतीपुर, सुंदरपुर, सन्दही, करिवाना, बंगराहा, बसहा, मधुवन, संडवारा, बखरी, मधुरापुर, बचपटी, वसंत, महम्मदपुर, चकासा, आवापुर, मानिकपुर, गंगटी, गाढा, सूर्यपटी, हिरौली, जैतपुर, बेदौल, कुसैल, भहमा, सिंगियाही, केषोपुर, हरिपुर, पोरभिंडा व हरदिया समेत तकरीबव तीन दर्जन से अधिक गांव के किसान व्यापक क्षति से बेहाल होकर रह गये हैं. बाजपट्टी प्रखंड के बसहा गांव के राम आशीष राय, गणेश साह, रास बिहारी साह, जयकांत पंडित, रामचंद्र पंडित, दाउद अंसारी, उमेश राय, रास बिहारी राय, रामचंद्र महतो, चरित्र महतो, रामवृक्ष महतो, विभिषण साह, रामवृक्ष राम, भग्यनारायण यादव, सुकनंदन यादव, उमेश साह, ईदरीश साफी, जुम्मन बैठा, सोलाजिम अंसारी, मोलाजिम, मुन्ना, हाफिज जी, गिरिजेश षर्मा, गुड्डू शर्मा, लड्डू शर्मा, प्रभात शर्मा व छेदी राय समेत अन्य किसान अपनी फसल की बर्बादी के लिए निर्माण कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया था. उनका कहना था कि खेत में लगा मक्का, गेहूं, मंसूर, आलू व केराव समेत अन्य फसल को बिना सूचना के ही मिट्टी समेत खेत से काट लिया गया है. बर्बादी को ले निर्माण एजेंसी के पदाधिकारी से बात भी करने का साहस नहीं हो पा रहा है. कारण कि कुछ भी बोलने पर मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जा रही है.

दूसरी ओर जन नायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के केन्द्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने भी मामले को गंभीरता से लिया. 4 दिसंबर 2013 को पूर्व सांसद ने सुदिष्ट कुमार, शशि भूषण, भाग्यनारायण यादव व सत्यनारायण राय समेत अन्य के साथ सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित डीएम डॉ. प्रतिमा के कार्यालय में पहुंच कर हालात से डीएम को अवगत कराया था. साथ ही एक स्मार पत्र के माध्यम से बांध निर्माण कार्य की जांच टीम गठित कर एक पखवाड़े में कराने, किसानों को मुआवजा एवं सुरक्षा दिलाने, बची फसल को नष्ट होने से बचाने एवं मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के साथ इंडियन स्टैंडर्ड व प्राक्कलन का पालन कराने की मांग की थी. सौंपे गये स्मार पत्र में निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत की गयी थी. कहा गया था कि प्राक्कलन के हिसाब से हर प्रथम फीट मिट्टी पर पानी तथा रोलर का प्रयोग कर कम्पेक्शन नहीं किया गया है. भारत सरकार की पुस्तिका इन्डियन स्टैंर्ड में वर्णित मिट्टी काटने के मापदंड का घोर उल्लंघन हो रहा है. मार्गदर्शिका का हवाला देते हुए पूर्व सांसद ने यह भी बताया था कि नदी के तटबंधों के निर्माण में रीवर या कंट्री साईड दोनो तरफ 80 मीटर के अंदर मिट्टी काटने पर रोक है. परंतु प्रावधानों की अनदेखी करोड़ों की बंदरबाट की नियत से की जा रही है. यह भी आरोप निर्माण कंपनी पर लगाया गया था कि पूरे प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत मिट्टी किसानों की फसलों वाली जमीन से जबरन काटी गयी है.

ग्रामीण सूत्रों के अनुसार, आनन–फानन में बसहा गांव के कुछ किसानों के बीच 90 रुपये प्रति डिस्मील की दर से मिट्टी का मुआवजा भुगतान कराया गया. अगर इसे सच माना जाये तो निश्चित तौर पर कार्य एजेंसी ने प्रावधानों के विपरित कार्य किया है इसमें संदेह नही. बताया जाता है कि शेष गांव के किसान न्याय की आस में अब तक है. तकरीबन तीन दर्जन गांव में से एक मात्र बसहा को छोड़ कर सभी की नजर सरकार की कार्रवाई पर टिकी है. हाल में जल संसाधन विभाग के निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोशांग के अधीक्षण अभियंता ई. निखिलेन्दु निखिल ने पूर्व सांसद नवल किशोर राय को एक पत्र प्रेषित कर निर्माण कंपनी पर लगाये गये आरोपों की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच किये जाने संबंधी जानकारी दी थी. 19 नवंबर से विभागीय अधिकारियों की टीम जांच कार्य में लगी रही. अब संबंधित क्षेत्र के किसानों की नजर निगरानी के उक्त टीम पर अटकी है. न्याय की आस लगाये किसानों को राहत मिलती है अथवा जांच की फाईल विभागीय कार्यालय में बंद होगी फिलहाल कहना मुश्किल है. वैसे पूर्व सांसद का कहना है कि निगरानी टीम पर पूर्ण भरोसा है. वर्तमान में सैकड़ों किसानों ने अपनी व्यथा की गाथा को कार्यपालक अभियंता व निगरानी टीम के समक्ष रखा है. इनमें चंद्रकांत झा, गुलजारी राय, श्याम बिहारी राय, वीरेंद्र कुमार समेत अन्य शामिल है.

जारी है निर्माण कंपनियों की दादागिरी

निर्माण कंपनी कर रही किसानों की हकमारी

चौथी दुनिया में प्रकाशित खबर

चर्चा है कि अगर किसानों को क्षति का वाजिब मुआवजा नहीं मिला तो आगामी विधानसभा चुनाव में यह मामला चुनावी मुद्दा बन सकता है. अगर ऐसा होता है तो संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए चुनावी मुश्किल सामने आ सकती है. वैसे जांच टीम की रिपोर्ट पर क्षेत्र के किसानों की नजर फिलहाल टिकी है. सभी को जांच के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है.■

feedback@chauthiduniya.com

गया

नौरंगिया पुलिस गोली कांड की जांच में देरी

सुनील सौरभ/अरविंद नाथ तिवारी

भारत–नेपाल की सीमा से लगे बिहार के पश्चिमी चंपारण का इलाका बगहा कभी दस्युओं के आतंक से त्रस्त था. बाद में नक्सली गतिविधियों ने भी बगहा को आतंक के साये में जीने को विवश कर दिया था. उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी गंडक नदी के रेता (दियारा) क्षेत्र में दस्युओं का खौफ तो नेपाल से लगे पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की दहशत ने बगहा के लोगों का जीना हराम कर दिया था. स्थिति बेकाबू होते देख राज्य सरकार ने बगहा को पुलिस जिला का दर्जा दे दिया. यहां आरक्षी अधीक्षक का पूर्ण कार्यालय हो गया. विधि व्यवस्था कुछ ठीक हुई. हाल के वर्षों में तो बगहा में न तो दस्युओं का और न ही नक्सलियों का कोई खौफ रहा. अधिकांश दस्यु सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ मुठभेड में मारे गये. नक्सली कार्रवाई भी समाप्त सी हो गयी. लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाये तो लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही स्थिति हो गयी है बगहा पुलिस जिले के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की. जिसका उदाहरण है नौरंगिया पुलिस फायरिंग. इस घटना में पांच ग्रामीणों की मौत हो गयी थी तो दर्जनों घायल आज भी जीवन–मौत से जूझ रहे हैं. घटना के करीब डेढ़ वर्ष बाद नौरंगिया पुलिस फायरिंग के पीड़ितों को मुआवजा तो मिला लेकिन घटना के कारणों की जांच आज तक पूरी नही हो पायी है और न ही इस घटना के दाषियों की पहचान अभी तक हो सकी है. हालांकि पीड़ितों का मानना है कि मुआवजे जो रकम उन्हें दी गई है उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो वे इलाज में खर्च कर चुके हैं.

यह घटना बगहा पुलिस जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच स्थित नौरंगिया थाना क्षेत्र मे बसी थारू जन जाति के बीच आपसी विवाद से शुरू होकर खूनी संघर्ष में तब्दील हो पुलिस फायरिंग तक जा पहुंची थी. प्राय: शांतिप्रिय थारू जनजाति के लोग इस घटना के बाद से पुलिसिया कार्रवाई से दहशत में हैं तो इस घटना में मारे गये लोगो के परिवार न्याय की आस लगाये बैठे हैं. जबकि घटना के मूल कारणों को थारू जनजाति का कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहा है. जबकि कारण सभी को पता है.

ममला यह था कि नौरंगिया थाना के देवताहा गांव के रामनारायण काजी के पुत्र चंदेश्वर काजी का अपहरण 15 जून 2013 को हो गया था. अपहरण की घटना के बाद परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए नौरंगिया तथा वाल्मीकिनगर थाने करीब नौ दिनों तक दौड़ते रहे. दोनों थाने घटना स्थल को अपना क्षेत्र नहीं होने की बात कहकर मामले को टालते रहे. जब कुछ जनप्रतिनिधियों का दबाव पड़ा तो 23 जून 2013 को नौरंगिया थाना ने प्राथमिकी दर्ज की. जिसमे तीन लोगों को नामजद किया गया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी अभियुक्तों पर कार्रवाई नहीं होते देख ग्रामीणों में अंदर ही अंदर पुलिस के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था. पुलिस ने तब ग्रामीणों के भीतर पनपते आक्रोश को भांप लिया और प्राथमिकी में बनाये गये एक अभियुक्त अमवां गांव निवासी बालेश्वर महतो के पुत्र रविकेश कुमार को हिरासत में लिया. 25 जून 2013 को अपहृत चंदेश्वर काजी के परिजनों और ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली कि पुलिस पकड़े गये अभियुक्त को छोड़ रही है. इस बात पर अपहृत व्यक्ति के परिजनों समेत दर्जनों ग्रामीण नौरंगिया थाना पहुंच कर विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गये. तभी पुलिस को सूचना मिली की अपहृत चंदेश्वर की हत्या कर लाश को जमीन में गाड़ दिया गया. पुलिस इस सूचना पर स्थल पर पहुंची. लेकिन लाश नहीं मिली. पुलिस जब वापस लौट रही तो धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि अभियुक्त रविकेश को हमलोगों के सामने लाकर पूछा जाये कि अपहृत की लाश कहां है? पुलिस ने यह बात नहीं मानी. ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता गया. तब तक सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने को घेर कर सारे पुलिस कर्मियों को एक तरह से बंधक बना लिया. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने इसकी सूचना बगहा एसपी को दी. एसपी ने घटना स्थल पर एसडीपीओ तथा इंस्पेक्टर को पुलिस बल के साथ भेजा. बढ़ते पुलिस बल को देख ग्रामीण भी उत्तेजित होने लगे. ग्रामीणों को समझाने में पुलिस अधिकारी नाकाम रहे. ग्रामीण अभियुक्त रविकेश को अपने हवाले करने की मांग पर अड़े रहे. ग्रामीणों का कहना था कि रविकेश से हमलोग बात उगलवा लेंगे कि चन्देश्वर की लाश को कहां छिपाया है. इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया. पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को देख पीछे हटने लगी. ग्रामीणों की उग्रता देख पुलिस रक्षात्मक अवस्था में आ गई. लेकिन स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की. इस पर ग्रामीण और उग्र हो गये. जान बचते नहीं देख पुलिस पदाधिकारियों ने सीधे फायरिंग का आदेश दिया. देखते–देखते सैकड़ों लोग जमीन पर खून से लथपथ लोटने लगे. पुलिस भागते ग्रामीणों को खदेड़–खदेड़ कर लाठी–डंडे, पुलिस वाहन से कुचलने लगी. मीडिया कर्मियो को घटना स्थल पर जाने से रोक दिया गया. इस घटना में पांच ग्रामीणों की मौत हुई थी और सौ से अधिक घायल हुए थे. राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतकों के परिजनों को पांच–पांच लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रुपये दिये और एसपी समेत थानाध्यक्ष, डीएसपी को स्थानान्तरित कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर जज राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व मे एक सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू की गयी. अब तक इस मामले में गवाही दर गवाही हो रही है. 7–8 नवंबर 2014 को वाल्मीकिनगर में जांच कमेटी ने गवाही ली. वहीं दूसरी ओर कोई भी थारू यह बताने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि चन्देश्वर काजी का अपहरण के बाद हत्या किन कारणो से हुई? पुलिस फायरिंग के बाद तो यह मूल सवाल ही कहीं दूर छूट गया. वहीं दूसरी ओर अपहरण और हत्या का आरोपी रविकेश कुमार समेत सभी तीन अभियुक्त जमानत पर गांव आ चुके हैं. भारतीय थारू कल्याण महासभा के दीपनारायण बताते हैं कि इस घटना की जांच हो रही है. हमलोग अभी चुप हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार तथा अभियुक्त भी हमारे समाज का ही है. जांच कमेटी और न्यायपालिका का क्या आदेश आता है, हमलोग इसे देखेंगे. दीपनारायण कहते हैं कि अनेक घायल ऐसे हैं, जिसके इलाज में लाखों रुपये खर्च हुआ है और दर्जन से अधिक ऐसे है, जो अभी भी जीवन–मौत से जूझ रहे हैं. सरकार को इन घायलों को इलाज का खर्च वहन करना चाहिए.

यहां सच कहा जाये तो इस घटना के लिए न तो ग्रामीणों की गलती है और न ही पुलिस की गलती मानी जा सकती है. राजनीति के माहिर राजनीतिज्ञों द्वारा वोट बैंक की खातिर चलायी गयी नयी बयार ने जो परिस्थिति पैदा की उसी का परिणाम है नौरंगिया पुलिस गोलीकांड. हाई कोर्ट के रिटायर जज राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय जांच कमेटी ने पहले तो सभी गवाहों को पटना बुलाया. इस पर भारतीय थारू कल्याण महासभा और नौरंगिया गोलीकांड संघर्ष समिति ने आपत्ति करते हुए जांच कमेटी को घटना स्थल के निकट आकर जांच करने की मांग की, तब जाकर घटना की जांच वाल्मीकिनगर में शुरू हुई. गत 7–8 नवम्बर 2014 को भी जांच कमेटी के समक्ष सभी 24 गवाहों से सरकारी वकील ने जिरह की. केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने थारुओं को जनजाति का दर्जा दिया था. इसमें तत्कालीन रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. तभी से बिहार में जदयू चंपारण में थारुओं के वोट को अपना वोट बैंक मानकर राजनीति करती रही है. लेकिन नौरंगिया पुलिस फायरिंग के बाद चंपारण में थारुओं में बिहार सरकार तथा जदयू के प्रति नकारात्मक संदेश गया. हालांकि घटना के कुछ दिनों पूर्व ही अलग हुई भाजपा को विशेष राजनीतिक लाभ नहीं मिल सका. यदि बिहार विधान सभा के चुनाव से पूर्व इस मामले में कोई फैसला नहीं आ सका तो भाजपा इस मुद्दे को चंपारण में उठाकर थारुओं की सहानुभूति प्राप्त कर सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

पंचायत के तुगलकी फरमान

सुनील सौरभ

वर्तमान मामला है कि पटवा समाज के एक लड़के और लड़की ने अपने मन से विवाह कर लिया. इसमें समाज के ही दो लड़कों ने मदद की. एक नवंबर को दोनों प्रेमी युगल घर आये तो लोगों ने इस मामले को पंचायत में उठाया. 6 नवंबर 2014 को पूरे पटवा समाज पंचायत ने प्रेमी–प्रेमिका के घर वालों का हुक्का–पानी बंद कर दिया और प्रेमी तथा उसके दो दोस्तों का सिर मुंडवा कर घर–घर माफी मंगवायी गयी.

समाज विकासक्रम में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. इसके कई धड़े होते जा रहे हैं. समाज का एक हिस्सा तो समय के साथ हाईटेक होता जा रहा है तो दूसरा, परंपराओं के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक गया है. यह समाज घोर परंपरावादी बनता जा रहा है. इस तरह के समाज के लिए आज भी पंचायत का फैसला ही सर्वोपरी माना जाता है. ये पंचायतें समय–समय पर 'तुगलकी फरमान' सुनाती रहती हैं. ऐसा ही एक मामला आया है बिहार के मैनचेस्टर कहलाने वाले गया के मानपुर पटवा टोली का.

पटवा टोली पिछले कई वर्षों से देश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान आईआईटी में सफलता का एक मानक बन गया है. यहां से अब तक दर्जनों छात्र–छात्राएं आईआईटी में सफलता प्राप्त कर चुके हैं. आईआईटी कर यहां के अनेक छात्र देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बावजूद इसके मानपुर पटवा समाज आज भी परंपरावादी है. बोलचाल, रस्म–रिवाज, सामाजिक नियम–कानून भी इस समाज का अपने हैं. समाज का कोई भी व्यक्ति बने सामाजिक दायरे तथा पंचायत के नियम–कानून से दायें–बायें नहीं जा सकता है. शादी–विवाह भी कोई अपने मन से नहीं कर सकता. समाज के मन से ही शादी–विवाह भी करना होगा. अपने मन से शादी की तो पंचायत ऐसे परिवारों का हुक्का–पानी बंद करने समेत अनेक तरह की सजा देने के लिए अधिकृत है. पटवा समाज ऐसा एकजुट है कि पीड़ित परिवार अपनी पंचायत के निर्णय के खिलाफ पुलिस थाने भी नहीं जा सकता है. यदि गये तो समाज तथा पंचायत की ओर से और फजीहत होगी. नतीजा है कि पीड़ित परिवार समाज में रहने के लिए पंचायत के हर फरमान को मानने के लिए विवश होता है. वर्तमान मामला है कि पटवा समाज के एक लड़के और लड़की ने अपने मन से विवाह कर लिया. इसमें समाज के ही दो लड़कों ने मदद की. एक नवंबर को दोनों प्रेमी युगल घर आये तो लोगों ने इस मामले को पंचायत में उठाया. 6 नवंबर 2014 को पूरे पटवा समाज पंचायत ने प्रेमी–प्रेमिका के घर वालों का हुक्का–पानी बंद कर दिया और प्रेमी तथा उसके दो दोस्तों का सिर मुंडवा कर घर–घर माफी मंगवायी गयी. प्रेमिका के माथे पर लगे सिंदूर को भी धुलवाया गया. पटवा समाज को कोई भी व्यक्ति इस संबध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. घटना यह है कि पटवा टोली के लेखराज राम पटवा का बेटा गुड्डू कुमार पड़ोस की रहनेवाली अपनी ही जाति की एक लड़की से प्रेम करता था. करीब दो माह पूर्व वह अपने दो दोस्त लालू पटवा और जानकी पटवा की मदद से लड़की को भगा ले गया. लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो पटवा समाज के लोगों ने नाराजगी जतायी. पटवा जाति सुधार समिति की सकल पंचायत ने प्रेमी तथा इसे सहयोग करने वाले दोस्तो को भी मुंडन करा कर पटवा जाति के हर घर तक पहुंच कर माफी मांगने की सजा सुनायी. सजा को लागू करने के लिए गुरुवार पूर्णिमा 7 नवंबर 2014 को तिथि तय की गयी थी. इसी के तहत इस दिन सजायाप्ता युवकों को मानपुर के पटवा टोली मे मुंडन कराकर घर घर घुमाकर माफी मंगवायी गयी. सजा के तहत युवक के परिवार वालों को किसी विवाह समारोह में आने–जाने, सामुहिक पूजा करने और कोई बड़ा आयोजन करने पर तो रोक रहेगी, लेकिन यह परिवार यहां रह सकता है. दोषी युवक अपनी सजा पूरी करें इसके लिए उन पर निगाह रखी जा रही थी. वहीं एक दूसरे मामले में एक विधवा को भी सजा दी गई. विधवा महिला अपनी ही जाति के अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गयी थी. लौटकर जब उक्त विधवा का प्रेमी घर आया तो उसे भी बाल मुंडन कराकर घर–घर माफी मांगने की सजा भुगतनी पड़ी. इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व भी पटवा टोली के पंचायत का तुगलकी फरमान का शिकार एक चिकित्सक को होना पड़ा था. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. सीताराम प्रसाद के खिलाफ भी पटवा समाज के लोगों ने पंचायत कर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था. मामला था कि डॉ. सीताराम अपने इंजीनियर बेटे का विवाह बाहरी पटवा जाति में कर दिया था.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

जिला बनाने की मांग

फॉरबिसगंज को जिला बनाने की मांग इन दिनों काफी जोरों पर है. यह एक ऐसी मांग है जिसपर किसी के द्वारा भी कोई राजनीति नहीं की जा रही है. यूं कहा जाय सारे राजनीतिक दलों में इसी प्रकार की एकता नजर आ रही है जिस प्रकार संसद एवं विधानसभाओं में इनकी सुविधा में बढ़ोतरी के लिए पेश किये जाने वाले बिल को ध्वनि मत से बिना किसी विरोध के पास कराया जाता है. फारसिबगंज सीमावर्ती क्षेत्र के सभी राजनीतिक दल यथा कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू, कम्यूनिष्ट, लोजपा, बसपा, रालोसपा, राकंपा सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुद्धिजीवि एकजुट हो फारबिसगंज अनुमंडल को जिला बनाने की मांग एक स्वर में करने लगे हैं. इसी के तहत स्थानीय जेपी सभा भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता फारबिसगंज जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक शाहजहां शाद ने की. इस बैठक में जदयू नेता रमेश सिंह, समाजसेवी बच्छराज राखेचा, विनोद सरावगी, पूनम पांडिया, अरूण यादव, सरवर आलम, पिंटू तांती, सूर्यनारायण भगत, रमेश मेहता, चंदन यादव, बबन यादव, मनोज मेहता, पवन मिश्रा, मनोज जायसवाल, प्रवीण कुमार, मंचन केशरी, मोहन दास, विद्यानंद पासवान, मोजीब खान, बदरी नारायण मेहता, किशोर दास, रजत सिंह, रज्जाक, दिलीप पटेल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

– अजातषत्रु अग्रवाल

कैंसर जागरूकता रैली

मारवाड़ी युवा मंच की नवगछिया शाखा द्वारा एचडीएफसी बैंक के सौजन्य से नौ स्कूलों के बच्चों के सहयोग से नवगछिया नगर में कैंसर जागरूकता रैली निकाली गयी जिसमें बाल भारती, बाल भारती विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, अरविंद मेमोरियल स्कूल, इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका विद्यालय, राजकीय श्री लक्ष्मी कन्या मध्य विद्यालय तथा सावित्री पब्लिक स्कूल के छात्र संख्या में उपस्थित थीं. इन छात्रों के हाथों में तख्तियाँ थी. जिसपर लिखा था– जिंदगी चुनो– तंबाकू नहीं, धूम्रपान निषेध, तंबाकू जान लेवा है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकर है. इस कैंसर जागरूकता रैली में मारवाड़ी युवा मंच की शाखा के अध्यक्ष अरविंद, चौधरी, सचिव निखिल चिरानिया, वरुण केजरीवाल, संयुक्त सचिव प्रभात पंसारी, मनोज चौधरी, राज चौधरी, शंभू सर्राफ, कमल टिबड़े वाल, सौरभ नारनोली, संदीप चिरनिया, विशाल चिरनिया, सुमित वर्मा तथा एचडीएफसी बैंक के नवगछिया शाखा प्रबन्धक मनीष आचार्य, मदन झा और अविनाश शर्मा के अलावा मंच के प्रादेशिक अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा भी शामिल रहे.

– नमन

बारात का स्वागत

प्रत्येक पांच साल के अंतराल पर अयोध्या से जनकपुर जाने वाले श्रीराम के बरात का सीतामढी में भव्य स्वागत किया गया. दूल्हा श्रीराम की बरात जैसे ही जिला की सीमा में प्रवेष किया, वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ ने पुश्प वर्शा व आरती से भगवान श्रीराम व उनके अनुज लखन लाल का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया. इस दौरान महिलाओं ने भी इत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भागीदारी दी. विवाह पंचमी के मौके पर आयी बरात एक रात्रि के विश्राम के बाद नेपाल के जनकपुर स्थित ऐतिहासिक श्रीराम जानकी मंदिर के लिए प्रस्थान किया. जहां प्रति वर्ष भव्य विवाहोत्सव का आयोजन किया जाता है.

– ब्रजेष

भाजपा विधायक ने जतायी प्रसन्नता

अयोध्या से सीतामढ़ी आयी श्रीराम बरात के स्वागत में नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, मां जानकी जन सेवा ट्रस्ट के राधेश्याम मिश्रा, व्यवसायी संघ कोट बाजार के कैलाश कुमार हिसारिया, नगर परिषद के सभापति सुवंश राय, प्रदेष भाजपा कार्यसमिति सदस्य विष्वजीत पाठक, विशाल कुमार, विजय स्वर्णकार, नितेष भारद्वाज, महंत सिया किशोरी शरण मुठिया बाबा, महंत हरि नारायण दास, निशित सिंह, तरुण आनंद, आलोक कुमार, ओम प्रकाश साह, मदन प्रसाद, शिव कुमार अग्रवाल, सुरेष जालान व बाल किशन सुंदरका समेत अन्य ने सराहनीय योगदान दिया. इस दौरान भाजपा विधायक ने लोगों के इत्साह व श्रद्धा पर प्रसन्नता व्यक्त की.

– बाल्मीकि

चीन हो रहा परेशान

पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से चीन घबरा गया है. परेशानी का आलम है कि विवाह पंचमी के मौके पर पीएम मोदी के जनकपुर दौरा को भी रदद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आगामी 2 से 4 दिसंबर तक बिहार के वैशाली में आहूत संत समागम की सफलता को लेकर सीतामढ़ी पहुंचे श्री सिंह ने कहा कि नमो की यात्रा नही होने से मधेशियों में रोष व्याप्त हो गया है. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के बयानों को अनर्गल करार देते हुए राजधर्म का पालन में सीएम को अक्षम बताया. मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रो रामचंद्र सिंह, निशिथ सिंह, अरविंद कुमार सिंह, श्यामचंद्र सिंह अमिताभ, नीतेश भारद्वाज व अरुण कुमार गुप्ता समेत अन्य थे.

– ब्रजेष

कोरामीन से नहीं होगा फायदा

युवा रालोसपा के जिलाध्यक्ष अमित सहाय ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा को असरहीन कोरामीन की संज्ञा दी है. कहा है कि नीतीश जनता के बीच अपना विश्वास खो चुके है. अब किसी प्रकार पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने की फिराक में है. अमित ने कहा कि जब से बिहार में जदयू अलग हुई है इसे अपनी अस्तित्व रक्षा के लाले पर रहे है. विकास के बहाने राजनीति करने वालों की पोल अब खुल चुकी है. आगामी विधानसभा चुनाव में रालोसपा – लोजपा व भाजपा गठबंधन बिहार के तमाम सीटों पर सफलता का परचम लहरायेगी.

बच्चों ने चलाया अभियान

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डीएवी स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता अभियान की कमान थामी. प्राचार्य डॉ. पूनम शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक व छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर व आसपास के सडकों की वृहद सफाई की गयी. कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य ने बच्चों को स्वच्छता से लाभ की जानकारी दी. कहा कि स्वच्छता के अभाव में स्वस्थ्य मानसिकता का विकास असंभव है. एक सप्ताह तक चला अभियान के दौरान बच्चों ने साफ – सफाई को लेकर आम लोगों को जागरूक करने में अहम भागीदारी दी. अभियान में शिक्षक बीएन भटटाचार्य, मो मुउजुददीन, दीपेंद्र कुमार, हर्षबर्द्धन कुमार, मनोज कुमार व एसएस झा समेत अन्य थे.■

– विभा

सीतामढ़ी

अंग्रेजी शासन काल में शाहाबाद (संप्रति बक्सर) जिले के नवानगर अंचल के सिकरौल लख पर सोन नहर विभाग का कार्यालय था. जेपी के पिता हरषु दयाल श्रीवास्तव विभाग में जिलादार के पद पर कार्यरत थे और वहीं सरकारी क्वार्टर में सपरिवार रहते थे. लिहाजा वर्षों तक वहीं पर जेपी का बचपन गुजरा था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. जेपी जिस कमरे में रहते थे, वह आज खंडहर के रूप में मौजूद है. लेकिन राजद के 15 साल के शासन काल में जेपी की बचपन की स्मृतियों को संजोने की याद नहीं आई.

उपेक्षा का दंश झेल रहे साहित्यकार

विदेह राजा जनक की मिथिला नगरी में पग-पग पर धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य की पताका लहराती है. ज्योतिष शास्त्र के साथ वेदांत पर मजबूत पकड़ रखने वालों की एक श्रृंखला मिथिला को विश्व पटल पर पहचान दिलाती रही है. ऐतिहासिक स्थलों की पूर्णता से परिपूर्ण मिथिला क्षेत्र में ही सीतामढ़ी एक ऐसा पावन स्थल है, जहां जगत जननी मां जानकी पुनौरा धाम में धरती की कोख से अवतरित हुई थी. जिले में साहित्य व कला के साधकों को अब तक समुचित सम्मान नहीं मिल सका है. नृत्य, संगीत व साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी को मुकाम मिला है तो वह उसके खुद की बदौलत ही संभव हो सका है. सरकारी, प्रशासनिक अथवा जनप्रतिनिधियों के स्तर पर अब तक इस दिशा में किसी भी प्रकार की पहल नही की जा सकी है. हास्य कवि सम्मेलनों की श्रृंखला जिले में चलाई जा रही है, लेकिन स्थानीय साहित्यकारों को मंच तो दूर कोई पूछना तक मुनासिब नहीं समझ रहा है ...

अलाउद्दीन बिस्मिल

आशा प्रभात

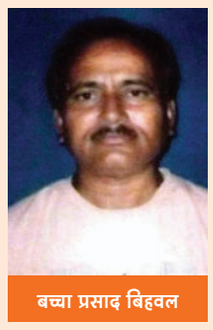
बच्चा प्रसाद बिहवल

गीतकार गीतेश

मुरलीधर झा मधुकर

राम किशोर सिंह चकवा

संगीता चौधरी

सत्येंद्र मिश्रा

सुरेश लाल कर्ण

सुरेश वर्मा

उमा शंकर लोहिया

वाल्मीकि कुमार

कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. किंतु अगर दर्पण ही धुंधला हो जाए तो उस समाज की सहज ही कल्पना की जा सकती है. बड़े मंचों से ऐसी ही कुछ बातें तो की जाती हैं, मगर साहित्य के धुंधले दर्पण को साफ करने का प्रयास करने को कोई तैयार नहीं है. यह बात ऐसी जगह के बारे में की जा रही है जिसे लोग जगत जननी मां जानकी के पावन प्राकट्य स्थली के रूप में जानते और पूजते हैं. वैसे तो लंबे अर्से से सीतामढ़ी में साहित्य साधको की जमात साहित्य के विकास को लेकर हर संभव प्रयास करते रहे हैं. किन्तु समुचित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण अब तक जिले को साहित्यिक तौर पर पहचान नहीं मिल सकी है. ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए सिर्फ समाज अथवा प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि ही दोषी हैं. कुछ हद तक मानें तो इसके लिए साहित्यकार भी कसूरवार हैं.

अब तक सीतामढ़ी की गौशाला में पिछले सवा सौ साल से गोपाष्टमी के अवसर पर अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है. देश के नामचीन कवियों को बुलाकर कार्यक्रम में लाखों खर्च की जाती है, परंतु स्थानीय साहित्यकारों को कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रण तक नही दिया जाता है. यह केवल गौशाला ही नही बल्कि जिले में आयोजित होने वाले तमाम कवि सम्मेलनों का हाल रहा करता है. आलम है कि जिले के साहित्यकार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

सीतामढ़ी जिले में अब तक तकरीबन आधा दर्जन संस्थाओं का गठन कर साहित्य को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है. इसमें अगर गौर किया जाये तो काम से अधिक नाम कमाने की मंशा झलकती दिख रही है. साहित्य की गलियों में अलख जगाने वालों की मानें तो सीतामढ़ी में अब तक काव्य संगम की कमान मैथिलीबल्लभ शरण परिमल, कला संगम की गीतकार गीतेश, प्रसाद साहित्य परिषद की ई. सचिंद्र कुमार हीरा, बज्म-ए-शम्स का अलाउद्दीन बिस्मिल, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की संगीता चौधरी एवं बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद की कमान प्रो. गणेश राय के हाथ में है. जबकि जिले से प्रकाशित हो रही एक मात्र त्रैमासिक पत्रिका 'नई सुवह' के संपादन का कार्य प्रो. दशरथ प्रजापति कर रहे है. उनके अलावा साहित्यकार आशा प्रभात भी ऐसे नामों में हैं, जिनकी अनगिनत रचनाएं देश-विदेशों तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं. उनकी कहानी 'कैसा सच', उपन्यास 'जाने कितने मोड़' हिन्दी व उर्दू में इतनी सफल रही कि इस पर सिरियल भी तैयार किये गये. 'धुंध में उगा पेड़' का आलम रहा कि पाकिस्तान में एक उर्दू धारावाहिक तक बनाया गया. जबकि 'मैं और वह' एवं ' मैं जनक नंदिनी ' भी चर्चित रहे. काव्य में भी आशा प्रभात की 'दरीचे' एवं 'मरमूज' काफी चर्चित रही है. प्रभात की रचना 'कैसे होगा हमारा वसर दोस्तों...' काफी चर्चित गजल रही है.

जिले के साहित्य साधकों की मेहनत अब तक मुकाम को नहीं पा सकी है. इसके लिए अब सामाजिक, प्रशासनिक व सरकारी स्तर पर भी पहल आवश्यक प्रतीत होने लगी है. सीतामढ़ी जिले के अलग-अलग स्थानों पर साहित्य जगत में हरियाली लाने को अथक प्रयास करने वाले गीतकार गीतेश की रचना 'जिंदगी संघर्ष है तो जीत भी है...', सत्येंद्र मिश्र की ' रेत पर खींची गयी कोई लकीर मै हूं ...' अलाउद्दीन बिस्मिल की रचना ' दर्द में औरो के दिल चीखता है मेरा ...' सुरेश वर्मा की 'देर तक ये दर्द दिल को सालता रहा...' राम किशोर सिंह चकवा की 'मत जला दूसरो का घर, तेरा घर भी बगल में है ...' संगीता चौधरी की 'मुझे मेरे परदेश की तस्वीर दिखायी गयी..' उमा शंकर लोहिया की ' दबे सहमे मजलूम को बेजुबान मत कहना...' मुरलीधर झा मधुकर की 'सप्त सुरों से सजी है गीत जिंदगी...' सुरेश लाल कर्ण की 'आया होगा पवन झकोरा, मेरे सुंदर गांव में...' एवं बच्चा प्रसाद बिहवल की रचना 'अपने सारे रूठ गये है...' कुछ ऐसी रचनाओं में शुमार है, जिसका जवाब तलाश करना काफी मुश्किल है. सीतामढ़ी के साहित्य जगत में डॉ. आनंद प्रकाश वर्मा, ई. सचिंद्र कुमार हीरा, डीएवी स्कूल के प्राचार्य अनंत सहाय, डॉ. अवधेश अरुण, सैयद अलाउद्दीन, गुफरान राशिद व डॉ. शत्रुघ्न यादव सरीखे कुछ ऐसे भी है, जिनकी मंशा जिले में साहित्य का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना है.

साहित्य जगत से मतलब रखने वालों की मानें तो जिले में साहित्य की नींव कमजोर नहीं है. आवश्यकता है इसकी मजबूत इमारत का रंग रोगन अर्थात नये सिरे से स्थापित करने की. इसके लिए साहित्यकारों के साथ प्रशासनिक महकमा व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अहम है. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जिला के साहित्य का परचम राज्य से लेकर राष्ट्रीय फलक पर गौरव के शिखर को छू सकती है. जिले में अलग-अलग संगठनों एवं संस्थाओं के अलावा राजनीतिक स्तर पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों में जिले के साहित्यकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है. बताया जाता है कि अब तक सीतामढ़ी की गौशाला में पिछले सवा सौ साल से गोपाष्टमी के अवसर पर अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है. देश के नामचीन कवियों को बुलाकर कार्यक्रम में लाखों खर्च की जाती है, परंतु स्थानीय साहित्यकारों को कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रण तक नही दिया जाता है. यह केवल गौशाला ही नही बल्कि जिले में आयोजित होने वाले तमाम कवि सम्मेलनों का हाल रहा करता है. आलम है कि जिले के साहित्यकार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. वे न तो प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों के समक्ष पहुंच पाते है और न ही अपनी भावना से उन्हे अवगत ही करा पाते है. 'घर की मुर्गी दाल बराबर' वाली कहावत इन साहित्यकारों पर लागू होकर रह जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

कैदखाने में जेपी की मूर्ति

जयमंगल पांडेय

जिस तानाशाही शासन के विरुद्ध लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था और इस क्रांति से राजनीति में स्थापित होने वाले उनके राजनीतिक शिष्यों की सरकार में वह खुद तानाशाही व्यवस्था के शिकार हो गए हैं. यही कारण है कि उनके शिष्यों की सरकार की जेल में जेपी नौ महीनों से कैद हैं.

बेशक आप इस बात से चौंक गए होंगे. भले ही जेपी आज जीवित नहीं हैं लेकिन महापुरुषों की मूर्तियां प्रतीक होती हैं, जो भावी पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित करती है. लेकिन दुर्भाग्य से लोक नायक जय प्रकाश नारायण की आकर्षक मूर्ति सार्वजनिक स्थल पर स्थापित होने के बदले बक्सर जिले के सिकरौल पुलिस के कैदखाने में बंद है. यहां राजनीतिज्ञों और महापुरुषों की मूर्तियां राजनीतिक फायदे के लिए ही स्थापित की जाती हैं. जेपी के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए मोहरे के तौर पर प्रयोग किया जाता है. इस साल लोकसभा चुनाव के समय ही राजनीतिक लाभ के लिए ही राजद नेताओं द्वारा बक्सर जिले के सिकरौल लख के इसी स्थान पर मूर्ति स्थापना की योजना बनाई गयी जहां वर्षों उनका बचपन गुजरा था. लेकिन इलाके में बचपन की स्मृतियों को जीवंत करने वाली जेपी की मूर्ति निश्चित स्थल पर स्थापित होने के बदले बेआबरू होकर पुलिस थाने में नौ माह से कैद है. लेकिन इतने दिनों के बाद भी मूर्ति को सम्मान देने की याद किसी को नहीं आई.

बक्सर

अंग्रेजी शासन काल में शाहाबाद (संप्रति बक्सर) जिले के नवानगर अंचल के सिकरौल लख पर सोन नहर विभाग का कार्यालय था. जेपी के पिता हरषु दयाल श्रीवास्तव विभाग में जिलादार के पद पर कार्यरत थे और वहीं सरकारी क्वार्टर में सपरिवार रहते थे. लिहाजा वर्षों तक वहीं पर जेपी का बचपन गुजरा था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. जेपी जिस कमरे में रहते थे, वह आज खंडहर के रूप में मौजूद है. लेकिन राजद के 15 साल के शासन काल में जेपी की बचपन की स्मृतियों को संजोने की याद नहीं आई. इस साल लोकसभा चुनाव के समय सिकरौल लख की सरकारी जमीन पर राजद नेताओं ने चबूतरा बनाकर जेपी की 85 किलो की संगमरमर की मूर्ति बनाकर रख दी. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 8 मार्च 2014 को मूर्ति का अनावरण कर लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले थे. इससे पहले ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर आचार संहिता लागू कर दी गई. इसके बाद सोन नहर विभाग के अभियंताओं ने इसमें अड़ंगा लगा दिया. लेकिन एक महीने पहले से चबूतरा निर्माण चल रहा था तो विभाग को सरकारी जमीन के अतिक्रमण का ख्याल नहीं आया. इसके बाद जिलाधिकारी ने मूर्ति स्थापना पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि विभाग द्वारा एनओसी नहीं दी गई है. विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने सिकरौल पुलिस से लिखित शिकायत कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई. पुलिस ने इस मामले में एक सनहा दर्ज कर लिया. इसके बाद सोन नहर के अवर प्रमंडल पदाधिकारी नावानगर के अचंलाधिकारी ने 4 मार्च 2014 को जेपी की मूर्ति उठाकर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने चबूतरे को ध्वस्त कर दिया. सिकरौल के थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि आज तक जेपी की मूर्ति लेने का दावेदार कोई नहीं आया. मूर्ति सुरक्षित रखी गई है. अहम सवाल यह है कि जेपी के राजनीतिक शिष्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लालू प्रसाद के ही हाथों में पिछले लगभग 25 सालों से राज्य की सत्ता है. दोनों राजनीतिक फायदे के लिए उनके विचारों को भुनाते रहते हैं. फिर भी दोनों को मूर्ति की दुर्गति की याद नहीं आई.■

जेपी के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए मोहरे के तौर पर प्रयोग किया जाता है. इस साल लोकसभा चुनाव के समय ही राजनीतिक लाभ के लिए ही राजद नेताओं द्वारा बक्सर जिले के सिकरौल लख के इसी स्थान पर मूर्ति स्थापना की योजना बनाई गयी जहां वर्षों उनका बचपन गुजरा था. लेकिन इलाके में बचपन की स्मृतियों को जीवंत करने वाली जेपी की मूर्ति निश्चित स्थल पर स्थापित होने के बदले बेआबरू होकर पुलिस थाने में नौ माह से कैद है. लेकिन इतने दिनों के बाद भी मूर्ति को सम्मान देने की याद किसी को नहीं आई.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

08 दिसंबर–14 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

जश्न-ए-जन्मदिन

समाजवाद बबुआ बग्घी से आई

प्रभात रंजन दीन

मुलायम सिंह यादव ने आजम खान की पत्नी को राज्यसभा का सांसद बनाया तो आजम ने शाहंशाहाना तरीके से मुलायम का जन्मदिन मनाकर उपकार चुकाया, लेकिन उपकार करने और चुकाने की प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी ने क्या खोया, उसकी आत्मसमीक्षा समाजवादियों को ही करनी चाहिए. मायावती के आलीशान जन्मदिन समारोहों का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी को आम नागरिकों का सैद्धान्तिक समर्थन मिला था, लेकिन वही समाजवादी सिद्धांत मायावाद के सिरहाने जाकर छुप गया, इसे लेकर आम लोगों में चर्चा है और नाराजगी भी है. रामपुर की सड़कों पर शाही बग्घी पर समाजवाद को सवार देख कर नवाबों की घिघ्घी बंध गई और आम जनता समाजवाद के सामंतवादी चकाचौंध में खो गई. खुद मुलायम सिंह इतने गदगद और आह्लादित थे कि उन्होंने रामपुर में आयोजित जन्मदिन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान मिला है. ऐसा सम्मान शायद ही जिंदगी में फिर कभी मिले. मुलायम ने आजम की तारीफ करते हुए कहा कि आजम ने जो सम्मान दिया उसे बोलकर नहीं चुकाया जा सकता. वहीं आजम, जिन्होंने मुलायम के जन्मदिन समारोह की भव्यता पर उठी उंगली के जवाब में कहा था कि समारोह के आयोजन में तालिबानी फंड है, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद इब्राहिम ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है और कुछ जो मर आतंकवादी हैं उनसे आया है. मायावती और मुलायम के जन्मदिन समारोह में फर्क इतना ही था कि मुलायम के जन्मदिन पर धन की वसूली नहीं की गई, लेकिन समारोह की भव्यता में कोई फर्क नहीं था. हालांकि खुद सपाई ही कहते हैं कि लोहिया के शिष्य और समाजवाद के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्म दिवस समारोह जिस तरह से रामपुर में मनाया गया उसने मायावती के जन्मदिन की भव्यता को बहुत पीछे छोड़ दिया है. वाकई, मुलायम के जन्मदिवस समारोह की तैयारियों के बारे में आप जानेंगे, तो उसकी भव्यता का सहज अंदाजा लगेगा. मुलायम का जन्मदिन मनाने के लिए इंग्लैंड से विशेष विक्टोरिया बग्घी मंगाई गई थी और दिल्ली से खास तौर पर बनवाया गया 75 फीट का चार सौ किलो का केक मंगवाया गया था. समाजवादी नेता मुलायम सिंह का जिस पंडाल में जन्म दिवस समारोह मनाया गया वह दो करोड़ रुपये का था. रंगारंग कार्यकम पर तकरीबन 16 लाख रुपये खर्च किए गए. शहर भर में लाइव प्रसारण के लिए एलईडी टीवी लगाए गए थे. मेहमानों के आने–जाने के लिए चार विमान लगाए गए थे. सवा करोड़ रुपये की लागत से शहर में 125 तोरण द्वार बनाए गए थे. हजार मेहमानों को न्यौता दिया गया था और उन सबके लिए अलग–अलग गाड़ियां मंगाई गई थीं. पूरा रामपुर शहर धो दिया गया था. पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा था, लेकिन पूरे शहर में आम लोगों के मूवमेंट पर रोक लग गई थी.

रामपुर के स्कूलों में 21 नवम्बर से ही छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन स्कूली बच्चों को जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए उपस्थित रखा गया था. दो दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चे कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए तो कहीं रंगोली बनाते हुए तो कहीं सड़क किनारे खड़े होकर मुलायम सिंह अमर रहें के नारे लगाते नजर आ रहे थे. यह प्रायोजित नजारा था. कार्यक्रम आम लोगों की पहुंच से दूर था. आम आदमी केवल एलईडी पर चल रहा लाइव शो ही देख सकता था. प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट रामपुर में हाजिर थी. प्रदेश सरकार का पूरा पुलिस प्रशासन का अमला रामपुर में तैनात था. जौहर यूनिवर्सिटी में जो केंद्रीय पंडाल बनाया गया था उसके लिए दो करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया था. इसके अलावा रामपुर जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग ने अलग से करीब 30 लाख रुपये खर्च किए. हंसराज हंस को पौने बारह लाख रुपये दिए गए, फिरोज खान को साढ़े तीन लाख रुपये मिले और साबरी ब्रदर्स को साढ़े चार लाख रुपये दिए गए.

इसके अलावा नगर विकास विभाग ने भी अपने फंड से खर्च किया. मोटी फीस पर कथक और बैले डांसरों को भी बुलाया गया था. 22 नवम्बर को रामपुर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई थी और लखनऊ हतप्रभ थी. मुलायम सिंह के 75 साल के अब तक के जीवन में ऐसा जन्मदिन पहली बार मना. जन्म दिवस समारोह की सारी तैयारी आजम खान की निगरानी में हुई थी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इतने कृतकृत्य थे कि वे यह कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि आजम साहब, इतना सम्मान देकर आपने मेरे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया है, मुझे कुछ करना होगा. मैं नेताजी को जन्मदिन की और आजम खान साहब को उनके इंतजामात की बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं. आज तक ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मना होगा जैसा आजम साहब ने मनवा दिया.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

सामंतवादी जश्न पर समाजवादी रफुगीरी

सैफई महोत्सव की तरह मुलायम के भव्य जन्मदिवस समारोह का विवाद तूल पकड़े उसके लिए जरूरी था ऐसा कुछ जनताऊ उपक्रम करना जिससे मुलायम के समाजवादी रवैये का लोगों को दर्शन मिल सके. इसके लिए जन्म दिवस समारोह के अगले ही दिन अवसर मिला और मौका था लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास कार्यक्रम का. इस कार्यक्रम में मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खूब खरी-खोटी सुना दी. मुलायम ने विकास योजनाओं की धीमी गति के लिए प्रदेश सरकार को उलाहना दिया और कहा कि रेंग रही विकास योजनाओं की गति बढ़ाकर उन्हें समय से पूरा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम ही नहीं होने चाहिए, उनके उद्घाटन का कार्यक्रम भी होना चाहिए. विकास योजनाएं तो बहुत हैं, मगर वे रेंग रही हैं. शिलान्यास कार्यक्रम तो बहुत सुनाई पड़ते हैं, मगर उद्घाटन की बात सुनाई नहीं पड़ती. मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर देखते हुए कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं विकास योजनाओं का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन करता था. मैं जब कभी किसी योजना का शिलान्यास करता था तो उसी समय उद्घाटन की तारीख भी तय कर देता था. मुलायम ने अखिलेश सरकार के मंत्रियों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें परिणाम देने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि पार्टी संगठन सरकार से ऊपर है. आप तभी तक मंत्री रह पाएंगे जब तक संगठन आप को चाहेगा. आप सभी मंत्रियों और अधिकारियों को बताना चाहिए कि विकास परियोजनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं. मुलायम की इस फटकार और जनरुचि की बातों को खुद सपाई ही जन्म दिवस समारोह की भव्यता पर समाजवादी रफुगीरी बताते हैं. ■

रामपुर के स्कूलों में 21 नवम्बर से ही छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन स्कूली बच्चों को जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए उपस्थित रखा गया था. दो दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चे कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए तो कहीं रंगोली बनाते हुए तो कहीं सड़क किनारे खड़े होकर मुलायम सिंह अमर रहें के नारे लगाते नजर आ रहे थे.

जन्म दिवस पर प्रतिक्रियाएं

“खुद को आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया का अनुयायी बताने वाले मुलायम सिंह इस तरह से जन्मदिन मनाएंगे तो उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा. मुलायम यादव दीर्घायु हों और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएं यह हमारी कामना है, लेकिन शाही जन्मदिन उचित नहीं है. इस तरह से जन्मदिन मनाना प्रदेश में अभाव से उत्पीड़ित जनता के जले पर नमक छिड़कना है. अगर वो अपना जन्मदिन गरीबों की बस्ती में मनाते तो अच्छा होता.”

– डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

“यह समाजवाद नहीं, सामंतवाद है.”

– संबित पात्रा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

“मायावती अपना जन्मदिन हमेशा सादगी से मनाती हैं. इस तरह का तमाशा उन्होंने कभी नहीं किया. मुलायम ने इस तरह से जन्मदिन मना कर लोहिया के विचारों को चांटा मारा है और समाजवाद का मखौल उड़ाया है.”

– स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी नेता प्रतिपक्ष

“समाजवादी पार्टी की सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है. यह जश्न समाजवादी पार्टी के लोगों के सामंती विचार को व्यक्त करता है.”

– सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी नेता

भारतीय समाज की दशा बताती जेलें

सूफी यायावर

आ भी यह खबर सुर्खियों में रही कि भारतवर्ष की जेलों में अधिकांश कैदी कमजोर वर्ग के हैं और उनमें भी अधिकांश दलित हैं. अपराध की जातिगत समीक्षा नहीं हो सकती. अपराध की वर्गीय समीक्षा हो सकती है. वर्गीय खाई बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा और जेलों में भीड़ बढ़ेगी. चलिए हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करें. आधिकारिक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जेलों की हालत बहुत खस्ता है. जेलों में निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक कैदी ठुंसे हुए हैं. सजायाफ्ता कैदियों की जितनी तादाद है उससे तीन गुना अधिक ऐसे कैदी बंद हैं जिनके मामले वर्षों से विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं. उत्तर प्रदेश की जेलें यातना गृह के रूप में तब्दील हो गई हैं. इसके बावजूद सरकार जेल सुधार के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है. कैदियों के मानवाधिकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है.

कुछ अर्सा पहले का आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 81027 कैदी हैं जबकि यहां की जेलों में केवल 48298 कैदियों केरखने की क्षमता है. यानी प्रदेश की जेलों में कैदियों की 167 प्रतिशत से अधिक भीड़ है. यह भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि जेलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. जेलों में बन्द दो तिहाई कैदी ऐसे हैं जिनके मामले अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं. दोष सिद्ध कैदियों की तादाद 25567 है जबकि विचाराधीन कैदियों की संख्या 55460 है. न्याय में अवांछित देरी की वजह से यह भीड़ जेलों में बंद है. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान देने वाला नहीं.

आधिकारिक सूचनाएं यह भी बताती हैं कि गोरखपुर में 22, एटा में 11, फतेहपुर में 5, सीतापुर में 17 तथा खीरी की जेल में 27 ऐसे कैदी बंद हैं जो किए गए अपराध की अधिकतम अवधि का आधे से अधिक की सजा दोष सिद्ध होने केपहले ही भोग चुके हैं. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जब उत्तर प्रदेश केकारागार मंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि वे जेल में बन्द कैदियों की रिहाई के लिए अभियान छेड़ेंगे. जेलों में सजा काट चुके लोगों की रिहाई के लिए वे फिल्म अभिनेता सलमान खान से भी सम्पर्क करेंगे, जिन्होंने ऐसे लोगों को मदद करने की इच्छा जाहिर की थी. राजा भैया ने मंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता उन कैदियों की रिहाई की ही रखी थी जो अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके हैं, लेकिन जुर्माना अदा नहीं कर सके. सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन ने उत्तर प्रदेश की जेलों में अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके लेकिन जुर्माना अदा नहीं करने के कारण जेल में बंद कैदियों की रिहाई में आर्थिक मदद की पेशकश की थी. राज्य में ऐसे तीन सौ कैदी हैं, जिनमें अधिकतर पांच केंद्रीय जेलों में बंद हैं. ऐसे कैदियों की रिहाई पर करीब पचास लाख रुपए खर्च होंगे.

विडम्बना यह है कि राज्य सरकार की ओर से जुर्माना अदा कर कैदियों को छुड़ाने का कोई प्रावधान नहीं है. तब खुद कारागार मंत्री ने यह माना था कि प्रदेश की जेलों को प्रताड़ना गृह बना दिया गया है. बंदियों के साथ राज्य के किसी भी जेल में ठीक व्यवहार नहीं होता. जाड़े में न तो उन्हें कंबल दिए जाते हैं और न उनके इलाज का कोई इंतजाम होता है. कैदियों का खाना भी घटिया ही होता है. ■

> रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जब उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि वे जेल में बन्द कैदियों की रिहाई के लिए अभियान छेड़ेंगे. जेलों में सजा काट चुके लोगों की रिहाई के लिए वे फिल्म अभिनेता सलमान खान से भी सम्पर्क करेंगे, जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने की इच्छा जाहिर की थी. राजा भैया ने मंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता उन कैदियों की रिहाई की ही रखी थी जो अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माना अदा नहीं करने के कारण अभी तक जेल में हैं.

कानून और पूर्वाग्रह

एस. आर. दारापुरी (रि.आईपीएस)

स भी देश आधुनिकता और प्रगति का दावा बढ़-चढ़ा करते हैं. फिर भी सभी देश वर्गों का भद्दा ध्रुवीकरण, समाज के पायदान पर पड़े लोगों का शोषण, धन संपत्ति से वन्चितिकरण, सत्ता और विशेषाधिकार की व्यवस्था को मजबूत करता है. भारत में भी इसी प्रक्रिया का उदाहरण देखा जा सकता है. इसी महीने जेलों पर जारी की गई सरकारी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दलित, आदिवासी और मुसलमान जो कि समाज का अति पिछड़ा वर्ग है देश की जेलों में उनकी संख्या अधिक है. सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 39% है जबकि जेलों में इनकी संख्या 53% है. हाल में ही जेलों के बारे में जारी की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि हमारी व्यवस्था किस प्रकार विषमतावादी, अमीरों की पक्षधर और गरीबों केविरोध में खड़ी है. उदाहरण केलिए 2013 में भारत की जेलों में 4.2 लाख बंदी थे. इनमें से 20 फीसदी मुसलमान थे जबकि 2001 की जनगणना केअनुसार इनकी आबादी देश की कुल आबादी का केवल 13 प्रतिशत थी. दलितों की 17 प्रतिशत आबादी के खिलाफ जेलों में उनकी संख्या 22 फीसदी और आदिवासियों की 9 प्रतिशत आबादी केखिलाफ 11 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जेलों के बारे में 1995 से और 1999 से जातिवार दिए जा रहे आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि पिछले पंद्रह साल से दलित, मुस्लिम और आदिवासी कैदियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. साफ तौर पर यह हमारी व्यवस्था में जाति, साम्प्रदाय और वर्ग आधारित पूर्वाग्रह का ही परिणाम है. ये कानून का समान रूप से लागू करने में बहुत बड़ी बाधा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जश्न-ए-जन्मदिन

समाजवाद बबुआ बग्घी से आई

पृष्ठ 17 का शेष

जश्न जारी रहना चाहिए...

इधर जन्म दिवस समारोह का आलीशान जश्न चलता रहा, उधर भगदड़ में महिलाएं कुचली जाती रहीं. एक महिला की मौत भी हो गई, लेकिन इससे जश्न केउल्लास पर कोई फर्क नहीं पड़ा. मुलायम केजन्मदिन पर उनकेसांसद भतीजे धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र बदायूं में कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा था. इस कार्यक्रम में भगदड़ मच गई जिसमें दर्जनों महिलाएं कुचली गईं और गंभीर रूप से जख्मी हुईं. भगदड़ में एक बुजुर्ग महिला की तो मौत भी हो गई. इस मौत से रामपुर के जश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ा, न कोई शोक संवाद ही जारी करने की कोई औपचारिकता हुई. किसी गरीब महिला की ऐसे कार्यक्रम में हुई मौत से समाजवाद का जश्न आखिर क्यों रुके!

बच्चों की प्रताड़ना की होगी जांच

रामपुर में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह के लिए स्कूलों की छुट्टी करने और स्कूली बच्चों को मुलायम सिंह जिंदाबाद केनारे लगाने केलिए घंटों खड़े रखने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा भेजी शिकायत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शीघ्र जांच करेगा. जन्मदिन समारोह के लिए स्कूलों की छुट्टी कर बच्चों को नारे लगाने के लिए घंटों खड़ा रखने को बाल अधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए नूतन ठाकुर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत भेजी थी. शिकायत में कहा गया कि एक नेता के लिए नारे लगाने के लिए बच्चों को घंटों खड़े रखना आईपीसी की धारा 342 में अपराध है. इसके साथ-साथ 21 और 22 नवंबर को रामपुर के डीएम सीपी त्रिपाठी द्वारा इस जश्न के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश देना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ है. बाल आयोग से इन दोनों बिन्दुओं पर जांच कर डीएम रामपुर सहित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने का आग्रह किया गया है ताकि यह भविष्य में बाल अधिकारों का हनन करने वालों के लिए यह एक उदाहरण बन सके. आयोग के सदस्य-सचिव ने आश्वासन दिया है कि आयोग इस मामले की शीघ्र जांच करेगा.

क्षुब्ध और क्षुद्र लोग उठा रहे उंगली : चौधरी

मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह को तूल देने के रवैये पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर उसकी सरकार बनाई है. इससे क्षुब्ध विपक्षी दल जब प्रदेश में अशांति फैलाने में विफल रहे तो अब मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं. इन विपक्षी पार्टियों को वे दिन भूल गए जब एक नेता केजन्मदिन पर ठाठबाट सजता था. उन्हें नोटों की माला पहनाने के लिए जबरन चंदा वसूली होती थी जिसमें एक विधायक ने तो पीट-पीटकर एक अभियन्ता की ही जान ले ली थी. कुछ अफसरों ने भी उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का रामपुर में जन्मदिन का समारोह कार्यकर्ताओं के स्वतःस्फुर्त उत्साह और अथाह प्रेम का प्रदर्शन था. सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने सादगी और ईमानदारी का जीवन जीते हुए गांव-गरीब, किसान, मुसलमान की लड़ाई लड़ी है. उनका जीवन समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में बीता है. जो लोग इस विचारधारा से चिढ़ते हैं वे अपनी क्षुद्र मानसिकता दर्शाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. ■

खाकी और खादी का गठजोड़

बढ़ती आतंकी और आपराधिक गतिविधियां

हरिशंकर वर्मा/अजय गुप्ता

ने पाल सीमा से जुड़े होने के कारण लखीमपुर-खीरी जिले में बढ़ी आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को काबू में करना पुलिस के लिए चुनौती है. इसकेलिए लगातार आईएस और आईपीएस अफसरों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है और प्रदेश सरकार की छवि पर बट्टा भी लगा. अखिलेश सरकार अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. इन वर्षों में सरकार ने प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाने का भी कार्य किया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री केमाथे पर बल भी पड़े. तमाम प्रशासनिक फेरबदल भी किए गए, लेकिन अखिलेश सरकार को इसमें कामयाबी नहीं मिली. प्रदेश सरकार में अपराधियों से निपटने की इच्छा शक्ति की कमी का होना और पुलिस की कार्यशैली में लापरवाही दोनों ही इसके मुख्य कारण हैं. प्रदेश में आए दिन किसी न किसी बहाने साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें सर उठाती रही हैं जिससे कानून व्यवस्था सवालों केघेरे में आती रही है. ऐसी ही स्थिति से नेपाल से लगे प्रदेश केसबसे बड़े जनपद लखीमपुर खीरी को भी गुजरना पड़ा जहां पर सत्ता पक्ष केही एक प्रभावशाली नेता की पुत्री का अपहरण दूसरे समुदाय केयुवक द्वारा किए जाने से जनपद में साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ा और स्थितियां बेकाबू हो जाने के कारण तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी.

इस संवेदनशील सीमाई जिले में गायों की तस्करी, दो मुंहे सापों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा पुरजोर चलता है. यहां के ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब की भट्ठियां, अवैध खनन और देह व्यापार के धंधे पुलिस के संरक्षण में चलते रहे हैं. जुए के अड्डे एवं भारी मात्रा में सट्टा कारोबारी तो यहां की आपराधिक गतिविधियों में आम हैं. यहां की आपराधिक और साम्प्रदायिक गतिविधियों को बहुत हद तक काबू में लाने वाले मौजूदा एसपी अरविंद सेन कहते हैं कि यदि पुलिस का रहन-सहन व ड्यूटी आवर्स नियत कर दिए जाएं और डे-नाइट केअधिकारी अलग-अलग हो जाएं तो बेहतर पुलिसिंग केकाफी अच्छे परिणाम आ सकते हैं. श्री सेन यह मानते हैं कि पुलिसकर्मियों केदायित्वबोध में कमी आई है इसीलिए परिणाम बेहतर नहीं मिलते. उनका मानना है कि अपराध को छिपाने से अपराध बढ़ते हैं और अपराध पंजीकृत करने से अपराध कम होते हैं, क्योंकि जब अपराध का पंजीकरण होगा तो उसकेवर्क आउट की भी चिंता होगी.

जिले में पुलिस और अपराधियों की साठगांठ का हाल यह है कि छापेमारी के पहले ही उन्हें सूचना हो जाती है और छापामार दस्ते को मौकेपर कुछ नहीं मिल पाता. अपराधियों से मिलीभगत करने वाले खाकीधारियों को चिन्हित कर उन्हें दंडित करने का अभियान चलाने केबाद इस पर थोड़ा अंकुश लगा है. पहले पुलिस पर अपराधी भारी पड़ते थे, अब अपराधियों पर पुलिस भारी पड़ने लगी है. लेकिन फिर भी जनपद की सीमा लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर तक विस्तृत होने केकारण पुलिस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है. अब ऐसे सफेदपोशों की भी पहचान कराई जा रही है जो अपराधियों और पुलिस दोनों से साठगांठ रखते हैं और लिंक का काम करते हैं. इन पर निगरानी का ही नतीजा है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर केतस्करों और अपराधियों की गिरफ्तारी का संभव हो पाना.

तराई जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है. इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी हैं, जिसका फायदा उठा कर अपराधी जघन्य वारदातों को अंजाम देकर नेपाल भाग जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय कानूनी दावपेंच केचलते पुलिस बेबस भी बनी रहती है और पुलिस की मिलीभगत भी रहती है. पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन ने जोखिम उठाकर नेपाल में छिपे इनामी बदमाश डालू और बग्गा जैसे खुंखार अपराधियों को पकड़वाने का प्रयास किया पर वहां केकानून केचलते पुलिस को मायूस होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा. खुली सीमा केचलते सीमा पर तैनात कस्टम, सशस्त्र सीमा बल व पुलिस की मिलीभगत से तस्करी यहां केलिए कोई अजूबी बात नहीं है. पुलिस व सीमा सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सुपारी, इलायची, अनाज, खाद, कबाड़ और पशुओं आदि की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. नेपाल केरास्ते भारत की अर्थ व्यवस्था को खोखला करने केलिए नकली नोटों को पंप किया जा रहा है और ऐसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां जनपद की पुलिस केलिए चुनौती बनी हैं. जिले केपुलिस अधीक्षक अरविंद सेन केसाथ-साथ सीओ धौरहरा मनोज कुमार यादव, सीओ सदर अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर कुंवर प्रभात सिंह, थानाध्यक्ष भीरा अजय कुमार यादव व थानाध्यक्ष निघासन रामकुमार की सक्रियता आम लोगों की चर्चा में तो है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता और अवैध कमाई में उनकेमशगूल होने के चलते सर्राफा व्यापारियों से दिनदहाड़े हो रही लूट, सट्टा कारोबारियों केधंधे, प्रतिबंधित पशुओं केमांस की तस्करी, पुलिस अभिरक्षा से बंदियों केफरार हो जाने की घटनाएं परेशानी का सबब बनी हुई हैं.

अवैध हथियारों केधंधे से लोग परेशान

जिले में बढ़ते अपराध केपीछे अवैध असलहों केधंधे की मुख्य भूमिका है. नाजायज असलहों से ही जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है. पुलिस ने पिछले दिनों प्रमोद कुमार पुत्र हरिनंदन निवासी ग्राम रायपुर बुजुर्ग थाना नीमगांव और जाबिर पुत्र वासिद खां निवासी ग्राम सेहरूआ थाना नीमगांव को गिरफ्तार कर हथियार तस्करों के गिरोह का पता लगाया और इनकेकब्जे से शस्त्र निर्माण फैक्टरी की मुहर लगे 315

बोर व 12 बोर के14 तमंचे, एक रायफल व अन्य उपकरण बरामद किए. नेपाल के रास्ते चीनी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हथियारों की भी देश में खूब आमद हो रही है. इसकेलिए खीरी जैसे सीमाई इलाकों को ही चुना और अड्डा बनाया जा रहा है.

सट्टा कारोबारियों केआगे पुलिस बौनी

कोतवाली सदर सहित जिले केलगभग सभी छोटे-बड़े कस्बों में पुलिस की मिलीभगत से सट्टे का कारोबार बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है. इसके पीछे सीधे तौर खाकी और खादी का संरक्षण है. अभी पिछले ही दिनों मोहल्ला अर्जुन पुरवा में संचालित हो रहे सट्टे केकारोबार का पर्दाफाश किया गया, जिसमें आधा दर्जन युवकों सहित भारी मात्रा में नंबर लिखी पर्चियां, आधा दर्जन मोबाइल और 67 हजार रुपये बरामद किए गए, लेकिन यह केवल ऊंट केमुंह में जीरा है. पुलिस के अधिकारी ही बताते हैं कि जिले केसभी मुख्य स्थानों पर सट्टे का धंधा जड़ जमाए बैठा है. सट्टा कारोबार से जुड़े मुखिया खुद ही काफी रसूखदार हैं और इसकेअलावा उन्हें कुछ सफेदपोशों का संरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन पुलिस इन लोगों पर हाथ डालने से हिचकती है.

शिकंजे में अंतरराष्ट्रीय मूर्ति चोरों का गिरोह

जनपद में लंबे समय से सक्रिय अंतरराष्ट्रीय मूर्ति चोरों केगिरोह केखिलाफ कारगर कार्रवाई से लोगों को राहत है. अति प्राचीन अष्ट धातु की भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ तस्कर केपकड़े जाने से इस मामले में पुलिस को पहली कामयाबी मिली. बरामद मूर्ति का वजन लगभग 10 किलोग्राम है जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई गई. इसी क्रम में 24 सितंबर को अष्ट धातु से बनी लक्ष्मण जी की मूर्ति बरामद की गई जिसका वजन करीब 35 किलो है और उसकी कीमत करीब 20 करोड़ बताई गई. पकड़े गए मूर्तिचोर सुआराम और रघुनाथ से इस गिरोह से जुड़े कई सफेदपोशों का भी पता चला है. लक्ष्मण की मूर्ति पिसावां थाने केबरगांवा गांव से चोरी हुई थी. यहां केऐतिहासिक मंदिर से राम और सीता की अष्टधातु से निर्मित बहुमूल्य मूर्तियां चुराई गई थीं जिसका आज तक पता नहीं चला. इसी तरह सोने की ईंट दिखाकर लूटने वाले गिरोहों को भी धरा जा रहा है. ■

गरीबों के स्वास्थ्य की फिक्र करता एक अस्पताल

हरिशंकर वर्मा

प्र देश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही केचलते जनपदों केसरकारी चिकित्सालयों में मरीजों केसाथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं आम हो गई हैं. गरीबों केलिए सरकारी चिकित्सालय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं. मरीजों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या को लेकर सरकारी अस्पताल प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक गम्भीर नहीं दिख रही है. ऐसे में मजबूर गरीब मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं. लखीमपुर खीरी जनपद में वेन्टीलेटर एवं डायलिसिस जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण मीरपुर ऐरा रोड स्थित मेहता मिलेनियम अस्पताल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता रहता है. अस्पताल के संचालक डॉ. प्रदीप मेहता ने बताया कि बीते दिनों अस्पताल में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जिले केदूरदराज से आए लगभग साढ़े तीन सौ मरीजों का परीक्षण व उपचार लखनऊ से आए न्यूरो सर्जन डॉ. सुनील बिसेन, दूरबीन सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. राहुल सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनमीत सिंह अरोड़ा, दंत एवं जबड़ा रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराग यादव, एण्डो क्राइन सर्जन डॉ. गीतिका नंदा द्वारा किया गया. जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रूबी मेहता ने विशेष योगदान दिया. जनपद के अग्रणी व्यापारी और समाजसेवी प्रेम शंकर अग्रवाल ने शिविर में पहुंचकर सम्मानित चिकित्सकों का माल्यार्पण कर धन्यवाद अर्पित किया. ■

स्कीइंग का सपना होगा साकार

रेनु शर्मा

रु द्रप्रयाग जनपद का खूबसूरत हिल स्टेशन चोपतादुग लबिट्ठा की बर्फीली ढलानों में स्कीइंग के रोमांच का सपना हरीश सरकार के प्रयास से साकार होने जा रहा है. जिले का पर्यटन विभाग और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी संयुक्त रूप से चोपता में स्कीइंग कराएगा. पहले चरण में स्थानीय युवाओं को स्कीइंग का ट्रॉयल दिया जाएगा. चार फीट बर्फ जमने के बाद जनवरी, फरवरी माह के मध्य में ही दस दिन का विंटर कोर्स संचालित होंगा. चोपता में उम्मीद के मुताबिक बर्फ गिरी तो सफेद चादर से ढ़की स्लोपों(ढलानों) पर बहुप्रतिक्षित स्कीइंग हो सकेगी. पर्यटन विभाग विंटर कोर्स के रूप में स्कीइंग कराएगा. पर्यटन विभाग इस कोर्स को ट्रॉयल के रूप में चला रहा है. चोपतादुग लबिट्ठा की ढ़लाने स्कीइंग के उपयुक्त साबित होती हैं, तो हर वर्ष यहां पर स्कीइंग हो सकेगी. स्थानीय युवाओं को दस दिनी स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस काम में पर्यटन विभाग को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का पूरा सहयोग देगा और दोनों मिलकर स्कीइंग प्रशिक्षण देंगे. अभी तक पर्यटन विभाग संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के कारण स्कीइंग कोर्स संचालित नहीं कर पा रहा था. विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या स्कीइंग सेट की थी. चोपतादुग लबिट्ठा की ढलानों में स्कीइंग का ट्रॉयल सफल हो जाता है, तो यह पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना पाएगा. देवभूमि की धरती पर चोपता स्वर्ग का अहसास कराता है. चोपता-दुगलबिट्ठा हिल स्टेशन एक ऐसी खूबसूरत जगह है, जहां पहुंचकर मन को शांति मिलती है. यहां की सुंदरता किसी फ्रेम में कैद तस्वीर जैसी लगती है. मनोरम दृश्यों वाला यह पर्यटन स्थल भीड़-भाड़ से दूर शांति और सुकून दिलाने वाला टूरिस्ट प्लेस है. समुद्र तल से 12 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित चोपता घने जंगलों से घिरा है. यहां से भगवान शिव के हृदयभाग तुंगनाथ और चन्द्रशिला के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है. इस खूबसूरत स्थल से हिमालय की नंदादेवी, त्रिशूल एवं चौखंबा पर्वत श्रृंखला के विहंगम दृश्य दिखते हैं. जब सूर्य की किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं, तो सुबह काफी मनोरम लगती है. शीतकाल में बर्फबारी के बाद यहां की सुंदरता पर चार चांद लग जाते हैं. इसका लुत्फ उठाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं. सरकार ने सुंदरतम पर्यटक स्थलों में हरीश सरकार ने विंटर टूरिज्म चलाने की योजना बनाई है. इसके लिए पर्यटन विभाग से प्रस्ताव मांगे गए हैं. इसके साथ ही विभाग राफ्टिंग का भी कार्य योजना बना रहा है. जिला साहसिक खेल अधिकारी सीमा नौटियाल का मानना है कि ट्रैकिंग के लिए विभाग ने देवरियाताल, चोपता, चन्द्रशिला, कार्तिक स्वामी, कालीशिला, कालीमठ, गुप्तकाशी आदि स्थलों को चिन्हित किया गया है. इसके अलावा गौचर से धारी देवी तक राफ्टिंग भी संचालित की जाएगी. शासन से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. ■

बद्रीनाथ पूजा स्थल को लेकर घमासान

राजकुमार शर्मा

उ त्तराखंड में ब्रदीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर बवाल मचा हुआ है. जोशीमठ के नागरिक जहां नरसिंह मंदिर को शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर खुलकर आगे आ गए हैं, वहीं पांडुकेश्वर के लोगों ने भी मोर्चा खोल लिया है. इससे चार धामयात्रा के शीतकाल में शुरू होने से पूर्व ही इस यात्रा को लेकर शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई है. हरीश सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने का बीड़ा क्या उठाया कि जोशीमठ में इस यात्रा को लेकर घमासान शुरू हो गया है. इस शीतकालीन यात्रा को लेकर यात्रियों की संख्या में किस तरह का इजाफा होता है यह तो भविष्य के गर्भ में है, इससे जोशीमठ तथा पांडुकेश्वर क्षेत्र के लोगों में तनातनी शुरू हो गई है. इस बार भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर नया विवाद सामने आया है. प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में यह शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है. दैवीय आपदा के चलते चारधामों में तीर्थयात्रियों की आमद न होने के चलते अब सरकार ने शीतकाल में शीतकालीन तीर्थ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है.

जोशीमठ की देव पुजाई समिति ने तो बकायदा शीतकालीन पूजा स्थल को नरसिंह मंदिर जोशीमठ को बताकर यह भी चेतावनी दे डाली है कि यदि भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ को मान्यता नहीं मिली तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा. इसी के चलते मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जोशीमठ वासियों ने एसडीएम को सौंप दिया है. शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर इस तरह की प्रतिध्वनि सामने आने से पांडुकेश्वर क्षेत्र के लोग भी भड़क उठे हैं. बद्रीनाथ मंदिर के हकहकूक धारी समाज से जुड़े पांडुकेश्वर निवासी जयदीप मेहता, उत्तम मेहता, जगदीश पंवार, चंद्र सिंह पंवार, राधाकृष्ण भट्ट तथा कौशल सिंह भंडारी भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर को लेकर खुले तौर पर आगे आ गए हैं. उनका कहना है कि शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ से भगवान कुबेर तथा उद्धव की उत्सव मूर्तियां योगध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में पूजित होती हैं. यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही हैं. उनका कहना है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य की गद्दी पहुंचती है. इसलिए इस आधार पर पांडुकेश्वर के तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता. इनका कहना है कि जब भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह कुबेर और उद्धव की मूर्तियां पांडुकेश्वर में ही शीतकाल में पूजित होती हैं और भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन पूजा स्थल के रूप में पांडुकेश्वर को ही मान्यता मिली है. इसलिए इस पर अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए. सदियों से यह परंपरा चली आ रही है. चार धाम शीतकालीन यात्रा के बहाने इस तरह की परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. जोशीमठ के लोग पहले ही कह चुके हैं कि नरसिंह मंदिर में ही शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की शीतकाल की पूजाएं संपादित होती हैं. पहले भी 28 वर्षों तक जोशीमठ में ही यह पूजा संचालित हुई है. जोशीमठ में शीतकालीन पूजा का समर्थन नरसिंह मन्दिर के पुजारी लक्ष्मीप्रसाद डिमरी जी ने भी किया है. इस तरह के दोनों पक्षों के तर्क से धर्म क्षेत्र में दखल रखने वाले लोग भी फिलहाल असमंजस में पड़ गए हैं. दोनों पक्षों के बीच अब इस शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर उठे विवाद से प्रशासन के साथ ही सरकार भी सकते में आ गई है. धार्मिक मसला होने के कारण सरकारी पक्ष इस मामले पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है. यदि इस मामले में जल्द धर्म क्षेत्र में दखल रखने वाले लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया तो शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले यह मामला दोनों ओर से तनातनी का रूप ले सकता है. अब देखना यह है कि दोनों पक्ष इस मसले पर किस तरह के कदमों के साथ आगे बढते हैं. अगर ऐसा ही रहा तो शीतकालीन पूजा स्थल को लेकर सरकार भी हाथ खड़ा कर सकती है. ■

जागेश्वर धाम विश्व हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हो सकता है

भा रतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जागेश्वर धाम को विश्व हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है. इसके लिए एएसआई पहले जागेश्वर मंदिर समूह को संभावित सूची में शामिल करने के लिए आवेदन करेगी. इसके बाद यूनेस्को की विशेषज्ञ टीम इस बारे में निर्णय लेगी. स्थल की महत्वता एवं प्राकृतिक दिव्यता के कारण पूरी सम्भावना है कि भविष्य में जागेश्वर मंदिर समूह को विश्व धरोहरों में शामिल कर लिया जाएगा. जागेश्वरधाम राज्य की पहली सांस्कृतिक धरोहर होगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों का मानना है कि जागेश्वर मंदिर समूह में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की सभी खूबियां हैं, इसलिए एएसआई ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का फैसला किया है. उत्तराखंड के अधीक्षक पुरातत्वविद् अतुल भार्गव ने बताया कि इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक राकेश तिवारी काफी गंभीर हैं. उनका मानना है कि किसी भी स्मारक को विश्व धरोहर के तौर पर शामिल करने से पहले विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल होना जरूरी है. इसलिए पहले संभावित सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित फॉरमेट में आवेदन किया जाएगा. यह स्मारक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके सभी तथ्यों का विवरण दिया जाएगा. इसके बाद यूनेस्को के अंतर्गत इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनोमेंट्स एंड साइट्स (ईकोमोस) अपने विशेषज्ञों को जागेश्वर भेजेगी और उनकी रिपोर्ट के बाद इस बारे में फैसला होगा. जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में सातवीं से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य हुआ है. कत्यूरी शासक खुद को परम महेश्वर कहते थे और वह खुद को शिव के परम भक्त मानते थे. यह भी मान्यता है कि आदि जगद्गुरू शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया और इस मंदिर की मान्यता को पुर्नस्थापित किया. जागेश्वर मंदिर नागर शैली का है. यहां स्थापित मंदिरों की विशेषता यह है कि इनके शिखर में लकड़ी का बिजौरा(छत्र) बना है. जागनाथ मंदिर में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है. जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत शिव, महामृत्युंजय, लकुलीश, केदारेश्वर, बालेश्वर, पुस्टिदेवी समेत छोटे बड़े 124 मंदिर हैं. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

सरकार के लिए खतरा बने विधायक खुद ही खतरे में

उ त्तराखंड की हरीश सरकार के लिए खतरा पैदा करने से पहले ही बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी स्वयं ही खतरे में आ गए. वह एक स्टिंग ऑपरेशन में बूरी तरह फंस चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी ने विधायक अंसारी का इस्तीफा मांगा, साथ ही नैनिताल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग सहित नियम 310 के तहत स्थगन प्रस्ताव रखा, बाद में नियम 58 पर हुई चर्चा कराने पर सदन में अड़े रही. सदन के स्पीकर गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विधानसभा से मामले की जांच कराने के दिए निर्देश दे कर मामले को ठंढे बस्ते में डाल दिया. एक दिन में विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को चार बार स्थगित करना पड़ा, जो इस बात का इशारा करता है कि राज्य में सब ठीक नहीं चल रहा है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजभवन जाकर राज्यपाल से पूरे प्रकरण का ब्योरा देने के साथ यह साफ कर दिया की उनकी सरकार इन विवादों से अछूती है, उस पर किसी तरह का खतरा नही है. इस मामले में मंगलौर से बसपा विधायक व आवास विकास परिषद के अध्यक्ष सरवत करीम अंसारी से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण ने इस प्रकार तूल पकड़ लिया कि पूरी सरकार हिल उठी. विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा ने इसी प्रकरण को लेकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी. विपक्षी विधायक अंसारी के इस्तीफे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से प्रकरण की जांच की मांग पर अड़ा रहा. चार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा से प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए. भाजपा सदस्यों ने एक टीवी चैनल पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के स्टिंग ऑपरेशन का प्रकरण उठाते हुए नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की. नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि बसपा विधायक से जुड़ा प्रकरण काफी गंभीर है. जांच प्रभावित न हो इसके लिए बसपा विधायक की सदस्यता समाप्त की जाए. अजय भट्ट ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में सरकार का तख्ता पलटने, पिटकुल के प्रबंध निदेशक सहित ऊंचे पदों पर नियुक्ति कराए जाने की बात दिखाई गई है, इससे यह झलकता है कि सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. बसपा विधायक अंसारी ने अपने को बेगुनाह बताते हुए कहा कि कुछ विरोधियों ने मुझे फंसाने की गहरी साजिश की है. मैं मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं. दोषी पाए जाने पर इस्तीफा दे दूंगा. जून 2014 में लिए गए फुटेज को सत्र के दौरान दिखाना संदेहास्पद है. चैनल की बात सत्य है तो इसे उस व्यक्ति को भी दिखाना चाहिए जिससे कथित तौर पर पैसे लिए गए हैं. नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को स्टिंग आपरेशन की सीडी सौंपी. भट्ट ने कहा कि प्रकरण में कितनी सत्यता है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा. सीडी में सरकार का तख्ता पलट, पिटकुल में एमडी व दूसरे ऊंचे पदों पर नियुक्ति से जुड़ी बातें रिकार्ड हैं.

विवादों में बसपा के सभी विधायक

मंगलौर के विधायक सरवत करीम अंसारी के कथित स्टिंग ऑपरेशन के बाद बसपा प्रदेश की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई है, जिसका हर विधायक विवादों के घेरे में है. इस समय प्रदेश विधानसभा में बसपा के तीन विधायक हैं, जिनमें से भगवानपुर के विधायक सुरेंद्र राकेश सरकार में समाज कल्याण व परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. झबरेड़ा के विधायक हरिदास को हाल ही में हरिद्वार विकास प्राधिकरण का दायित्व दिया गया है. सरवत करीम अंसारी को भी हाल में ही हरीश रावत सरकार ने आवास विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है. कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश की तो वह पहले शिक्षक रहे हैं. कुछ समय पहले सूचनाधिकार के एक मामले में यह जानकारी सामने आई थी कि विद्यालय में उनका रिकार्ड ही नहीं है. ■

-राजकुमार शर्मा

छात्रों की कमी के कारण 1800 स्कूल बंद होंगे

उ त्तराखंड राज्य के चौदह वर्ष व्यतीत होने के बाद जमीनी हकीकत ने जिस तरह की तस्वीर पेश की है. इससे यह बात साफ साफ हो गई है कि इस राज्य के शिक्षा, ऊर्जा प्रदेश बनने की सच्चाई केवल हवा हवाई ही है. पहाड़ों से लोगों का पलायन इस कदर हुआ है कि जिस पर विश्वास भी नही होता. पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों की बेहद कम संख्या के होने के कारण प्रदेश की हरीश सरकार ने करीब 1800 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है. इन स्कूलों के बदले में प्रदेश सरकार ब्लॉक मुख्यालयों में आवासीय विद्यालय व बंद होने वाले चार से पांच विद्यालयों के बदले किसी एक मुख्य गांव में एक अन्य स्कूल खोलने की तैयारी में है. जनसंख्या के भारी पलायन के चलते पर्वतीय जिलों के बहुत से स्कूलों में पर्याप्त विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे में बहुत से स्कूलों में तो विद्यार्थियों से ज्यादा शिक्षक हैं, जबकि प्रदेश में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हर एक किलोमीटर पर करीब एक स्कूल है. कुछ स्कूलों में तो केवल एक ही विद्यार्थी पढ़ता है, जबकि दो अध्यापक हैं. इसी समस्या को हल करने के लिए प्रदेश सरकार ने अगले सत्र से पर्वतीय क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित हो रहे इन 1800 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जहां कि 10 से कम विद्यार्थी हैं.

इससे सरकार को इन शिक्षकों का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जो कि ऐसे स्कूलों में तैनात हैं. इससे कम शिक्षकों वाले स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक मुहैया कराने का अवसर मिलेगा. इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विद्यालयों को बंद कर सरकारी धन के अपव्यय को रोकने के साथ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम आरंभ किया है. प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य के 12 जनपदों के 1451 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है. जब की राज्य के निर्माण के समय इसे एक ऊर्जा प्रदेश बनाने का ठिठोरा पीटा गया था इन सरकारी आकड़ों से ही स्वंय सिद्ध होता है कि सरकार की वह घोषणा भी हवा हवाई ही सिद्ध हुई है. इन स्कूलों द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए या तो आवेदन अथवा शुल्क जमा नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन अथवा संयोजन शुल्क जमा करने के बाद इन स्कूलो को बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे. विधानसभा सत्र के दौरान सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बतौर ऊर्जा मंत्री (मुख्यमंत्री) हरीश रावत ने कहा कि ऊधमसिंह नगर के अलावा शेष अन्य 12 जनपदों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 1451 स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा आवेदन एवं संयोजन शुल्क जमा कराए जाने के बाद कनेक्शन दिए जाएंगे. हरीश रावत ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा कम्प्यूटर की शिक्षा ले. जिन स्कूलों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है, उनमें जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के तीन, जागेश्वर के 77, सोमेश्वर के 25, रानीखेत पांच, द्वाराहाट 22 व सल्ट 56 , जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के 70, कर्णप्रयाग और थराली के 150-150 स्कूल शामिल हैं. जनपद पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में 13, पौड़ी में 22, दुगका तीन, यमकेश्वर 55, लैंसडोन 118 व कोटद्वार 68, रुद्रप्रयाग 116, जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में 40 व धारचूला में 36, नैनीताल जनपद के कालीढूंगी विधानसभा क्षेत्र में चार, जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली 24, प्रतापनगर 12, टिहरी छह, देवप्रयाग 89 व धनोल्टी में 19 स्कूलों में बिजली नहीं है. चंपावत जिले के चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 172, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में एक, देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्र चकराता में 15, रायपुर में तीन, उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री विस क्षेत्र में तीन, यमुनोत्री में 16 व पुरोला में 31 तथा बागेश्वर जिले के कपकोट में 13 व बागेश्वर में 14 स्कूल बिजली की सुविधा से वंचित हैं.

अगले सत्र से बंद होने वाले इन स्कूलों की जगह की जाने वाली उपयोग के लिए शिक्षा विभाग को पैनल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. यह पैनल इन स्कूलों की इमारतों के उपयोग की व्यवस्था और ब्लॉक मुख्यालयों में बनने वाले आवासीय विद्यालयों के बारे में फैसला लेगा. पैनल विचार करेगा कि नए बनने वाले आवासीय स्कूलों को राजीव गांधी आवासीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाए या अन्य तरीके से-मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री. ■

-राजकुमार शर्मा